राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 30

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, शनिवार, 10 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14



कोपा अमेरिका के खिताबी मुकाबले में भिड़ेंगी मेसी की अर्जेंटीना और नेमार की ब्राजील

>> 12

जागरण विशेष

नंदियों के आंगन में बसा दिया सरोकारों का संसार



फतेहाबाद : हरियाणा के टोहाना कस्बे में स्थित शिव नंदी गोशाला दूसरों के लिए मिसाल है। बेसहारा गोवंश को आश्रय देने के साथ ही यह गरीबी उन्मूलन, स्वस्थ समाज जैसे सरोकारों को आगे बढ़ा रही है। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राष्ट्रीय राजधानी ▶ पृष्ठ 2

टोक्यो में स्वर्ण जीतने वाले को तीन करोड़ देगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली : टोक्यो ओलंपिक, 2020 से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना बनाई है। इसमें दिल्ली के खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक जीतने पर तीन करोड़, रजत पदक जीतने पर दो करोड़ एवं कांस्य पदक जीतने पर एक करोड़ रुपये की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। पदक विजेता खिलाड़ियों के कोच को भी 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 6

शताब्दी वर्ष तक गांव-गांव लगेंगी संघ की शाखाएं

चित्रकूट : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को 2025 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। संघ के शीर्ष नेतृत्व की कोशिश है कि शताब्दी वर्ष से पहले ही शाखाओं को ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचा दिया जाए। अभी न्याय पंचायत स्तर तक संचालित हो रहीं शाखाओं में प्रमुखता से सनातनियों का ही जुड़ाव है। अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में कार्ययोजना पर विमर्श के बाद इसे अमल में लाने के जतन भी शुरू हो जाएंगे।

कोरोना से जंग ▶ पृष्ठ 6

दूसरी लहर अभी गई नहीं, 66 जिलों में संक्रमण दर 10 फीसद

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने एक बार फिर कोरोना महामारी को लेकर लोगों को सावधान किया है। सरकार का कहना है कि अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। देश के 66 जिलों में कोरोना संक्रमण दर अभी भी 10 फीसद से ज्यादा बनी हुई है। महाराष्ट्र और केरल में अभी भी ज्यादा मामले मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते में देश में सामने आए कुल संक्रमितों में से 53 फीसद इन्हीं दोनों राज्यों से थे।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

अफगानिस्तान के 85 फीसद हिस्से पर तालिबान का कब्जा

काबुल : अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की हो रही वापसी के बीच आतंकी संगठन तालिबान तेजी से इस देश पर काबिज होते जा रहा है। उसने युद्ध प्रभावित इस देश के 85 फीसद से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यह दावा रूस की राजधानी मास्को पहुंचे तालिबान के प्रतिनिधिमंडल ने किया है। हालांकि अफगानिस्तान की सरकार ने तालिबान की इस बात का खंडन किया है। साथ ही कहा कि यह सिर्फ दुष्प्रचार है।

समान नागरिक संहिता वक्त की जरूरत

कानून की पैरवी ▶ दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार उठाए आवश्यक कदम, सुप्रीम कोर्ट भी बता चुका है जरूरी

कहा-आधुनिक भारतीय समाज में खत्म हो रहे धर्म, समुदाय व जाति के अवरोध

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली

- ऐसे में युवाओं को विभिन्न कानूनी मुद्दों से संघर्ष करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए
- आदेश की एक प्रति केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के सचिव को भी भेजने के निर्देश

कानून के सामने सब समान और सबके लिए एक समान कानून जीवंत लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है। विवाह, तलाक, संपत्ति के बंटवारे आदि के संबंध में वैकल्पिक व्यवस्थाओं की मौजूदगी न सिर्फ देश के विधिक व न्यायिक ढांचे के लिए लंबे वक्त से बड़ी चुनौती बनी है, बल्कि ये संविधान के कई महत्वपूर्ण प्रविधानों को तत्वतः लागू करने में भी बाधक हैं। इन टिप्पणियों के साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने देशभर के विभिन्न मंचों से उठ रही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की वकालत की। साथ ही, केंद्र सरकार को इस संबंध में जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया।

तलाक की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने कहा, भारतीय समाज समरूप हो रहा है, जाति व धर्म की दूरियां मिट रही हैं। विभिन्न समुदायों, जनजातियों, जातियों या धर्मों के लोगों को विवाह व तलाक के लिए कानूनी अड़चनों से जूझने के लिए मजबूर होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पीठ ने निर्देश दिया कि आदेश की प्रति केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के सचिव को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाए।

पत्नी की दलील खारिज: याचिकाकर्ता सतप्रकाश मीणा ने अलका मीणा से 24 जून, 2012 को हिंदू पद्धति से विवाह किया था। याचिकाकर्ता ने पत्नी से तलाक की याचिका दायर की थी। वहीं, पत्नी ने याचिका को खारिज करने के लिए आवेदन दायर करते हुए दलील दी कि उन पर हिंदू विवाह अधिनियम के प्रविधान लागू नहीं होते, क्योंकि वे राजस्थान के अनुसूचित जनजाति मीणा के सदस्य हैं। हालांकि, पीठ ने अलका की दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सभी के लिए समान संहिता की जरूरत है, जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि जैसे पहलुओं के संबंध में समान सिद्धांतों को लागू करने में सक्षम हो।

पीठ ने कहा कि दस्तावेजों से साफ है कि दोनों पक्षों की शादी हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी और वे इसका पालन करते हैं। पीठ ने कहा कि हालांकि, हिंदू की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर जनजातियों के सदस्यों का हिंदूकरण किया जाता है तो उन पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होगा। इतना ही नहीं, अदालत के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य नहीं रखा गया, जो दर्शाता हो कि मीणा समुदाय के पास इन मुद्दों से निपटने के लिए उचित प्रक्रियाओं के साथ एक विशेष न्यायालय है। पीठ ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए हिंदू विवाह अधिनियम-1955 के उपबंध 13-1 (ए) के तहत योग्यता के आधार पर छह सप्ताह में मामले में फैसला देने को कहा।

जनमत मुद्दा

क्या आप मानते हैं कि समान नागरिक संहिता का निर्माण जल्द किया जाना चाहिए?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं।



महज उम्मीद बनकर न रह जाए यूसीसी की जरूरत: वर्ष 1985 के शाहबानो केस सहित सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा, शीर्ष अदालत ने भी समय-समय पर अनुच्छेद-44 के तहत परिकल्पित यूसीसी की जरूरत को दोहराया है। ऐसे में राज्य की तरफ से अपने नागरिकों के लिए यूसीसी का प्रविधान सिर्फ एक उम्मीद बनकर नहीं रहना चाहिए। पीठ ने निराशा जताई कि तीन दशक बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया है।

शाहबानो प्रकरण: शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधारा वाले कानूनों के प्रति असमान निष्ठा को हटाकर राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य की पूर्ति करने में मदद करेगी। यह भी देखा गया था कि राज्य पर देश के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित रखने का कर्तव्य है।

संविधान का अनुच्छेद-44

संविधान के भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद-44 राज्य को उचित समय आने पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद-44 का उद्देश्य कमजोर वर्गों से भेदभाव की समस्या को खत्म करके देशभर में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच तालमेल बढ़ाना है।

डाटा संरक्षण विधेयक आने तक निजता नीति स्वीकार करने को नहीं करेंगे मजबूर : वाट्सएप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ दिल्ली हाई कोर्ट में कहा, नीति नहीं स्वीकारने वाले यूजर्स की सेवाओं को नहीं किया जाएगा बाधित

नई निजता नीति को लेकर वाट्सएप ने अपना अड़ियल रवैया छोड़कर दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि अगर संसद अनुमति देगी तो वह इसे लागू करेंगे और जब तक डाटा संरक्षण विधेयक लागू नहीं होता तब तक उपभोक्ताओं को नई नीति स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष वाट्सएप की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने यह भी कहा कि वाट्सएप ने इसे स्वतः ही रोकने का फैसला किया है और नीति को स्वीकार करने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिन लोगों ने अब तक नीति को स्वीकार नहीं किया है, उनकी सेवाओं को सीमित या बाधित नहीं किया जाएगा। हालांकि, वाट्सएप अभी भी उपभोक्ताओं को अपडेट दिखाना जारी रखेगा। इस पर पीठ ने सवाल उठाते हुए कहा कि नीति लागू करने पर भले ही आपने रोक लगा दी है, लेकिन नीति अब भी मौजूद रहेगी। आप लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीति आपके साथ है और आप कभी भी इसे लागू कर सकते हैं। जवाब में साल्वे ने कहा कि डाटा संरक्षण विधेयक लागू होने तक यह फैसला बरकरार रहेगा। साल्वे ने पीठ से अनुरोध किया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) की तरफ से जांच के संबंध में भेजी गई प्रश्नावली का जवाब देने के लिए वाट्सएप को जुलाई अंत तक का समय दिया जाए। वहीं, विधेयक की जांच करने वाली संसद की संयुक्त समिति को रिपोर्ट देने के लिए मानसून सत्र तक का वक्त दिया गया है।

फेसबुक के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के बावजूद सीसीआइ ने जांच का आदेश दिया है, जो उचित नहीं है। सीसीआइ की तरफ से पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि जब तक गोपनीयता नीति मौजूद रहेगी, इसके निहितार्थ बने रहेंगे। फेसबुक और वाट्सएप ने नई निजता नीति के मामले में सीसीआइ द्वारा दी गई जांच के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार करने के एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी है। 22 अप्रैल को एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि फेसबुक और वाट्सएप की याचिकाओं में कोई मेरिट दिखाई नहीं देती।

तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां तेज

आक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- दूसरी लहर जैसी न हो किल्लत इसके लिए उपायों को सुनिश्चित करने का दिया निर्देश
- शीघ्र शुरू किए जाएंगे 1500 से ज्यादा आक्सीजन प्लांट, इनकी आनलाइन मानिटरिंग भी होगी

देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है। दूसरी लहर ने भारी तबाही मचाई है, इससे सबक लेते हुए सरकार ने संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। दूसरी लहर में सबसे ज्यादा आक्सीजन का संकट देखने को मिला था, इसलिए इस जीवन रक्षक गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। देश भर में 1500 आक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर नजर रख रहे हैं। शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने इसकी प्रगति की समीक्षा की और जल्द से जल्द इन प्लांट को चालू करने निर्देश दिया।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आक्सीजन प्लांट की आनलाइन मानिटरिंग की तकनीक विकसित की गई है और उसका परीक्षण भी कर लिया गया है। इससे अस्पतालों में लगने वाले प्लांट पर एक केंद्रीय कंट्रोल रूम से नजर रखी जा सकेगी। प्रधानमंत्री ने सभी ऑक्सीजन प्लांट को इस तकनीक से जोड़ने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि देश के विभिन्न अस्पतालों में आक्सीजन प्लांट लगाने का काम चल रहा है। कुल 1500 प्लांट लगाए जा रहे हैं। हालांकि, अभी तक बहुत कम प्लांट ही लग पाए हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, केवल पीएम-केयर्स फंड से लगने वाले प्लांट से चार लाख मरीजों को आक्सीजन मुहैया कराई जा सकेगी।

ज्ञात हो, कोरोना की पहली लहर के दौरान भी पीएम-केयर फंड से अस्पतालों में आक्सीजन प्लांट लगाने के लिए धन दिया गया था। दूसरी लहर के आने के बाद पता चला कि अधिकतर प्लांट लगे ही नहीं थे। पीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। बता दें कि एक दिन पहले ही कैबिनेट मे फैसला लिया गया था कि 1050 आक्सीजन स्टोरेज टैंक भी तैयार होंगे। हर जिले में कम से कम एक ऐसे टैंक होंगे।



नई दिल्ली में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के मद्देनजर आक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। प्रेट्र

8000 युवा प्रशिक्षित किए जाएंगे : समीक्षा बैठक में आक्सीजन प्लांट को चलाने के लिए प्रशिक्षित लोगों की कमी की भी बात उठी। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि पूरे देश में इसके लिए आठ हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने की तैयारी है। प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल तैयार कर लिया गया है और राज्यों के साथ संपर्क कर युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

जिला स्तर पर युवाओं का चयन करने का निर्देश : प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रशिक्षण के लिए युवाओं का चुनाव जिला स्तर पर किया जाए, ताकि हर जिले में ऐसे प्लांट को चलाने व रखरखाव के लिए प्रशिक्षित युवा उपलब्ध हो सकें।

छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप, राजद्रोह का केस दर्ज

नईदुनिया, रायपुर

भ्रष्टाचार के आरोप में गत दिनों निलंबित किए गए छत्तीसगढ़ के चर्चित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) जीपी सिंह के खिलाफ रायपुर में राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। उन पर राज्य सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने और उसको गिराने की साजिश का आरोप लगा है। उधर, गुरुवार देर रात केस दर्ज होते ही जीपी सिंह हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गए। उनकी ओर से पेश याचिका में मामले की जांच सीबीआइ से कराने का आग्रह किया गया है। साथ ही जांच होने तक एसीबी-ईओडब्ल्यू व पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। वहीं, जीपी सिंह भूमिगत हो गए हैं।

ज्ञात हो, आय से अधिक संपत्ति के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की टीम ने सिंह के 15 ठिकानों पर गत दिनों छापे मारे थे। इस दौरान मिली डायरी और अन्य दस्तावेज के आधार पर उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।



छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी जीपी सिंह। नईदुनिया आर्काइव

धार्मिक उन्माद फैलाने और विधायकों की संदिग्ध रिपोर्ट तैयार करने का भी आरोप, जीपी सिंह पहुंचे हाई कोर्ट, हुए भूमिगत

एसीबी व ईओडब्ल्यू की जानकारी के आधार पर हुई कार्रवाई : भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, एसीबी व ईओडब्ल्यू को मिली जानकारी के आधार पर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसीबी ने थाने को दी शिकायत में कहा है कि सिंह के घर से मिले कागजात से पता चला है कि कई विधायकों की गोपनीय रिपोर्ट तैयार कराई गई है। सरकारी योजनाओं व धार्मिक मुद्दों पर भड़काऊ भाषा के साथ गंभीर टिप्पणियां की गई हैं,जिससे सरकार के प्रति असंतोष पैदा किया जा सके।

एसीबी ने चार जुलाई को ही पुलिस को सौंप दिए थे दस्तावेज पेज>>5

एक अगस्त को प्रस्तावित नीट का टलना तय

नई दिल्ली : मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए नीट (नेशनल एलिजबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाई के लिए और समय मिल सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट की एक अगस्त को प्रस्तावित परीक्षा स्थगित करने के संकेत दिए हैं। इस परीक्षा को अब अगस्त के अंतिम हफ्ते में कराने की योजना है। (पेज-3)

52 फीसद को भरोसा, उप्र में फिर जीतेंगे योगी आदित्यनाथ

नई दिल्ली : आइएएनएस-सी वोटर के एक सर्वे के मुताबिक 52 फीसद को भरोसा है कि उप्र में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं 37 फीसद का मानना है कि ऐसा नहीं होगा। (पेज-4)

परिसीमन से जम्मू-कश्मीर विस में बढ़ेंगी सात सीटें

जम्मू : जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आए परिसीमन आयोग ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर ही होगा। परिसीमन के तहत राज्य विधानसभा में मौजूदा 107 सीटों को 114 करने का प्रस्ताव है। इसमें गुलाम कश्मीर की 24 सीटें शामिल हैं। कुछ क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण भी होना है। (पेज-5)

'नए नियमों के तहत उपद्रवियों से वसूली करे यूपी सरकार'



सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीएए विरोधी आंदोलन में पूर्व के नोटिस पर कार्रवाई नहीं करें, नियमों-ट्रिब्यूनल का विवरण पेश करने को कहा

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुई क्षति की वसूली के लिए जिला प्रशासन द्वारा पहले भेजे गए नोटिस पर कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने हालांकि राज्य सरकार से कहा, वह कानून के मुताबिक और नए नियमों के तहत उपद्रवियों के खिलाफ कदम उठा सकती है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने कहा, पहले भेजे गए नोटिसों के तहत कार्रवाई मत कीजिए। सभी कार्रवाई नए नियमों के अनुरूप की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की ओर से पेश वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने कहा, राज्य सरकार सुनवाई की आखिरी तारीख से आगे बढ़ रही है। इसने ट्रिब्यूनल का गठन किया है और सभी जरूरी नियम बनाए हैं। इस पर पीठ ने प्रसाद को जवाबी हलफनामा दायर कर नियमों और ट्रिब्यूनल का विस्तृत विवरण देने को कहा और मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी।

सुप्रीम कोर्ट परवेज आरिफ टीटू की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। परवेज ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए नोटिस को रद करने की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जिला प्रशासन की ओर से मनमाने ढंग से नोटिस भेजे गए हैं।

मिलीभगत

इन संस्थाओं के शीर्ष पर खुद को मनोनीत या निर्वाचित कराने का है संगठित कार्टेल, कई लाख करोड़ रुपये का संचालन होता है हाथों में, राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, कार्टेल बरकरार रखने में सभी भाईचारे में करते हैं एक-दूसरे की मदद

मुट्ठीभर नेताओं के बीच घूमती रही हैं शीर्ष सहकारी संस्थाएं

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

▶ नवगठित सहकारिता मंत्रालय से बढ़ी अपेक्षाएं, गवर्नेंस के अभाव में डूबी कई संस्थाएं और बैंक

इफको, कृभको, नैफेड, एनसीसीएफ और राज्यों के सहकारी फेडरेशनों समेत सैकड़ों जिला व राज्य स्तरीय सहकारी बैंकों का इतिहास उठाकर देख लें तो साफ हो जाएगा कि किस तरह ये परिवार और कार्टेल के बीच ही घूमते रहे हैं। विभिन्न सहकारी संस्थाओं के शीर्ष पर खुद को मनोनीत अथवा निर्वाचित कराने का संगठित कार्टेल है। इसके लिए परस्पर रोटेशन के आधार पर खुद को मनोनीत कराते रहते हैं। नियमों की खामियां उनके लिए मददगार होती हैं। रोचक बात यह है कि राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो यहां सभी भाईचारे में एकदूसरे की मदद करते हैं ताकि कार्टेल बरकरार रहे। इन संस्थाओं का वित्तीय आकलन करें तो यह कई लाख करोड़ रुपये बैठेगा, जिसका संचालन इन्हीं लोगों के हाथों में रहता है। शायद यही कारण है कि केंद्र में बने नए सहकारिता मंत्रालय ने लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। उन्हें डर सताने लगा है कि उनका कब्जा न खत्म हो जाए।

इस नई कवायद के बाद राजनीति कौन सी करवट लेगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन माना जा रहा है कि इससे देश के सुस्त पड़े सहकारी आंदोलन को नया जीवन मिल सकता है। सहकारी आंदोलन को समर्थन देकर युवाओं को रोजगार और वंचितों को जीवन यापन के साधन मुहैया कराए जा सकते हैं। लेकिन इस दिशा में सरकारी स्तर पर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। सहकारिता क्षेत्र में सुधार की तत्काल जरूरत है, जिसके लिए कई कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। कई सहकारी संस्थानों की हैसियत मल्टीनेशनल कंपनियों से कम नहीं है, लेकिन उन पर काबिज सहकारी नेताओं ने उन्हें अपना साम्राज्य जैसा बना लिया है।

अधिकार बहाली के लिए करनी होगी कोर्ट में विचाराधीन मामले की पैरवी : चर्चित अर्बन सहकारी बैंक घोटाले और अन्य ग्रामीण जिला व राज्य सहकारी बैंकों की खस्ता हालत के जिम्मेदार लोगों की नकेल कसनी होगी, जिससे आम लोगों का विश्वास सहकारी क्षेत्र में बढ़ाया जा सके। नए मंत्रालय को 97वें संविधान संशोधन के तहत मिले अधिकार की बहाली के लिए अदालत में विचाराधीन मामले की पैरवी करनी होगी। इसके तहत राज्यों को माडल कानून लागू कर सहकारी आंदोलन को गति देनी होगी। राज्यों में सहकारी क्षेत्र के चुनाव के लिए अलग निर्वाचन आयोग बनाना होगा। कोआपरेटिव रजिस्ट्रार की नियुक्ति के साथ उसे पर्याप्त अधिकार सौंपने होंगे, ताकि लागू माडल कानून के तहत पूरे सिस्टम की निगरानी की जा सके। नवगठित सहकारिता मंत्रालय से बड़ी अपेक्षाएं हैं।



फाइल/इंटरनेट मीडिया

सरकारी निगरानी नहीं होने से पारदर्शिता का अभाव पेज>>3



This PDF was originally uploaded To The English Newspaper L-- Banna SA (https://t.me/English_Newspaper_L_Banna)one else Backup chennal @NEWS_Backup_L_Banna

48 घंटे के अंदर जल आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष व सत्येंद्र जैन के निवास का पानी कनेक्शन काट देंगे। यह चेतावनी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दी है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 10 जुलाई, 2021

दुकानदार कैसे बांटें अनाज, जब हो गया खराब!

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

- खाद्य आपूर्ति विभाग ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना का बचा अनाज बांटने का निकाला सर्कुलर
- इसी माह 68,715 अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों को किया जाना है वितरण, लेकिन काफी दालों और चने में लग चुका घुन



गोदाम में अनाज की बर्बादी। फाइल फोटो

पीएमजीकेएवाइ व एएनबी योजना का सारा अनाज खराब नहीं हुआ है। गोदामों में रखी दाल और चना ठीक है, फिर भी जो अनाज खराब होगा, उसे न बांटकर सही अनाज का वितरण ही किया जाएगा।
– देशराज, सहायक आयुक्त (वितरण), खाद्य आपूर्ति विभाग, दिल्ली सरकार

एएनबी योजना का सारा अनाज राशन दुकानदारों के पास ही पड़ा हुआ है और काफी हद तक खराब हो चुका है। चने और दालों में घुन भी लगा हुआ है, काफी मात्रा में तो उसका आटा बन गया है। इसलिए इसे बांटना जोखिम भरा हो सकता है।
–शिव कुमार गर्ग, अध्यक्ष, दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ

गरीबों और प्रवासी कामगारों को वितरित किया जाने वाला अनाज बड़ी मात्रा में सड़ने के मामले सामने आने के बीच दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अब बचा हुआ सारा अनाज बांटने का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से सर्कुलर जारी कर राशन दुकानदारों को इसी माह 68 हजार से अधिक अंत्योदय अन्न योजना (एएपी) कार्ड धारकों को यह अनाज बांटने का निर्देश दिया है। इस अनाज में दालों और चने का वितरण किया जाएगा। दूसरी तरफ राशन दुकानदारों का कहना है जो अनाज बांटने के लिए कहा जा रहा है, उसमें से काफी खराब हो चुका है। ऐसे में इसको खाने से अगर किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सहायक आयुक्त (वितरण) देशराज की तरफ से जारी सर्कुलर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाइ)- एक व दो और आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) योजना के तहत राशन की दुकानों पर वितरित दाल व चने के आवंटन का आदेश दिया गया है। पीएमजीकेएवाइ व एएनबी के तहत राशन की दुकानों पर ही नहीं, बल्कि दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन (डीएससीएससी) के गोदामों में पडी हुई दालों व चने का आवंटन भी जुलाई माह में ही 68,715 अंत्योदय कार्ड धारकों को किया जाएगा। प्रत्येक अंत्योदय कार्ड धारक को चार किलोग्राम प्रति कार्ड के हिसाब से चना या दाल का वितरण किया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक कुल 2,74,860 किलोग्राम दाल और चने का आंवटन किया जाएगा, जिसे राजधानी की 1,295 राशन की दुकानों से बांटा जाएगा। पहले से ही 37,481 किलोग्राम दाल व चना राजधानी की कई राशन की दुकानों पर रखा हुआ है। जबकि, 2,37,379 किलोग्राम चने व दाल का आवंटन और किया जाएगा। इस आदेश के अनुसार डीएससीएससी में उपलब्ध स्टाक 1,71,163 किलोग्राम है जिसे 1,295 राशन की दुकानों में 132 किलोग्राम की बराबर मात्रा में वितरित करने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली की जनहित याचिका पर सुप्रीम सवाल

वायु प्रदूषण मामला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- दिल्ली सरकार ने पहले से लंबित मामले में अर्जी दाखिल करने की छूट लेते हुए वापस ली याचिका



दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की केंद्र सरकार के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर शुक्रवार को सवाल उठाया। दिल्ली ने पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में स्थित 10 थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन (एफजीडी) तकनीक का उपयोग न होने के आधार पर संचालन बंद करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य ने केंद्र सरकार के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की है, इसे लेकर उनके पास बहुत से सवाल हैं। कोर्ट देखेगा कि इस पर विचार भी किया जा सकता है या नहीं। कोर्ट का नकारात्मक रुख देखते हुए दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के लंबित मामले में अर्जी दाखिल करने की छूट लेते हुए अपनी जनहित याचिका वापस ले ली।

जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि उनके पास पूछने के लिए बहुत से सवाल हैं, अगर उन्होंने सभी सवाल पूछे तो उन्हें नहीं मालूम कि केस किधर जाएगा। बेहतर होगा कि राज्य सरकार लंबित मामले में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल करे। कोर्ट ने दिल्ली से कहा कि अगर केंद्र सरकार ने किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कोई बात कही थी और वह उससे भिन्न काम कर रही है तो राज्य सरकार को उसी मामले में अर्जी दाखिल करनी चाहिए थी। इस पर दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कालिन गोंसाल्विस ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली थर्मल पावर प्लांट से प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट इस याचिका पर नोटिस जारी करके इसे लंबित मामले के साथ सुनवाई के लिए संलग्न कर दे, लेकिन पीठ का नकारात्मक रुख देखते हुए बाद में उन्होंने कहा कि वह याचिका वापस लेते हैं और लंबित मामले में अर्जी दाखिल करेंगे। कोर्ट ने उन्हें इजाजत देते हुए याचिका वापस लिए जाने के कारण खारिज घोषित कर दी।

इससे पहले बहस के दौरान गोंसाल्विस ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 10 थर्मल पावर प्लांटों में एफजीडी तकनीक नहीं लगे होने से वायु प्रदूषण होता है जिससे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। सल्फर डाइआक्साइड और नाइट्रोजन डाइआक्साइड जानलेवा गैसें हैं। यह मुद्दा लोगों की सेहत से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोर्ट से कहा था कि धुएं के संशोधित मानक लागू किए जाएंगे। इस पर जस्टिस सिन्हा ने कहा कि अधिसूचना के मुताबिक ये 2022 से लागू होंगे। गोंसाल्विस ने कहा कि नई अधिसूचना देखिए। प्रदूषण की स्थिति खराब है, मानक जल्द लागू होने चाहिए।

न्यूज गैलरी

दिल्ली- एनसीआर में मानसून आज दे सकता है दस्तक

नई दिल्ली: बारिश के दिनों में दिल्ली-एनसीआर के लोग उमस और तपिश से परेशान हैं। ऐसे में मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए शनिवार को राहत की बारिश हो सकती है। दरअसल, दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दिल्ली में दस्तक देने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को घोषणा की कि अगले 24 घंटे में धीमी गति से बढ़ रहे दक्षिण पश्चिमी मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान के शेष इलाकों में पहुंचने के आसार हैं। इसके बाद अगले पांच से छह दिन राजधानी में हल्की से लेकर मध्यम स्तर तक की बारिश हो सकती है। पिछले 18 सालों में पहली बार मानसून इतनी देरी से पहुंचेगा। (राब्यू)

कोरोना की फर्जी रिपोर्ट : 10 वकीलों के लाइसेंस निलंबित

नई दिल्ली : दिल्ली बार काउंसिल ने कोरोना की फर्जी रिपोर्ट लगाकर आर्थिक मदद के लिए आवेदन करने वाले 10 वकीलों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इस मामले में तीन सदस्यीय विशेष अनुशासन समिति को जांच सौंपी गई है। कोरोना की दूसरी लहर में काफी संख्या में वकील संक्रमण की चपेट में आ गए थे। इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली बार काउंसिल ने 29 अप्रैल को प्रस्ताव पारित किया था कि कोरोना संक्रमित होने वाले वकीलों को 15-15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए आवेदन मांगे गए थे। (जासं)

लाल किला हिंसा मामले में आरोपित को मिली जमानत

नई दिल्ली : गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में तोड़फोड़, हिंसा के आरोपित गुरजोत सिंह को जमानत मिल गई। शुक्रवार को तीस हजारी कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ की अदालत ने अभियान और आरोपित पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपित को जमानत दी। इसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये के इनाम घोषित किया गया था। गुरजोत लाल किले पर हुई हिंसा और तिरंगे के अपमान का आरोपित है। (जासं)

बजाज एलियांज के वाइस प्रेसिडेंट की तलाश तेज

गुरुग्राम: इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी बजाज एलियांज के वाइस प्रेसिडेंट अंकित गोयनका की तलाश में गुरुग्राम पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुग्राम ही नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर पुणे तक उनकी तलाश की जा रही है। इसके लिए अलग-अलग टीम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समाचार लिखे जाने तक उनके बारे में कुछ भी जानकारी सामने नहीं आ पाई थी। डीएलएफ फेज-दो इलाके में परिवार सहित रह रहे अंकित गोयनका कंपनी की ओर से महाराष्ट्र के पुणे में काम देख रहे हैं। वह बुधवार शाम से लापता हैं। (जासं)

टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले को तीन करोड़ देगी दिल्ली सरकार

प्रोत्साहन ▸ रजत पदक जीतने पर दो करोड़ व कांस्य पदक के लिए मिलेंगे एक करोड़ रुपये

सिसोदिया ने कहा, भविष्य के ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार करने को बनेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली



दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उप कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी और अन्य मौजूद लोग। सौजन्य : दिल्ली सरकार

टोक्यो ओलंपिक, 2020 से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना बनाई है। इसमें भाग लेने वाले दिल्ली के खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक जीतने पर तीन करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने पर दो करोड़ रुपये एवं कांस्य पदक जीतने पर एक करोड़ रुपये की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के कोच को भी 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। दिल्ली की ओर से ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों में मनिका बत्रा, दीपक कुमार, अमोज जैकब और सार्थक भांबरी शामिल हैं।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की एक बैठक भी हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी की उपकुलपति कर्णम मल्लेश्वरी भी शामिल थीं। बैठक में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले दिल्ली के एथलीटों का उत्साह बढ़ाने और समर्थन देने के साथ-साथ आने वाले ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने में यूनिवर्सिटी की भूमिका पर भी चर्चा की गई।

डीएसयू प्रदान करेगी विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं : मल्लेश्वरी

मल्लेश्वरी ने कहा कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण की तैयारी के साथ वह बेहतरीन खिलाड़ी बनने का सपना देखने वाले देश के हर छात्र से वादा करती हैं कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उनके कौशलों को निखारने के लिए विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं और उपकरण प्रदान करेगी। उन्हें आगामी ओलंपिक खेलों के लिए तैयार करेगी, ताकि वह ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर देश के लिए मेडल ला सकें।

दिल्ली को 2048 ओलंपिक की मेजवानी के लिए करेंगे तैयार

सिसोदिया ने कहा कि भविष्य के ओलंपियन बनाने के लिए दिल्ली की तैयारी जोरों पर है और हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। यह यूनिवर्सिटी उन खिलाड़ियों को तैयार करने का काम करेगी जो ओलंपिक खेलों में देश के लिए मेडल जीतकर लाएंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करेगी। इस दिशा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी कम्युनिटी स्पोर्ट्स के माध्यम से दिल्ली में स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित करेगी, ताकि दिल्ली के साथ-साथ पूरे देश में स्पोर्ट्स को लेकर माहौल तैयार हो और हम 2048 के ओलंपिक खेलों के लिए मेजबानी का दावा कर सकें।

रैपिड रेल के एक तिहाई से ज्यादा हिस्से के पिलर तैयार



दिल्ली- मेरठ के बीच निर्माणाधीन रीजनल रैपिड रेल कारिडोर के एक तिहाई हिस्से में पिलर बनकर तैयार हो गए हैं। सौजन्य : एनसीआरटीसी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली-मेरठ के बीच बनाए जा रहे देश के पहले रैपिड रेल कारिडोर के एक तिहाई से अधिक हिस्से में पिलर तैयार कर लिए गए हैं। 82 किमी लंबे इस कारिडोर का 70 किमी हिस्सा एलिवेटेड है, जिसमें अभी तक करीब 24 किलोमीटर के हिस्से में पिलर तैयार हो गए हैं। 12 किलोमीटर भूमिगत हिस्से में करीब चार किमी में है। दिल्ली के भूमिगत हिस्से के निर्माण के लिए आनंद विहार में बोरिंग मशीन से टनल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

तैयार हुए 800 से ज्यादा पिलर

एनसीआरटीसी ने एलिवेटेड भाग के निर्माण कार्य के तहत अब तक 800 से ज्यादा पिलर तैयार कर लिए हैं, साथ ही आठ किलोमीटर का आरआरटीएस वायाडक्ट तैयार कर लिया है। वायडक्ट का ज्यादातर भाग प्राथमिकता खंड में साहिबाबाद से दुहाई के बीच तैयार किया गया है। इस पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो गया है। साहिबाबाद और दुहाई के बीच 17 किमी वाले खंड में आरआरटीएस स्टेशन के डिजाइन व आर्किटेक्चर का कार्य पूरा हो गया है।

180 किमी प्रतिघंटे की गति से दौड़ेगी मेक इन इंडिया ट्रेन

रैपिड रेल प्रोजेक्ट के तहत यात्री मेक इन इंडिया के तहत तैयार की जा रही ट्रेन में चलेंगे। इन ट्रेनों की स्पीड 180 किमी प्रति घंटे की होगी। इनके लिए दुहाई डिपो में ट्रेनों के परिचालन व रख-रखाव के लिए स्टेबलिंग व इंस्पेक्शन लाइन और कंट्रोल केंद्र तैयार किया जा रहा है। आरआरटीएस ट्रैक के लिए रेल लाइन भी दुहाई में उतारी जा चुकी है, जिसे बिछाने का कार्य चल रहा है। दुहाई डिपो में आरआरटीएस ट्रेन के स्टेबलिंग लाइन के लिए ओएचई का कार्य भी शुरू हो गया है। साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किमी के खंड को 2023 तक शुरू करने का लक्ष्य है।

दूसरी बीमारियों के इलाज में देरी से गंभीर हो सकती है परेशानी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- कोरोना के कारण ओपीडी में 89.2 फीसद कम हुए मरीज, सर्जरी भी 80.75 फीसद घटी
- अब अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के साथ इलाज के लिए पहुंच रहे हैं मरीज

कोरोना महामारी से दूसरी बीमारियों के इलाज की व्यवस्था चरमरा गई है। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के डाक्टरों द्वारा कोरोना के पहले और कोरोना के बाद की परिस्थितियों पर किए गए तुलनात्मक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि ओपीडी में 89.2 फीसद कम मरीज देखे गए। वहीं सर्जरी भी 80.75 फीसद कम हो गई है। कोरोना मरीजों के दबाव के कारण दूसरी बीमारियों के इलाज की उपेक्षा हुई है। डाक्टर कहते हैं कि अधिक देर तक इलाज व सर्जरी को टालना खतरनाक हो सकता है। अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के साथ मरीज इलाज के लिए अधिक पहुंच रहे हैं।

अपोलो अस्पताल के डाक्टरों ने दो वर्षों में ओपीडी में इलाज कराने वाले पांच लाख 99 हजार 281 मरीजों व अस्पताल में भर्ती 77,956 मरीजों पर अध्ययन किया। जिसमें कोरोना की महामारी शुरू होने से पहले और महामारी के दौरान इलाज कराने वाले मरीज शामिल हैं। इस अध्ययन में पाया गया कि नए व पुराने मरीजों को मिलाकर 57.65 फीसद कम मरीज इलाज के लिए पहुंचे।

अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डा. अनुपम सिब्बल ने कहा कि श्वास रोग विभाग में भर्ती मरीजों की संख्या पहले की तुलना में 314.04 फीसद बढ़ गई। इसका कारण कोरोना है। मोटापा कम करने की सर्जरी 87.5 फीसद, आंखों की बीमारियों की सर्जरी 65.45 फीसद व जनरल सर्जरी 32.28 फीसद कम हुई। वैसे गंभीर मामलों में आपातकालीन सर्जरी कम प्रभावित रही। कोरोना से बचाव के उपायों के साथ लिवर, किडनी प्रत्यारोपण व कैंसर के मरीजों की सर्जरी की गई लेकिन पहले की तुलना में यह भी कम रही। अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. राजू वैश्य ने कहा कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच कोरोना के 3,746 मरीज भर्ती किए गए, जो कुल भर्ती मरीजों का 12.09 फीसद है।

सुपरटेक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया अवमानना का केस

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रियल इस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड के खिलाफ अवमानना केस बंद कर दिया। कंपनी ने सूचित किया कि उसने उप्र के नोएडा स्थित एमरल्ड कोर्ट परियोजना में फ्लैट बुक करने वाले कुछ खरीददारों की धनराशि वापस कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस परियोजना में निर्मित टावरों को गिराने का आदेश दिया था।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने इस बात पर संज्ञान लिया कि सुपरटेक की अपील वर्ष 2014 से लंबित है और निपटारे के लिए मामले की सुनवाई अगले हफ्ते के लिए तय कर दी। मामले में न्यायमित्र नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने कहा, सिर्फ एक सवाल पर फैसला होना बाकी है कि निर्माण के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा दी गई अनुमति वैध है या नहीं। सुपरटेक के वकील ने कहा, अदालत को देखना होगा कि टावरों की 73 मीटर से बढ़ाकर 120 मीटर की गई ऊंचाई वैध है अथवा नहीं। उन्होंने बताया कि अदालत के आदेशों के अनुपालन में कंपनी ने 50 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करा दिए हैं।

तीन तथ्यों पर विकसित होगा 'नया नोएडा'

जागरण संवाददाता, नोएडा

- जीआइएस आधारित डीएनजीआइआर का मास्टर प्लान 10 माह में होगा तैयार
- स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली व नोएडा प्राधिकरण में हुआ अनुबंध



नोएडा सेक्टर-6 स्थित कार्यालय में दादरी नोएडा गाजियाबाद इंवेस्टमेंट रीजन (डीएनजीआइआर) के रूपमें 'नया नोएडा' का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नोएडा प्राधिकरण और स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) नई दिल्ली के बीच अनुबंध हुआ। इस दौरान (दाएं से चौथी) नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी मौजूद रहीं। जागरण

दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएनजीआइआर) के रूप में 'नया नोएडा' विकसित होने जा रहा है। इसके लिए शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण ने अनुबंध कर मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) नई दिल्ली को सौंप दी है। वह 10 माह में प्लान तैयार कर प्राधिकरण को सौंपेगा।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जीआइएस आधारित मास्टर प्लान 2041 को लेकर तीन तथ्यों पर तैयार किया जाएगा। उसमें होने वाले इन्वेस्टमेंट को लेकर इस बात का खयाल रखा जाएगा कि एनसीआर ही नहीं, बल्कि देशभर के तमाम औद्योगिक क्षेत्रों से किस प्रकार अलग सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इससे इन्वेस्टर इस रीजन में आने को मजबूर हो सकेंगे। मार्केटिंग एनालिसिस के जरिये यह पता लगाया जाएगा कि आइटी, फार्मा, फूड (एग्रीकल्चर), केमिकल, ऑटो कंपोनेंट या अन्य किस प्रकार की इंडस्ट्री के जरिये इन्वेस्टर को आकर्षित किया जाए। प्राइवेट फर्म, पब्लिक फर्म व पीपीपी माडल आधारित फर्म, इन्फ्रास्ट्रक्चर को विशेष तौर पर तवज्जो दी जाए अथवा नहीं। फिजिकल ले आउट तैयार करने में यातायात, हरियाली, पानी के सोर्स इत्यादि को समाहित किया जाएगा। साथ ही यहां पर रहने वाले व जमीन देने वाले किसानों को कैसे इन्वेस्टर व डेवलपर के रूप में तैयार कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जाए, इस पर भी जोर रहेगा।

सेक्टर छह स्थित प्राधिकरण कार्यालय पर अनुबंध साइन किया गया। इस मौके पर प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नेहा शर्मा, चीफ टाउन एंड कंट्री प्लान मोहम्मद इंतियाक अहमद, स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) नई दिल्ली के निदेशक पीएसएन राव, डीन अशोक कुमार, कोर्डिनेटर प्रोफेसर आर विश्वास समेत अन्य मौजूद रहे।

मोबाइल टावर से चोरी का मामला

फर्जी तरीके से कोरियर कंपनियों के माध्यम से आयात-निर्यात का मामला, बिना अनुमति, बिना टैक्स और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है उपकरण मंगाने का खेल

दिल्ली के हजार कारोबारी से देश को लग रहा चूना

आशुतोष गुप्ता, गाजियाबाद

मोबाइल टावर से उपकरण चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों से पूछताछ में पता चला था कि दिल्ली में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रानिक कारोबारी व कबाड़ का काम करने वाले अवैध रूप से माल को आयात व निर्यात करते हैं। इससे देश को आर्थिक नुकसान होता है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस व संबंधित विभागों समेत अन्य एजेंसियों को अगवत कराया गया है।
–अमित पाठक, एसएसपी, गाजियाबाद

पुलिस व क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े गए मोबाइल टावर से माडम व नेटवर्क कार्ड चोरी कर चीन भेजने के मामले में गाजियाबाद पुलिस के हाथ अहम जानकारियां लगी हैं। इलेक्ट्रानिक उपकरणों का काम करने वाले दिल्ली के एक हजार से ज्यादा कारोबारी अवैध रूप से चीन से आयात-निर्यात कर देश को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं।

अवैध कारोबार में लिप्त कोरियर कंपनियां भी देश की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ कर रही हैं। कोरियर कंपनी फर्जी तरीके से चीन और भारत के बीच कारोबारियों के माल का आदान-प्रदान करा रही हैं। इन कारोबारियों के पास न तो आयात-निर्यात की अनुमति है और न ही जीएसटी समेत अन्य विभागों में रजिस्ट्रेशन। बावजूद इसके बड़े पैमाने पर आयात-निर्यात हो रहा है। इस तरह से हर माह देश को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यदि मामले की जांच हो तो बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है। एक निर्यात कारोबारी के मुताबिक आयात-निर्यात के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसिल से एक कोड मिलता है। इस कोड के हिसाब से ही माल के आयात-निर्यात की अनुमति होती है।

आयात पर चुकाना होता है 26.85 फीसद टैक्स : आयात-निर्यात का कारोबार करने वाले कारोबारी के मुताबिक देश से दूसरे देशों में निर्यात पर कोई टैक्स नहीं देना होता। निर्यात कर पूर्व में समाप्त किया जा चुका है। आयात पर 26.85 फीसद टैक्स देना होता है। इसमें इलेक्ट्रानिक उपकरणों पर सात फीसद बेसिक कस्टम ड्यूटी, 18 फीसद जीएसटी और 2.69 फीसद ड्यूटी टैक्स शामिल हैं। अवैध कारोबार करने वाले ये लोग टैक्स की चोरी करते हैं।

कोरियर कंपनियों के दफ्तरों से चलता है खेल : जांच में आया है कि आयात-निर्यात का पूरा खेल कोरियर कंपनियों के दफ्तरों से चलता है। कारोबारियों के पास किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस नहीं है। इसके चलते पार्सल पर कारोबारी का नाम-पता अंकित नहीं किया जाता और कोरियर कंपनियां अपने दफ्तर के पते पर माल मंगाती हैं। इसमें किस कारोबारी का माल आया है उसका नाम साइड में अंकित होता है। संबंधित कारोबारी कोरियर कंपनी के दफ्तर से माल उठा लेता है और जो माल चीन भेजना है वह चीन की कोरियर कंपनी के पते पर भेजा जाता है।

गुलफिशा फातिमा की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

जासं, नई दिल्ली : गत वर्ष दिल्ली में हुए दंगे के मामले में गिरफ्तार छात्रा गुलफिशा फातिमा की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने गलत और आधारहीन मानते हुए खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ही पीठ ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण गुमशुदा या अवैध तरीके से हिरासत में रखे गए व्यक्ति को पेश करने की मांग को लेकर दायर की जाती है। पीठ ने कहा कि जो व्यक्ति पहले से न्यायिक हिरासत में है उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकण याचिका नहीं दायर की जा सकती है।

पीठ ने कहा कि अगर फातिमा निचली अदालत की तरफ से न्यायिक प्रक्रिया के तहत दिए गए आदेश से सहमत नहीं हैं तो वह उचित मंच पर अपनी बात रख सकती हैं। फातिमा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए याचिका दायर की थी।

कोरोना नियमों के उल्लंघन पर गफ्फार मार्केट बंद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बाद अब मध्य दिल्ली में भी कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते करोलबाग इलाके के दो बड़े बाजार अगले दो दिन के लिए बंद रहेंगे। शनिवार और रविवार को यह बंदी रहेगी। हालांकि सोमवार को गफ्फार और नाईवाला बाजार की एसोसिएशन के पदाधिकारी खुद बाजार बंद रखते हैं। ऐसे में यह बंदी तीन दिन हो जाएगी। वहीं, जिला प्रशासन पहले भी दुकानदारों को चेतावनी देता रहा है कि वह शारीरिक दूरी के नियम का पालन करे, लेकिन इसके बाद भी बाजार में नियमों की अनदेखी की जा रही थी।

करोलबाग के एसडीएम बलराम मीणा ने बताया कि शनिवार और रविवार को बड़ी संख्या में लोग गफ्फार और नाईवाला बाजार में पहुंचते हैं। दोनों बाजारों में लोगों की संख्या और कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए नौ जुलाई को रात 10 बजे से 10 जुलाई रात 10 बजे तक बाजार बंद रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों बाजारों में दिल्ली समेत पूरे देश के लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं। गफ्फार मार्केट में मोबाइल का सामान बेचा जाता है। वहीं, नाईवाला बाजार में बाइक के पार्ट्स बेचे जाते हैं, जिन्हें लोग खरीदने के लिए देश के कोने-कोने से पहुंचते हैं। पिछले दिनों प्रशासन की टीम ने बाजार में जाकर दुकानदारों को चेतावनी भी दी थी कि वे शारीरिक दूरी के नियम का ग्राहकों को पालन कराएं। जब प्रशासन की टीम ने उल्लंघन होते हुए देखा तो ग्राहकों और दुकानदारों के चालान भी काटे। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई है। स्थिति नहीं सुधरी तो तो आगे भी बाजार बंद किए जा सकते हैं।

This PDF was originally uploaded To The English Newspaper L-- Banna SA (https://t.me/English_Newspaper_L_Banna)one else Backup chennal @NEWS_Backup_L_Banna

20 वांछित नक्सलियों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सूची जारी की है छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक भीमा मंडावी की हत्या के मामले में। एजेंसी ने इन पर अधिकतम सात लाख तक का इनाम घोषित किया है।

न्यूज गैलरी

राष्ट्रपति से मिले गृह मंत्री शाह, शिष्टाचार भेंट बताया

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द से मुलाकात की। गृह मंत्री ने ट्वीट कर इसे शिष्टाचार भेंट बताया। प्रेट्र के मुताबिक, गृह मंत्री 17 जुलाई को उत्तर पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों के सीमा विवाद को लेकर बैठक करेंगे। बैठक में इन प्रदेशों के मुख्य सचिव और डीजीपी भी शामिल होंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा कि 'गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर पूर्व के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जानकारी दी है। 17 जुलाई को कन्वेंशन हाल में बैठक हो सकती है। केंद्र सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले राज्यों के बीच सीमा विवाद सुलझाने की इच्छा जताई है।' (एएनआइ)

इजरायली रक्षा मंत्री से राजनाथ ने की फोन पर बात

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष इजरायली रक्षा मंत्री बेंजामिन गैंट्ज़े से फोन पर बात की। उन्होंने इजरायल की नई सरकार में उप-प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बनने पर गैंट्ज़े को बधाई दी। राजनाथ ने ट्वीट किया, 'लेफ्टिनेंट जनरल बेंजामिन गैंट्ज़े को उप-प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करने पर बधाई। कोरोना काल में मदद के लिए इजरायल का धन्यवाद। रक्षा सहयोग को और मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी के लिए इजरायल के साथ मिलकर काम करेंगे।' गौरतलब है कि इजरायल से सैन्य उपकरण खरीदने वाला भारत सबसे बड़ा देश है। (प्रेट्र)

सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में वृद्धि को लेकर राहुल का तंज

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महंगाई बढ़ रही है और अच्छे दिन देश पर बोझ बन गए हैं। पीएनजी, सीएनजी प्राइस हाइक हैशटैग के साथ उन्होंने ट्वीट किया-महंगाई बढ़ रही है, अच्छे दिन देश पर बोझ बन गए हैं और प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मित्रों के प्रति जवाबदेह हैं। (एएनआइ)

केटीएस तुलसी ने मां की लिखी पुस्तक पीएम को भेंट की

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें 'गुरु गोबिंद सिंह जी की रामायण' पुस्तक की पहली प्रति मिली है। इस पुस्तक को जाने-माने अधिवक्ता केटीएस तुलसी की मां ने लिखा है। मोदी ने ट्विटर पर तुलसी के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर भी साझा की है। तुलसी पुस्तक की प्रति भेंट करने के लिए मोदी से मिले थे। इस पुस्तक का प्रकाशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किया है। (प्रेट्र)

अब एक अगस्त को प्रस्तावित नीट का टलना तय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए नीट (नेशनल एलिजबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) की तैयारी कर रहे छात्रों को फिलहाल पढ़ाई के लिए कुछ और समय मिल सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट की एक अगस्त को प्रस्तावित परीक्षा तारीख को स्थगित करने के संकेत दिए हैं। साथ ही इस परीक्षा को अब अगस्त के अंतिम हफ्ते में कराने की योजना बनाई है। पहले इसको सितंबर में कराने की योजना बनी थी, लेकिन देश में कोरोना संक्रमण की नई लहर की आशंकाओं को देखते हुए अब इसे अगस्त में कराने की तैयारी है। इसकी नई तारीखों का जल्द ही एलान होगा।

एनटीए से जुड़े अधिकारियों की मानें तो नीट की एक अगस्त की प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव के पीछे कई वजहें हैं। पहला हाल ही में जेईई मेंस के बाकी बचे दो सत्रों के परीक्षा कार्यक्रम का जो एलान किया गया है, उनमें मई सत्र की परीक्षा 27 से 02 अगस्त के बीच आयोजित होनी है। ऐसे में एक अगस्त को परीक्षा कराने में दिक्कत है। इसके साथ ही इसके आवेदन के लिए अब तक न्यूनतम 60 दिन का समय दिया जाता था, जो एक अगस्त को आयोजित होने पर पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था। हालांकि इस बार 60 दिन का समय तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम 35 से 40 दिन मिलने तय हैं।

परीक्षा पर फौरी राहत

सूत्रों के मुताबिक नीट के आयोजन की पूरी रूपरेखा बन गई है। पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंजूरी भी दे दी थी। जेईई मेंस के बाद इसकी तारीख के एलान की योजना थी। लेकिन कैबिनेट में इस बीच हुए फेरबदल के चलते पूरी योजना टल गई। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में नए शिक्षा मंत्री से चर्चा के बाद इसकी तारीख घोषित कर दी जाएगी। गौरतलब है कि कैबिनेट में फेरबदल के एक दिन पहले ही पूर्व शिक्षा मंत्री निशंक ने जेईई मेंस के स्थगित सत्रों का कार्यक्रम घोषित किया था।

सबको शिक्षा, सबको कौशल के मंत्र से गढ़े जाएंगे छात्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भविष्य के भारत के लिए दोनों की बताई जरूरत
- काम-काज संभालने के तुरंत बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा के अमल की प्रगति का लिया जायजा
- प्रधान का मुख्य फोकस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन के साथ आगे बढ़ने का है


नई दिल्ली में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। प्रेट्र

नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही तेजी से काम-काज भी शुरू कर दिया है। शुक्रवार को उन्होंने मंत्रालय के काम-काज से जुड़ी करीब आधा दर्जन बैठकें कीं। इसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल को लेकर भी एक अहम बैठक शामिल है। साथ ही संबंधित अधिकारियों से नीति के अमल की प्रगति की पूरी रिपोर्ट ली है। खास बात यह है कि नीति के अमल को एक तय समयसीमा में लागू करने का मंत्रालय ने एक खाका बनाया है।

प्रधान का मुख्य फोकस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन के साथ आगे बढ़ने का है। इस दौरान उन्होंने सबको शिक्षा के साथ ही सबको कौशल से जोड़ने का मंत्र भी दिया। साथ ही कहा कि भविष्य के भारत को नई ऊंचाई देना है तो छात्रों को शिक्षा के साथ कौशल से भी जोड़ना जरूरी है। देश के 30 करोड़ से ज्यादा छात्रों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए यह बेहद अहम है। गौरतलब है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कौशल विकास पर जोर दिया गया है। साथ ही स्कूली स्तर से ही बच्चों को किसी एक स्किल से जोड़ने की सिफारिश की गई है। प्रधान ने इस दौरान मीडिया से अनौपचारिक चर्चा में कहा कि डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। इस दिशा में मंत्रालय काफी तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह अपने पूर्व शिक्षा मंत्रियों की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर प्रधान ने रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावडेकर और स्मृति ईरानी के नामों का भी जिक्र किया।

आरटीआइ से हासिल दस्तावेजों का हवाला मत दो : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत प्राप्त सूचनाओं को यूं तो बहुत अहम माना जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान पक्षकार की ओर से आरटीआइ के जरिये हासिल दस्तावेजों का हवाला देने से मना करते हुए मौखिक टिप्पणी में कहा आरटीआइ से हासिल जवाब का हवाला मत दीजिए। ये बहुत भरोसे लायक नहीं होते। पीठ ने कहा कि हमारा अनुभव है कि आरटीआइ में पूछे गए सवाल का पत्र किसी और अथारिटी के पास पहुंच गया तो जवाब भिन्न होगा।

जस्टिस एएम खानविलकर व संजीव खन्ना की पीठ ने यह टिप्पणी उप्र के डिमोलीशन मामले में सुनवाई के दौरान की। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अथारिटी ने उनकी जमीन पर बने निर्माण को गैरकानूनी ढंग से ढहा दिया है। अथारिटी को नहीं रोका गया तो छह परिवारों के 25 सदस्य आश्रयहीन हो जाएंगे। याचिकाकर्ता ने कहा, आरटीआइ के जवाब में विकास प्राधिकरण ने कहा कि यह मास्टर प्लान में रिहायशी चिह्नित है।

रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद जार्जिया पहुंचे जयशंकर

कूटनीति ▶ जार्जिया जाने वाले देश के पहले विदेश मंत्री, रूस और जार्जिया में 36 का आंकड़ा

रूसी विदेश मंत्री भी अप्रैल में भारत के बाद पाकिस्तान यात्रा पर गए थे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मास्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से लंबी द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसमें परमाणु, अंतरिक्ष, ऊर्जा व रक्षा सहयोग के साथ ही मुक्त व्यापार समझौते व अफगानिस्तान में सहयोग जैसे व्यापक मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने पारंपरिक दोस्ताना रिश्तों की कसमें भी खाईं और पीएम नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच इस साल होने वाली शिखर बैठक की तैयारियों की समीक्षा भी की। इसके बावजूद दोनों देशों के रिश्तों में कुछ ऐसा है, जिससे लग रहा है कि दोनों देश एक-दूसरे को कुछ संकेत भी दे रहे हैं। दरअसल, मास्को की यात्रा समाप्त करने के बाद शुक्रवार को ही देर रात जयशंकर रूस के पड़ोसी देश जार्जिया की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा को अप्रैल 2021 में लावरोव की पाकिस्तान यात्रा से जोड़ कर देखा जा रहा है, क्योंकि रूस और जार्जिया में वैसे ही रिश्ते हैं जैसा भारत व पाकिस्तान के बीच है। यह किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की पहली जार्जिया यात्रा है।


रूस की यात्रा के दौरान एस जयशंकर मास्को में अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ। प्रेट्र

लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में जयशंकर ने कहा कि हमारी वार्ता बहुत लाभदायक रही है। वैश्विक माहौल में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं और खास तौर पर कोरोना के बाद के हालात को देखते हुए भी भारत व रूस के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। हम मानते हैं कि वैश्विक स्तर पर शांति व सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए भारत व रूस के रिश्तों को और मजबूत बनाया जाना चाहिए। कोरोना के बावजूद पिछले एक वर्ष के दौरान हमने रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा व विदेश मंत्रियों की अगुआई में टू प्लस टू वार्ता शुरू करने को एक अहम उपलब्धि बताया। उन्होंने रूसी कंपनियों की तरफ से मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा उपकरणों के निर्माण में रुचि दिखाने का खास तौर पर जिक्र किया। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और सुदूर पूर्व रूस में भारतीय कंपनियों की निवेश संभावनाओं पर भी बात हुई है।

दोनों मंत्रियों के बीच वार्ता में अफगानिस्तान भी अहम रहा। लावरोव ने अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात को लेकर चिंता भी जताई। जयशंकर ने रूस को याद दिलाया कि अफगानिस्तान में पिछले दो दशकों में लोकतंत्र स्थापित करने व आर्थिक प्रगति को लेकर जो कदम उठाए गए हैं, उन्हें बनाए रखने की जरूरत है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी दोनों देशों में बात हुई है। इस क्षेत्र को लेकर जयशंकर ने कहा कि भारत रूस को इस क्षेत्र में और ज्यादा सक्रिय देखना चाहता है।

लावरोव ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का मुद्दा उठाया है। यह पहला मौका है जब भारत और रूस के बीच एफटीए को लेकर बातचीत हुई है। दोनों देशों ने वर्ष 2025 तक अपना द्विपक्षीय कारोबार 30 अरब डालर करने का लक्ष्य रखा है।

व्यापक साझेदारी को लेकर चर्चाओं के बावजूद जयशंकर के इस दौरे को उनकी जार्जिया यात्रा से जोड़ कर देखा जाएगा। जार्जिया 1991 में तत्कालीन सोवियत गणराज्य से अलग हुआ था और भारत ने 1992 में उसके साथ कूटनीतिक रिश्ते भी बना लिए थे। लेकिन बाद में रूस और जार्जिया के रिश्ते बिगड़ने की वजह से भारत सरकार ने उसके साथ रिश्तों को ज्यादा तरजीह नहीं दी। 2008 में रूस और जार्जिया में युद्ध भी हुआ था और उसके बाद भारत से उसके रिश्ते कुछ ज्यादा ही सुस्त हो गए। अपने सबसे भरोसेमंद साझेदार रूस के हितों को देखते हुए भारत ने जार्जिया के साथ रिश्तों को ठंडा ही रखा। अप्रैल में लावरोव ने भी जब भारत के बाद पाकिस्तान की यात्रा की थी तो उसको लेकर कई तरह की बातें हुई थीं। माना जाता है कि आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने के साथ ही भारत और रूस वैश्विक कूटनीति में हो रहे बदलावों के मद्देनजर उन देशों के साथ भी रिश्तों को पटरी पर ला रहे हैं, जिसे अभी तक सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर रहे थे कि कहीं दूसरा पक्ष नाराज ना हो जाए।

देशमुख मामले में परमबीर से भी पूछताछ करेगी ईडी

राज्य ब्यूरो, मुंबई

▶ पूर्व पुलिस आयुक्त ने ही सबसे पहले देशमुख पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सबसे पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जल्द पूछताछ कर सकता है। फिलहाल निदेशालय मुंबई पुलिस के बर्खास्त हो चुके एपीआइ सचिन वाझे से पूछताछ कर रहा है। वाझे से पूछताछ शनिवार को भी जारी रहेगी।

ईडी ने परमबीर को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से कुछ दिन बाद ईडी के सामने हाजिर होने की अनुमति मांगी है। माना जा रहा है कि ईडी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पर शिकंजा कसने के लिए उन पर आरोप लगानेवाले सभी लोगों से पूछताछ कर तथ्य जुटा रही है। देशमुख पर सबसे पहले परमबीर ने ही 100 करोड़ रुपये प्रति माह की वसूली का टार्गेट देने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह आरोप मुख्यमंत्री को लिखे अपने लंबे पत्र में तब लगाया था, जब मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से उन्हें हटाए जाने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने एक चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि परमबीर सिंह को उनकी जिम्मेदारियां ठीक से न निभा पाने के कारण हटाया गया है।

परमबीर ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि देशमुख पुलिस अधिकारियों को अपने सरकारी आवास पर बुलाकर उन्हें हर महीने 100 करोड़ रुपये वसूलने का टार्गेट देते थे। परमबीर ने इस पत्र में एपीआइ सचिन वाझे सहित दो अन्य पुलिस अधिकारियों के नामों का उल्लेख किया था। बाद में एनआइए कोर्ट को लिखे अपने पत्र में वाझे ने भी परमबीर के आरोपों की पुष्टि की थी।

अब तक ईडी की जांच में यह तथ्य सामने आ चुका है कि वाझे ने मुंबई के बारों से 4.70 करोड़ रुपये वसूले और यह राशि दो सहयोगियों के जरिये देशमुख तक पहुंची। फिर हवाला के माध्यम से दिल्ली स्थित कुछ कागजी कंपनियों को भेजी गई। फिर उन कंपनियों ने 4.18 करोड़ रुपये देशमुख के एक पारिवारिक ट्रस्ट को दान स्वरूप भेज दिए। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष खुद अनिल देशमुख हैं। ईडी इस मामले में अब तक बार मालिकों, कागजी कंपनियों के मालिकों तथा देशमुख के दो सहयोगियों के बयान दर्ज कर चुकी है। इन सहयोगियों के सामने ही देशमुख ने वाझे को वसूली का आदेश दिया था। अब ईडी वाझे एवं परमबीर से पूछताछ करके अपनी जांच की कड़ी पूरी करना चाहती है। इसी कड़ी में गुरुवार एवं शुक्रवार को तलोजा जेल में बंद वाझे से ईडी पूछताछ कर चुकी है। उससे पूछताछ शनिवार को भी जारी रहेगी। वह मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन लदी स्कार्पियो खड़ी पाए जाने एवं इसके कुछ ही दिन बाद इस स्कार्पियो के कथित मालिक की हत्या के मामले में एनआइए की गिरफ्त में है। इसके बाद परमबीर सिंह से भी ईडी पूछताछ करेगी। हालांकि, देशमुख के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस, शिवसेना एवं राकांपा को रास नहीं आ रही है।

सरकारी निगरानी नहीं होने से पारदर्शिता का अभाव

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट बनने के बाद ही देश में सहकारी क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियां स्थापित की गईं। इनमें केंद्रीय मदद भी ली गई, लेकिन अब उनमें सरकार की हिस्सेदारी धेले भर की भी नहीं है। सरकारी निगरानी नहीं होने से पारदर्शिता का अभाव है, जिससे इन कंपनियों के प्रबंधन में घूम फिरकर गिनती के वही लोग सर्वेसर्वा होते हैं। इनमें और सहकार सदस्यों को कभी स्थान प्राप्त नहीं होता। पूर्ववर्ती सरकारों में रहे राजनीतिक दलों के नेताओं के एक वर्ग के लिए यह दुधारू गाय है।

40 करोड़ सदस्यों के जरिये साधी जाती है राजनीति : सहकारिता की आठ लाख प्राइमरी सोसायटियों में 40 करोड़ सदस्य हैं। जाहिर है कि इसके जरिये राजनीति साधी जाती रही है। सहकारी क्षेत्र को मजबूत व कारगर बनाने के लिए केंद्र ने राज्यों को सारे सिस्टम का कंप्यूटरीकरण करने के लिए वित्तीय मदद प्रदान की। इसके बावजूद एक दर्जन राज्यों में ही यह किया जा सका है। पूरे सिस्टम को आनलाइन करने की कोशिशें नहीं की गईं।

अगस्त से फिर काम शुरू करेगा भीमा कोरेगांव जांच आयोग

राज्य ब्यूरो, मुंबई

▶ शरद पवार सहित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दर्ज किए जाएंगे बयान

महाराष्ट्र में साढ़े तीन साल पहले हुए भीमा कोरेगांव उपद्रव की जांच कर रहा आयोग अगले माह से पुनः काम शुरू करेगा। इस आयोग के सामने अभी राकांपा अध्यक्ष शरद पवार सहित कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बयान दर्ज होने बाकी हैं।

एक जनवरी, 2018 को पुणे के निकट भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। अचानक भड़के इस उपद्रव से ठीक पहले 31 दिसंबर, 2017 को पुणे स्थित शनिवार वाड़ा के द्वार पर एलगार परिषद का आयोजन माओवादी संगठनों के सहयोग से किया गया था। इन दोनों घटनाओं के बाद महाराष्ट्र में एक सप्ताह तक अशांति का माहौल रहा था। एलगार परिषद एवं भीमा कोरेगांव मामलों की अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। एलगार परिषद मामले में कई माओवादी कार्यकर्ता गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लेकिन हिंसा भड़काने के इस कुचक्र की शुरुआत कैसे हुई, इसकी जांच के लिए तत्कालीन राज्य सरकार ने नौ फरवरी, 2018 को बांबे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जेएन पटेल की अध्यक्षता में दो सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था। इसके दूसरे सदस्य राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सुमित मलिक हैं। आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए चार माह का समय दिया गया था। उसने जांच शुरू कर कई लोगों के बयान दर्ज किए। इस दौरान उसके कार्यकाल को चार-चार माह के तीन विस्तार भी दिए गए। आयोग ने 30 मार्च से चार अप्रैल, 2020 के बीच राकांपा अध्यक्ष शरद पवार सहित कुछ और प्रमुख लोगों को पूछताछ के लिए समन भिजवाया था। तब तक देश में लाकडाउन शुरू हो जाने के कारण आयोग को कामकाज बंद करना पड़ा था।

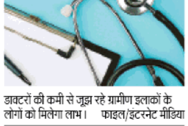
तीसरी लहर की तैयारी पूरे स्वास्थ्य ढांचे को करेगी मजबूत

नीलू रंजन, नई दिल्ली

▶ आक्सीजन प्लांट, एंबुलेंस और ई-संजीवनी से दूर-दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदलेगी तस्वीर

केंद्र सरकार की ओर से घोषित दूसरा स्वास्थ्य पैकेज तीसरी लहर की तैयारियों के साथ-साथ स्वास्थ्य ढांचे को स्थायी रूप से मजबूत भी करेगा। कोरोना की दूसरी लहर की व्यापकता और टीकाकरण की बढ़ती रफ्तार के आधार पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) ने तीसरी लहर के दूसरी लहर की तुलना में कमजोर होने का अनुमान लगाया है। जाहिर है पैकेज से मजबूत होने वाले स्वास्थ्य ढांचे का लाभ लंबे समय तक आम लोगों को मिलता रहेगा।

कोरोना की तीसरी लहर के बारे में वैसे तो अलग-अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक के हुए अध्ययनों से यह साफ है कि कोरोना से पहले संक्रमित होने वालों और वैक्सीन लेने वालों को संक्रमित होने की संभावना कम होती है और संक्रमित होने के बाद भी बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है। दूसरी लहर की व्यापकता का सही अंदाजा तो सीरो-सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कई शहरों में हुए स्थानीय स्तर पर हुए सीरो-सर्वे में 90 फीसद तक लोगों के संक्रमित होने के सबूत मिले हैं। जाहिर है ऐसे लोगों में तीसरी लहर का प्रभाव दूसरी लहर जैसा नहीं होगा।


डाक्टरों की कमी से जूझ रहे ग्रामीण इलाकों के लोगों को मिलेगा लाभ। फाइल/इंटरनेट मीडिया

तीसरी लहर को कमजोर करने में सबसे अहम भूमिका टीकाकरण की भी होगी। वैसे तो वैज्ञानिक रूप से वैक्सीन की दो डोज से इम्यूनिटी विकसित होने की बात की जाती है। लेकिन कई शोधों में यह भी साबित हुआ है कि एक डोज भी काफी हद तक संक्रमण की तीव्रता को रोकने में सहायक है और कोरोना से संक्रमित हो चुके व्यक्ति में एक डोज भी इम्यूनिटी विकसित कर देती है।

सरकार ने इस साल के अंत तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी लगभग 94 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। वहीं आइसीएमआर ने तीसरी लहर के नवंबर से जनवरी के बीच कभी भी शुरू होने का अनुमान लगाया है। यानी तीसरी लहर शुरू होने के पहले ही देश में अधिकांश लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी है।

ई-संजीवनी को मजबूत किया जाएगा : गुरुवार को घोषित दूसरे पैकेज के तहत देश के सभी जिलों में आक्सीजन रखने के लिए स्टोरेज तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही 8,800 नई एंबुलेंस भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ई-संजीवनी प्लेटफार्म को भी और मजबूत किया जाएगा, अभी तक यह प्लेटफार्म दूर-दराज के कोरोना मरीजों को बेहतरीन डाक्टरों की सलाह मुहैया करने में कारगर साबित हुआ है। फिलहाल इस पर हर दिन 50 हजार लोगों को सलाह दी जा रही है, जिसे बढ़ाकर प्रतिदिन पांच लाख करने की तैयारी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आक्सीजन उत्पादक प्लांट, भंडारण क्षमता और एंबुलेंस का इस्तेमाल सिर्फ कोरोना के मरीजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामान्य बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल होता रहेगा। इनकी उपलब्धता दूर-दराज के इलाकों में बेहतर इलाज मुहैया कराने में अहम साबित हो सकती है। वहीं ई-संजीवनी को आसानी से कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों के लिए सलाह के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। डाक्टरों की कमी से जूझ रहे ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए यह वरदान साबित हो सकता है।

प्रभाव की लड़ाई

नए सहकारिता मंत्रालय के गठन में छिपी सियासत से अलर्ट हुई कांग्रेस

चेन्निथला ने हाईकमान को पत्र लिखकर जताई आशंका, सहकारी संस्थाओं में बढ़ेगी संघ-भाजपा की सियासी पैठ, शाह को मंत्रालय सौंपे जाने के मद्देनजर जल्द सियासी पलटवार का किया आग्रह, जल्द दूसरे विपक्षी दलों से चर्चा करेगी पार्टी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के पीछे संघ-भाजपा के छिपे राजनीतिक एजेंडे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला के आरोप ने कांग्रेस के कान खड़े कर दिए हैं। इस नए मंत्रालय के जरिये केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक की सहकारी संस्थाओं में भाजपा का प्रभाव बढ़ाने की तैयारी की चेन्निथला की आशंका को पार्टी नजरअंदाज नहीं कर रही है। संकेत हैं कि कांग्रेस जल्द ही इसको लेकर विपक्षी खेमे के दूसरे दलों से चर्चा करेगी। उनसे मशविरे की यह प्रक्रिया मानसून सत्र से पहले पूरी की जाएगी ताकि इस नए मंत्रालय के गठन के पीछे की सियासत को संसद में उठाया जा सके।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ रणनीतिकार ने इस बारे में पार्टी हाईकमान को चेन्निथला के भेजे पत्र की चर्चा करते हुए कहा कि उनकी चिंता को इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद राजनीतिक साथी गृह मंत्री अमित शाह को इस मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है। उन्होंने कहा कि पार्टी मंत्रालय गठन से जुड़े राजनीतिक पहलुओं का इस चिंता के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने के बाद ही अन्य विपक्षी पार्टियों से बातचीत करेगी। मगर इसमें संदेह नहीं कि राजनीति के अनुभवी चेन्निथला ने इस मंत्रालय के गठन पर न केवल राजनीतिक बहस का रास्ता खोल दिया है बल्कि केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया है।

मालूम हो कि चेन्निथला ने कहा है कि भाजपा का यह कदम वित्तीय दृष्टिकोण से मजबूत सहकारी संस्थाओं को अपने प्रभाव में लेने की उसकी साजिश का हिस्सा है। केरल और महाराष्ट्र में वित्तीय रूप से मजबूत सहकारी संस्थाओं का बहुत बड़ा नेटवर्क है। महाराष्ट्र में सहकारी संस्थाओं पर जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मजबूत पकड़ है, वहीं केरल में माकपा और कांग्रेस का अपना-अपना प्रभाव है। उनके अनुसार भाजपा इन दोनों राज्यों में सहकारी संस्थाओं की राजनीति में अपनी पैठ बनाने में नाकाम रही है और इसके मद्देनजर ही चेन्निथला ने कांग्रेस हाईकमान को तत्काल नए मंत्रालय के गठन के पीछे छिपी सियासत पर जवाबी वार करने की जरूरत बताई है।


रमेश चेन्निथला। फाइल/इंटरनेट मीडिया

'भाजपा के लिए महत्वपूर्ण होने के चलते शाह को सौंपा मंत्रालय'

केरल की पिछली विधानसभा में नेता विपक्ष रहे चेन्निथला के मुताबिक अमित शाह को यह मंत्रालय सौंपे जाने से स्पष्ट है कि भाजपा के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। उनका यह भी मानना है कि केरल-महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, बंगाल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में सहकारी समितियां व्यापक जनआंदोलन का हिस्सा बनकर उभरी हैं और इनके ढांचे का स्वरूप भी धर्मनिरपेक्ष है। इसलिए संघ-भाजपा इन सहकारी संस्थाओं में अभी तक अपनी जगह नहीं बना सके हैं। ऐसे में उन्हें आशंका है कि केंद्र का यह कदम भगवा राजनीति के एजेंडे के लिए इसमें राह बनाने पर केंद्रित है। चेन्निथला का कहना है कि केंद्र के इस मकसद को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व को अपने संगठनात्मक राजनीतिक प्लेटफार्म के साथ-साथ संसद और विधानसभाओं में संघ-भाजपा के इस एजेंडे के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।

कह के रहेंगे माधव जोशी



This PDF was originally uploaded To The English Newspaper L-- Banna SA (https://t.me/English_Newspaper_L_Banna)one else Backup chennal @NEWS_Backup_L_Banna

1778 नामांकन बीते गुरुवार को किए गए थे उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद के लिए। जांच में कमियां मिलने पर 68 नामांकन रद कर दिए गए। 187 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 10 जुलाई, 2021

उत्तर प्रदेश में 349 ब्लाक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित

कुर्सी की दौड़ ▶ 476 के लिए मतदान आज, तीन बजे के बाद आज ही होगी मतगणना

निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए प्रत्याशियों में से 334 से ज्यादा भाजपा के हैं

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत प्रमुख (ब्लाक प्रमुख) के 825 पदों में से 476 पदों के लिए शनिवार को मतदान होगा। शुक्रवार को नामांकन वापसी के बाद 349 ब्लाक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। इनमें से 334 से ज्यादा भाजपा के हैं। शनिवार को तीन बजे तक मतदान के बाद मतगणना होगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि ब्लाक प्रमुख के 825 पदों के लिए कुल 1778 नामांकन बीते गुरुवार को किए गए थे। जांच में कमियां मिलने पर 68 नामांकन रद कर दिए गए। 187 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नाम वापसी के बाद जिन 349 पदों पर एक ही प्रत्याशी रह गया, वहां उसे निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

शेष 476 पदों के लिए अब 1174 वैध प्रत्याशी हैं। शनिवार सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा। तीन बजे से ही मतगणना होगी। मतगणना पूरी होते ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि गोंडा जिले के ब्लाक मुजेहना का कार्यकाल पूरा न होने के कारण यहां ब्लाक प्रमुख का चुनाव नहीं कराया जा रहा है।

निर्विरोध निर्वाचित प्रमुखों में 334 से ज्यादा भाजपा के

भाजपा के प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि निर्विरोध निर्वाचित ब्लाक प्रमुखों में 334 से ज्यादा भाजपा के हैं। पार्टी की ओर से पंचायत चुनाव का दायित्व संभाल रहे राठौर के मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्ष की तरह प्रमुख क्षेत्र पंचायत के पदों पर भी भाजपा का शानदार प्रदर्शन रहेगा। जिन पदों के लिए शनिवार को मतदान है, उनमें से भी ज्यादातर पर भाजपा ही जीत हासिल करेगी।

जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण 12 को

नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों को 12 जुलाई को सुबह 11 बजे शपथ दिलायी जाएगी। इस संबंध में पंचायती राज विभाग द्वारा सभी जिलाधिकारियों को दिए गए निर्देशों के मुताबिक नवगठित जिला पंचायत की प्रथम बैठक 12 जुलाई को ही दोपहर में की जाए। बैठक में जिला पंचायत की समितियों के गठन पर विचार किया जा सकता है। जिलाधिकारियों को पूरी कार्यवाही करने तथा शासन को भी बताने के लिए कहा गया है।

गुजरात कांग्रेस में बढ़ी रार, युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष पार्टी से बाहर

जागरण संवाददाता, अहमदाबाद : गुजरात प्रदेश कांग्रेस में रार बढ़ गई है। प्रदेश युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष निखिल सवाणी को तत्काल प्रभाव से उपाध्यक्ष पद से हटाने के साथ ही पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल का राजनीतिक करियर खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया था। सवाणी ने कहा कि गुजरात कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। पैसा एकत्र करने के लिए ही पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया जाता है। एनएसयूआइ व युवक कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव भी पैसों के दम पर जीते जाते हैं। कांग्रेस में राजा का बेटा ही राजा बनने की परंपरा है और आम कार्यकर्ता को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है।

बता दें कि गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावडा, नेता विपक्ष परेश धनाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भरतसिंह सोलंकी आदि नेताओं की उपस्थिति में गत दिनों प्रदेश कार्यालय पर एक बैठक हुई थी। बैठक में युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक गुलाबसिंह राजपूत एवं उपाध्यक्ष निखिल सवाणी के बीच जमकर तकरार हुई। इसके बाद सवाणी सहित छह कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया। अपनी सफाई को लेकर सवाणी ने पत्रकार वार्ता करने का एलान किया तो उससे पहले ही गुरुवार शाम युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हेमंत ओगले ने बिना कोई कारण बताए उन्हें उपाध्यक्ष पद से हटाने के साथ ही पार्टी से भी निष्कासित कर दिया।

महिला प्रस्तावक से बदसलूकी मामले में सीओ समेत छह पुलिसकर्मी निलंबित

▶ मुख्यमंत्री ने लखीमपुर की घटना पर जताई कड़ी नाराजगी

जागरण टीम, लखनऊ

ब्लाक प्रमुख के नामांकन के दौरान उप्र के लखीमपुर में महिला प्रस्तावक से बदसलूकी की घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता से लिया है। उनके सख्त रुख के बाद सीओ मोहम्मदी अभय प्रताप मल्ल, एसएचओ पसगवां आदर्श कुमार सिंह समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। सपा प्रत्याशी रीतू सिंह की तहरीर पर पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता बृजकिशोर व यश वर्मा व अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। आरोपित यश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है।

गौरतलब है कि ब्लाक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान गुरुवार को लखीमपुर के पसगवां में जमकर अराजकता हुई थी। सपा प्रत्याशी रीतू सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों ने उन्हें नामांकन दाखिल नहीं करने दिया। उनकी एक महिला प्रस्तावक के साथ की गई बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद मामला काफी तूल पकड़ गया। वायरल वीडियो में कुछ लोग महिला प्रस्तावक के साथ खींचतान करते और उसके कपड़े खींचते दिख रहे हैं। वहां तैनात पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मामला गुरुवार से ही इंटरनेट मीडिया पर छाया रहा।

आरोपितों का भाजपा से कोई सरोकार नहीं : डा. दिनेश शर्मा

उप मुख्यमंत्री डा.दिनेश शर्मा का कहना है कि लखीमपुर में महिला प्रस्तावक से बदसलूकी करने वाला आरोपित निर्दलीय प्रस्तावक का समर्थक है। आरोपितों का भाजपा से कोई सरोकार नहीं है। कहा कि राज्य सरकार अपराध को लेकर जीरो टालरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। उन्होंने पंचायत चुनाव में हो रही हिंसा को लेकर सपा पर निशाना भी साधा। कहा कि सपा मुखिया को यह समझना चाहिए कि भाजपा सरकार में अराजकतत्वों व अपराधियों को संरक्षण देने के बजाए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। पिछली सरकार में कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ, जिसमें लोगों की जानें नहीं गईं। अब जब उनकी मनमानी नहीं हो पा रही है तो कानून-व्यवस्था संभाल रहे पुलिस-प्रशासन के अफसरों पर गलत आरोप लगा रहे हैं।

महिला बीडीसी सदस्य के अपहरण की कोशिश, विरोध पर जेठ की हत्या

जासं, बहराइच

▶ नामजद आरोपितों में तीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार

ब्लाक प्रमुख चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए सत्तापक्ष ने महिला बीडीसी सदस्य के अपहरण के लिए रायगंज ग्राम पंचायत के दीनापुरवा गांव (बहराइच) में जमकर बवाल किया। विरोध कर रहे जेठ की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। स्वजन 30 लाख मुआवजे की मांग करते हुए अंतिम संस्कार न करने पर अड़ गए। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कराया। नामजद आरोपितों में सुधीर यज्ञसैनी, रामभुलावन शुक्ल व प्रमिलेश जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है।

शिवपुर में दीनापुरवा निवासी सुंदरलाल लोधी की पत्नी यदुरायी देवी क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हुईं हैं। बीते गुरुवार की रात्रि लगभग दो बजे ब्लाक प्रमुख पद की उम्मीदवार सरिता यज्ञसैनी के पति सुधीर यज्ञसैनी का काफिला दीनापुरवा गांव पहुंचा। आरोप है कि वोट मांगने की जगह घर पर मौजूद शिवपूजन से बीडीसी सदस्य के विषय में पूछा और घर में घुस गए, लेकिन बीडीसी सदस्य नहीं मिलीं। इस बीच शोर सुनकर जेठ मायाराम एवं देवर रामसागर लोधी भी मौके पर आ गए।

परिवार के लोगों ने विरोध किया तो गनर की बंदूक के बट से मायाराम की जमकर पिटाई की, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। इलाज के दौरान रात में ही उसकी मौत हो गई। अन्य लोगों को भी बीचबचाव में हल्की चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार ने इस मामले में पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तनाव के मद्देनजर गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।

थाना प्रभारी विमलेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के भाई रामसागर लोधी की तहरीर पर पांच नामजद सहित दस लोगों के खिलाफ हत्या, बलवा एवं घर में घुसकर उत्पात करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। नामजद अभियुक्तों में सुधीर यज्ञसैनी, उनके गनर, रामभुलावन शुक्ल, प्रमिलेश जायसवाल, मुकेश शुक्ल शामिल हैं। इसके अलावा पांच अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

> नामजद तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। दोषियों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी।
> -सुजाता सिंह, पुलिस अधीक्षक

52 फीसद को भरोसा, उत्तर प्रदेश में फिर जीतेंगे योगी आदित्यनाथ

आइएएनएस-सीवोटर सर्वे

▶ जिला पंचायत चुनाव में 75 मे से 67 सीटें जीतकर भाजपा के हौसले बुलंद, केंद्रीय नेतृत्व ने दी बधाई

▶ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी भी कर चुके हैं योगी के नेतृत्व की तारीफ


योगी आदित्यनाथ। फाइल/इंटरनेट मीडिया

नई दिल्ली, आइएएनएस : उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर सर्वे में लोगों ने फिर भरोसा जताया है। आइएएनएस-सीवोटर के एक सर्वे के मुताबिक 52 फीसद मानते हैं कि उप्र में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं 37 फीसद का मानना है कि ऐसा नहीं होगा। बता दें हाल ही में उप्र में हुए जिला पंचायत चुनाव में 75 में से भाजपा ने 67 सीटें जीती थीं। इस जीत ने भाजपा का हौसला बढ़ाया है।

जिला पंचायत चुनावों में भाजपा की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर चुके हैं। पीएम मोदी ने भाजपा की शानदार विजय को विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद बताया था। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया था कि यह जीत भाजपा की नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। स्पष्ट संदेश हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के विकास और सुशासन के एजेंडे के साथ है। नड्डा ने इसके लिए उप्र भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह और कार्यकर्ताओं को भी बधाई थी थी। नड्डा ने कहा था-प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उप्र सरकार हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है।

बता दें पिछले विस चुनावों (2017) में भाजपा ने 403 में से 312 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। वहीं 2012 में भाजपा को मात्र 47 सीट मिली थीं। भाजपा के दिग्गजों को उम्मीद है कि पार्टी एक बार फिर 2017 को दोहराएगी।

तेजप्रताप के तंज से आहत जगदानंद ने दिया इस्तीफा!

राज्य ब्यूरो, पटना : लालू प्रसाद के करीबी राजद के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि वह विधायक तेजप्रताप यादव के व्यवहार से असहज महसूस कर रहे थे। हालांकि उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया गया है। लालू ने उन्हें अपने पद पर बने रहने का आग्रह किया है। इस बीच राजद की ओर से भी इस्तीफे की बात से इन्कार किया गया है, मगर सूत्र बता रहे कि जगदानंद अपने पद पर बने रहना नहीं चाहते हैं। अपनी भावना से उन्होंने तेजस्वी यादव को भी अवगत करा दिया है।

इस्तीफे की खबर आने के तुरंत बाद राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन व मृत्युंजय तिवारी ने बयान जारी कर इसे बेबुनियाद बताया। मीडिया के सवालों पर जगदानंद ने न तो इसे पूरी तरह स्वीकार किया और न ही इन्कार किया। उनके तौर-तरीके व तेवर से साफ है कि पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। इसकी तस्दीक लालू परिवार से जुड़े सूत्र भी करते हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने चिराग पासवान की याचिका को माना आधारहीन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली



हाई कोर्ट ने कहा, चिराग लोकसभा अध्यक्ष के पास जाने के लिए स्वतंत्र। फाइल

लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के सांसद चिराग पासवान की याचिका को आधारहीन मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। चिराग ने लोजपा कोटे से हाल ही में मंत्री बनाए गए पशुपति नाथ पारस को सदन में पार्टी का नेता नामित किए जाने के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि यह आपसी विवाद है और इसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि चिराग अन्य विकल्पों का प्रयोग कर सकते हैं और लोकसभा अध्यक्ष के पास जाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। पीठ ने चिराग के अधिवक्ता एके बाजपेयी से पूछा कि इस तरह की याचिका दायर करने के लिए उन पर कितना जुर्माना लगाया जाए। अधिवक्ता ने कहा कि अदालत आने का उन्हें अधिकार है, इसलिए जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए। इस अनुरोध को अदालत ने स्वीकार कर लिया।

सुनवाई के दौरान बाजपेयी ने सवाल उठाया कि लोजपा नेता के रूप में चिराग की जगह पशुपति नाथ पारस को संसद में मान्यता दे दी गई। बगैर किसी सूचना के चिराग का नाम लोकसभा में पार्टी नेता के पद से हटा दिया गया। यह पार्टी के संविधान के विपरीत है, क्योंकि यह फैसला संसदीय बोर्ड को लेना चाहिए था।

केंद्र ने कहा, छह में से पांच सांसद चिराग के साथ नहीं : इस पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पार्टी के छह सदस्यों में से पांच चिराग के साथ नहीं हैं। ऐसे में यह मामला न्यायिक समीक्षा का नहीं है। पीठ ने बाजपेयी से कहा कि अगर आप मामले पर जिरह करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन यह पार्टी का आंतरिक विवाद है।

लोकसभा सचिव की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने पीठ को बताया कि यदि किसी सदस्य को पार्टी से बाहर निकाला जाता है, तो वह तब तक उसी पार्टी का माना जाता है, जब तक किसी और दल में शामिल नहीं होता। इसलिए याचिका का कोई आधार नहीं है और न ही मामले को आगे देखे जाने की जरूरत है। बाजपेयी ने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं है कि वे पार्टी के सदस्य नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे पार्टी की तरफ से फैसला कर सकते हैं। बाजपेयी के जवाब से असंतुष्ट पीठ ने कहा कि याचिका का कोई आधार नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

बिहार के मंत्री जमा खान ने कहा- हमारे पूर्वज हिंदू थे

जागरण संवाददाता, हाजीपुर


जमा खान ने कहा, खानदान में कुछ लोग अब भी हिंदू हैं। फाइल/इंटरनेट मीडिया

बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने शुक्रवार को कहा है कि उनके पूर्वज हिंदू थे। मूल रूप से राजपूत जाति से थे और खानदान कुछ लोग अब भी हिंदू हैं। उनके साथ उनका पारिवारिक संबंध बना हुआ है। मंत्री ने हाजीपुर में अंजानपीर चौक के पास पत्रकारों से बातचीत में यह बातें कहीं।

मंत्री ने कहा कि उनके पूर्वज बैसवारा से यहां आए थे। हमारे खानदान के दो भाई जयराम सिंह और भगवान सिंह यहां आए थे। जयराम सिंह का खानदान आज भी सरैया गांव में है और वह हिंदू है। दूसरे भाई भगवान सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिनके खानदान से हम लोग हैं। आज भी हम दोनों खानदान के बीच मधुर संबंध बना हुआ है। हम लोग एक-दूसरे के यहां आते-जाते हैं।

पटना से अपने प्रभार वाले जिले सीतामढ़ी जाने के क्रम में समर्थकों के स्वागत के दौरान जमा खान ने मतांतरण से संबंधित सवाल के जवाब में कहा कि कहीं भी कोई स्वेच्छा से धर्म बदलता है या स्वीकार करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन किसी को जबरन, बरगलाकर या लालच दिखाकर धर्म नहीं परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसे लोग नहीं बचेंगे। सरकार की इस पर पैनी नजर है। बिहार में तो यह संभव ही नहीं है, हमारी सरकार में जोर-जबर्दस्ती करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे।

आम आदमी पार्टी की गुजरात युवा इकाई के अध्यक्ष का इस्तीफा

जासं, अहमदाबाद : गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) को पैर पसारने की कोशिशों के बीच बड़ा झटका लगा है। आप प्रदेश युवा इकाई के अध्यक्ष महिपतसिंह चौहाण ने अपने पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि पार्टी उन्हें काम करने की स्वतंत्रता नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि उनके लिए पद पर बने रहना मुश्किल है।

चौहाण ने गुरुवार देर रात इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेताओं व जोन प्रभारी पर काम नहीं करने देने का आरोप लगाया। चौहाण का कहना है कि पार्टी प्रोटोकोल के नाम पर उन्हें काम करने से रोका जाता है, इसलिए वे पद छोड़ना उचित समझते हैं। उनका कहना है कि आप ने अलग तरह की राजनीति का वादा कर युवाओं से जुड़ने का एलान किया था, लेकिन यहां भी स्वतंत्ररूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है। बता दें कि चौहाण खेडा जिले की ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं।

सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ पूर्व सुरक्षा गार्ड की पत्नी ने तीन साल बाद दर्ज कराया केस

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने वाले भाजपा विधायक व नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, अधिकारी के पूर्व सुरक्षा गार्ड की पत्नी ने अपने पति की मौत के करीब तीन साल बाद उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पूर्व मेदिनीपुर जिले के कोंटाई पुलिस स्टेशन में अधिकारी के खिलाफ उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है और पति के कथित आत्महत्या मामले की फिर से जांच की मांग की है।

सुब्रत चक्रवर्ती नाम के सुरक्षा गार्ड की पत्नी सुबर्णा चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है कि सुवेंदु अधिकारी ने उसके पति को आत्महत्या के लिए उकसाया था। उन्होंने पति की मौत के लिए सुवेंदु को जिम्मेदार बताया है। सुबर्णा की शिकायत पर भारतीय दंड सहिंता की धारा 302 और 120 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जाता है कि सुवेंदु के पूर्व सुरक्षा गार्ड सुब्रत चक्रवर्ती ने 13 अक्टूबर, 2018 को कांथी में अपने किराये के घर में कथित तौर पर अपनी सर्विस रिवाल्वर से सिर में गोली मार ली थी। इसके अगले दिन कोलकाता के अपोलो अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। उस दौरान सुवेंदु ममता सरकार में परिवहन मंत्री थे।

हार का बदला लेने के लिए जेल भेजना चाहती हैं ममता : सुवेंदु

सुरक्षा गार्ड की मौत के मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर पर भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि नंदीग्राम में हार का बदला लेने के लिए ममता बनर्जी उन्हें जेल भेजने की साजिश रच रही हैं। उन्होंने ममता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी इच्छा का मान रखते हुए वह कुछ दिन जेल में भी रहकर लौट आएंगे। सुवेंदु ने दावा किया कि उस सुरक्षा गार्ड के परिवार का कोई सदस्य सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का विधायक भी है। हालांकि, उन्होंने विधायक का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हमको पुलिस व केस का डर दिखाकर तृणमूल कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा।

मुझे पति की मौत के मामले में पहले से ही शक था : सुबर्णा

सुबर्णा का आरोप है कि सुब्रत को कोलकाता के अपोलो हास्पिटल ले जाने में काफी देर की गई थी और अगले दिन शाम पांच बजे उनकी मौत हो गई। इतने लंबे समय बाद शिकायत दर्ज कराने के सवाल पर सुबर्णा ने कहा कि मुझे पति की मौत के मामले में पहले से ही शक था, लेकिन वह (सुवेंदु) बहुत प्रभावशाली हैं और पहले सत्ताधारी दल से जुड़े हुए थे, जिस वजह से सब उनके खिलाफ मुंह खोलने से डरते थे। दो बेटियों के साथ रहती हूं, इसीलिए कुछ कह नहीं पाई, पर अब परिस्थिति में बदलाव आने के बाद लग रहा है कि मुझे न्याय मिल सकता है।

'क्या बुनियादी ढांचे के विकास में भी कट-मनी रैकेट संलिप्त'

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति हरीश टंडन की खंडपीठ ने राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त महिला एवं बाल देखभाल गृह के बुनियादी ढांचे के विकास पर किए गए भारी भरकम खर्च को लेकर चिंता व्यक्त की है।

पीठ एक स्वतः संज्ञान मामले पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने रिपोर्ट पेश की। इसमें दिखाया गया था कि राज्य में एक महिला एवं बाल देखभाल गृह के भूतल के बुनियादी ढांचे के विकास पर 3.41 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस पर आश्चर्य व चिंता व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति सौमेन सेन ने कहा कि केवल भूतल के विकास के लिए 3.41 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ऐसा क्यों हुआ। क्या कोई कट-मनी रैकेट सक्रिय है?

धामी नए एजेंडे और उम्मीदों के साथ पहुंचे दिल्ली

राज्य ब्यूरो, देहरादून

▶ प्रधानमंत्री मोदी से आज दोपहर में मुलाकात का कार्यक्रम तय

▶ राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री व भाजपा अध्यक्ष से भी करेंगे मुलाकात


पुष्कर सिंह धामी ने चार जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। फाइल

उत्तराखंड के विकास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भावी एजेंडा जल्द सामने आएगा। धामी नई उम्मीदों के साथ शुक्रवार रात अपने पहले दौरे पर दिल्ली पहुंच गए। उनके साथ मुख्य सचिव डा. एसएस संधू समेत आला अधिकारियों की टीम भी है। शनिवार को धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम तय है। कोरोना संकट के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर वह केंद्रीय नेतृत्व से मार्गदर्शन ले सकते हैं।

गत चार जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले पुष्कर सिंह धामी को शुरुआती दौर से चुनौतियां मुंहबाए खड़ी हैं। नाराज वरिष्ठों को तो वह मना चुके हैं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। इससे निपटने को चाक-चौबंद व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार से मदद की दरकार है, साथ में लंबे समय से धीमे पड़े विकास कार्यों को गति देना जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री इन हालात को केंद्र सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से रखेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ यह पहली शिष्टाचार भेंट होगी। शनिवार को दिल्ली में दोपहर 11.45 बजे धामी प्रधानमंत्री मोदी और एक बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। अमित शाह से तीन बजे शाह, राजनाथ सिंह से शाम पांच बजे, भारी उद्योग मंत्री डा. महेंद्रनाथ पांडेय से साढ़े पांच बजे और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह से शाम छह बजे मुलाकात का कार्यक्रम तय है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी उनकी भेंट होनी है। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव डा. एसएस संधू के अलावा मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार व सचिव शैलेश बगोली की टीम भी रहेगी। केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात में उनके सामने राज्य की जरूरत का खाका प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह से मुलाकात को प्रदेश के भावी एक्शन प्लान के लिहाज से खास माना जा रहा है।

कोश्यारी से की मुलाकात: शुक्रवार रात्रि दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने महाराष्ट्र सदन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से शिष्टाचार भेंट की। दरअसल कोश्यारी उनके राजनीतिक गुरु हैं। कोश्यारी का शनिवार को मुंबई वापसी का कार्यक्रम है। लिहाजा धामी ने दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले उनसे भेंट की।

मुकुल रॉय बंगाल विस की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हाल में पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में वापसी करने वाले मुकुल रॉय को बंगाल विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति (पीएसी) का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। भाजपा की आपत्ति के बावजूद विस के अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगाते हुए औपचारिक रूप से उनके नाम की घोषणा कर दी। इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताते हुए विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की अगुआई में भाजपा के विधायक सदन का बहिष्कार किया। गौरतलब है कि इस समिति के अध्यक्ष का पद परंपरागत रूप से विपक्षी पार्टी के नेता को दिया जाता है।

कृष्णनगर उत्तर से आधिकारिक रूप से भाजपा के विधायक रॉय पिछले माह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि, उन्होंने भाजपा के कई बार कहने के बावजूद विस की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। उधर, विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने इसे अनैतिक कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि सामान्यता पीएसी अध्यक्ष का पद विपक्षी दल के विधायक को ही दिया जाता है, लेकिन तृणमूल सरकार ने नियमों का दुरुपयोग किया है। इसी तरह से तृणमूल ने 2016 में भी यही खेल खेला था और कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए मानस भुइयां को पीएसी का अध्यक्ष बना दिया था, जो बाद में तृणमूल में शामिल हो गए थे।

टीएमसी की ओर से सौरव गांगुली को राज्यसभा भेजने की चर्चा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता


सौरव गांगुली की जन्मतिथि पर ममता के उनके घर जाकर उन्हें शुभकामना दी थी। फाइल

राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) टीम इंडिया के पूर्व कप्तान व बीसीसीआइ के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। गुरुवार को सौरव की जन्मतिथि पर सीएम व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के उनके घर जाकर उन्हें शुभकामना देने के बाद से इस चर्चा ने और जोर पकड़ लिया है।

गौरतलब है कि भाजपा काफी समय से सौरव को अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सौरव को सीधे ममता के खिलाफ खड़ा करने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन सौरव ने साफ तौर पर कह दिया था कि अभी उनकी राजनीति में कदम रखने की कोई योजना नहीं है। ममता के साथ सौरव के अच्छे संबंध हैं। सौरव को बंगाल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनाने में ममता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि बीसीसीआइ अध्यक्ष बनने के बाद सौरव ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। इस साल जनवरी में सौरव को जब दिल का दौरा पड़ा था, तब ममता उन्हें देखने अस्पताल गई थीं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता ने राज्यसभा सदस्यता को लेकर उनसे बातचीत की है।

This PDF was originally uploaded To The English Newspaper L-- Banna SA (https://t.me/English_Newspaper_L_Banna)one else Backup chennal @NEWS_Backup_L_Banna

18 वर्ष से कम आयु के मरीजों का भी होगा एंटीजन टेस्ट उत्तराखंड में। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उठाया गया है कदम।

6
दैनिक जागरण
शनिवार 10 जुलाई, 2021
www.jagran.com

दूसरी लहर गई नहीं, 66 जिलों में संक्रमण दर 10 फीसद

चेतावनी ▸ पर्यटन स्थलों पर भीड़ व प्रोटोकाल के उल्लंघन पर चिंता

जेएनएन, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने एक बार फिर कोरोना महामारी को लेकर लोगों को सावधान किया है। सरकार का कहना है कि अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। देश के 66 जिलों में कोरोना संक्रमण दर अभी भी 10 फीसद से ज्यादा बनी हुई है। महाराष्ट्र और केरल में अभी भी ज्यादा मामले मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते में देश में सामने आए कुल संक्रमितों में से 53 फीसद इन्हीं दोनों राज्यों से थे।

संयुक्त स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने शुक्रवार को प्रेस कान्फ्रेंस में उत्तराखंड के मसूरी स्थित केम्पटी फाल का एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें सैलानियों की भीड़ लगी है और न कोई मास्क पहना है और न उनके बीच ज्यादा दूरी ही है। वीडियो दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि क्या यह संक्रमण को न्योता देना नहीं है। इस तरह की लापरवाही पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए अग्रवाल ने कहा कि इससे संक्रमण बढ़ेगा। अग्रवाल ने कहा कि इस गलत धारणा पर यकीन नहीं किया जा सकता कि दूसरी लहर खत्म हो गई है।

संयुक्त स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में 21 और केरल में 32 फीसद यानी कुल मामलों का 53 फीसद इन्हीं दोनों राज्यों से मामले पाए गए। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 90 जिलों में 80 फीसद मामले मिले हैं। आठ जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 66 जिलों में कोरोना संक्रमण दर 10 फीसद से ज्यादा थी। रूस, ब्रिटेन और बांग्लादेश जैसे कुछ देशों में हाल में संक्रमण के मामलों में हुई वृद्धि का हवाला देते हुए अग्रवाल ने लोगों को लापरवाही के प्रति सचेत भी किया। ब्रिटेन में मामले बढ़ रहे हैं। रूस भी तीसरी लहर की चपेट में है।

लैंब्डा वैरिएंट का कोई केस नहीं मिला: मंत्रालय ने कहा है कि तक कोरोना वायरस के लैंब्डा वैरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है। अग्रवाल ने कहा कि इस वैरिएंट पर लगातार नजर रखी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इसे सातवां वैरिएंट आफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है।



मसूरी के समीप कैम्पटी फाल में शुक्रवार को पर्यटकों की काफी भीड़ रही। पुलिस को दोपहर बाद सीमित संख्या में पर्यटक कैम्पटी फाल भेजने की व्यवस्था बनानी पड़ी। फोटो : जागरण

देश में लोगों को अब तक 37 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत ने अब तक कोरोना वैक्सीन की 37 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को शाम सात बजे तक 27.86 लाख डोज दी गईं। मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार को 18-44 वर्ष आयुवर्ग के 13.28 लाख लोगों को पहली और 1.24 लाख लोगों को दूसरी डोज दी गई। इस आयुवर्ग के कुल 10.98 करोड़ लोगों को पहली और 35.08 लाख लोगों को दूसरी डोज अभी तक दे गई हैं। राज्यों के पास अभी 1.70 करोड़ डोज है।

छह करोड़ से ज्यादा कोरोना जांच कर उप्र ने बनाया रिकार्ड

राब्यू, लखनऊ : उप्र ने छह करोड़ से ज्यादा कोरोना जांच कर रिकार्ड बनाया है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट उत्तर प्रदेश में ही किए गए हैं। यहां कोरोना संक्रमण काफी कम होने के बावजूद औसतन ढाई लाख लोगों की जांच हर दिन की जा रही है।

देश में कोरोना की स्थिति	
भारत	
24 घंटे में नए मामले	43,393
कुल सक्रिय मामले	4,58,727
24 घंटे में टीकाकरण	40.23 लाख
कुल टीकाकरण	36.89 करोड़
शुक्रवार सुबह आठ बजे तक कोरोना की स्थिति	
नए मामले	43,393
कुल मामले	3,07,52,950
मौतें	911
कुल मौतें	4,05,939
कुल सक्रिय मामले	4,58,727
ठीक होने की दर	97.19 फीसद
पाजिटिविटी दर	2.42 फीसद
मृत्यु दर	1.32 फीसद
जांचें (गुरुवार)	17,90,708
कुल जांचें	42,70,16,605

माडर्ना वैक्सीन लाने के लिए काम कर रही सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी दवा कंपनी माडर्ना की कोरोना वैक्सीन लाने के लिए बातचीत चल रही है। जल्द से जल्द वैक्सीन लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अधिक लोगों का टीकाकरण हो सके। पिछले महीने ही देश में माडर्ना की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई थी।

प्रेस कान्फ्रेंस में एक सवाल पर नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डा. वीके पाल ने कहा कि माडर्ना वैक्सीन इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए है। सरकार कंपनी के साथ सक्रिय रूप से बात कर रही है कि कैसे इसे जल्द से जल्द देश में उपलब्ध कराया जाए। वैक्सीन के आयात को लेकर भी काम चल रहा है। एक अन्य सवाल पर पाल ने कहा कि स्वदेशी दवा कंपनी जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के नतीजों को भारत के दवा महानियंत्रक (डीसीजीआइ) के पास जमा करा दिया है। इसका वैज्ञानिक आकलन किया जा रहा है। सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रक्रिया चल रही है। सभी आंकड़ों के आकलन के बाद सिफारिशें की जाएंगी।

जीका वायरस के 14 केस मिलने पर केरल में अलर्ट जारी, केंद्र सरकार ने भेजी टीम

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना महामारी की दूसरी लहर से केरल अभी उबरा भी नहीं है कि जीका वायरस ने वहां दस्तक दे दी है। राज्य में जीका वायरस के 14 मामले सामने आ चुके हैं। केरल सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। हालात पर नजर रखने और राज्य सरकार की मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने भी विशेषज्ञों की एक भेजी है।

राज्य सरकार ने कहा कि गुरुवार को 24 साल की एक गर्भवती महिला में इसका पहला मामले सामने आया था। इसके बाद 19 सैंपल जांच के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआइवी) भेजे गए थे। शुक्रवार को इनमें से 13 और लोगों के जीका वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'केरल से जीका के कुछ मामले आए हैं। हालात पर नजर रखने और राज्य सरकार को सहयोग देने के लिए छह सदस्यीय दल को वहां भेजा गया है। इनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, मच्छर जनित रोगों के विशेषज्ञ और एम्स के विशेषज्ञ शामिल हैं।' मच्छर के काटने से यह वायरस फैलता है। इसके लक्षण डेंगू की तरह हैं जिनमें बुखार, त्वचा पर चकत्ते और जोड़ों में दर्द होना शामिल है।

कोरोना में माता-पिता को खोने वालों को नहीं देनी होगी पंजीयन फीस

राहत

जासं, कानपुर : कोरोना संक्रमण काल में बहुत लोगों ने अपने माता-पिता को खोया है। ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान आगे आया है। उसने अगले एक वर्ष तक संस्थान में पहली बार एक्जीक्यूटिव फर्स्ट लेवल में प्रवेश लेने के समय दिए जाने वाले पंजीयन शुल्क को इन बच्चों के लिए माफ कर दिया है। अपने अभिभावकों को खो चुके जो भी छात्र-छात्राएं इस एक्जीक्यूटिव फर्स्ट लेवल में 31 मार्च, 2022 तक प्रवेश लेंगे, उन्हें पंजीयन शुल्क के 9500 रुपये नहीं देने होंगे।

कोरोना की दूसरी लहर में शायद ही कोई ऐसा होगा, जिसके किसी परिचित, स्वजन या रिश्तेदार का निधन न हुआ हो। इसके बीच बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं, जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने अभिभावकों को खो दिया है। एक तरफ उन्हें माता-पिता खोने का कष्ट है, वहीं उनकी पढ़ाई भी संकट में है। इसे देखते हुए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने ऐसे सभी बच्चों को प्रवेश के समय लगने वाले पंजीयन शुल्क से छूट दे दी है। यह सुविधा उन सभी बच्चों के लिए हैं, जिनके अभिभावक, कानूनी अभिभावक या गोद लेने वालों का कोरोना में निधन हो गया हो। संस्थान पहले ही इंट्रेंस टेस्ट की कोचिंग व किताबों के खर्चों को ऐसे बच्चों के लिए माफ कर चुका है। संस्थान के पूर्व चेयरमैन गोपेश साहू के मुताबिक यह सुविधा चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक जारी रहेगी।

कोलकाता के फर्जी वैक्सीन कैंप मामले की ईडी ने भी शुरू की जांच

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

राज्य की जांच में हस्तक्षेप नहीं करेगा हाई कोर्ट

उधर, शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि वह फर्जी वैक्सीन कैंप मामले में राज्य की जांच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायमूर्ति इंद्रप्रसन्न मुखर्जी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने सभी जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि अदालत को नहीं लगता कि इस समय मामले की सीबीआइ जांच की कोई जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो इस मामले पर सीबीआइ विचार करेगी।

कोलकाता में फर्जी कोरोना वैक्सीन कैंप आयोजित करने के मामले की अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी शुक्रवार से आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। वहीं, दूसरी ओर कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि मामले की सीबीआइ जांच की अभी जरूरत नहीं है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों कोलकाता में दो वैक्सीन कैंप आयोजित किए गए थे। इनमें जब कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवाई तो उसके बाद उन्हें उससे संबंधित मैसेज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नहीं मिले। ऐसे में शंका होने पर पड़ताल की गई तो पता चला कि दोनों कैंप फर्जी हैं। इस मामले में खुद को आइएएस अधिकारी व कोलकाता नगर निगम का संयुक्त आयुक्त बताने वाले मुख्य आरोपित देबांजन देब को कोलकाता पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक नौ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शुक्रवार को बैंकशाल कोर्ट में मुख्य आरोपित देबांजन देब तथा अन्य आरोपितों को पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने देबांजन को 23 जुलाई तक तथा अन्य को 16 जुलाई तक जेल भेजने का निर्देश दिया।

देबांजन को हिरासत में लेना चाहती है ईडी: इस मामले में ईडी ने शुक्रवार को कुल छह एफआइआर दर्ज की हैं। इसमें एक एफआइआर फर्जी वैक्सीन कैंप मामले में तथा पांच एफआइआर कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रेमडेसिविर टैबलेट तथा आक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर दर्ज की गई हैं। बताया जाता है कि ईडी मुख्य आरोपित देबांजन को अपनी हिरासत में लेना चाहती है।

जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी पुलिस: एडवोकेट जनरल किशोर दत्त ने कोर्ट में सवाल किया कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ मुख्य आरोपित देबांजन के बाडीगार्ड की तस्वीर है। क्या तब राज्यपाल को कठघरे में खड़ा किया जाएगा? वैक्सीन कैंप में प्रधानमंत्री के साथ एक महिला की तस्वीर थी। क्या तब प्रधानमंत्री पर कार्रवाई की जाएगी? क्या यही हमारे देश का कानून है?



मैक्लोडगंज में नन्हे अमित के साथ थाना प्रभारी विपिन कुमार। जागरण

पांच साल का अमित कोरोना के खिलाफ बना 'प्रहरी'

जासं धर्मशाला : उसकी उम्र भले ही पांच साल है, लेकिन उसकी सोच ने पढ़े-लिखे लोगों को जिंदगी का सबक सिखा दिया है। हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैक्लोडगंज के निकट भागसूनाग में गुब्बारे बेचने वाले दंपती का पांच वर्षीय बेटा अमित हाथ में प्लास्टिक का डंडा लिए बिना मास्क घूम रहे पर्यटकों से पूछता है कि आपका मास्क कहां है? कई लोगों ने उसके जज्बे को सलाम किया तो कुछ नाराज भी हुए। कांगड़ा जिला पुलिस ने उसे कोविड जागरूकता अभियान का प्रहरी बनाया है। पुलिस इस बच्चे के फोटोयुक्त जागरूकता पोस्टर आसपास के पर्यटन स्थलों में लगाएगी।

अमृतसर में कोरोना से लड़ने वाला वायरस बनाने की तैयारी, आइसीएमआर से मांगी इजाजत

नितिन धीमान, अमृतसर

दुनिया भर में कोरोना पर रिसर्च जारी है। कोरोना वैक्सीन भी इसी रिसर्च का एक अहम हिस्सा है। अमृतसर स्थित सरकारी मेडिकल कालेज में ऐसी ही एक रिसर्च चल रही है। यहां वायरस लाइक पार्टिकल (वीएलपी) बनाने की तैयारी की जा रही है। कोरोना से लड़ने में सक्षम वीएलपी एक कृत्रिम वायरस है, लेकिन इनमें जेनेटिक मेटीरियल नहीं होते। इसलिए यह इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, लेकिन यह इंसान के शरीर में प्रवेश होने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय कर देता है।

दरअसल, कोरोना वायरस में डीआक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (डीएनए) व राइबोन्यूक्लिक एसिड (आरएनए) नामक जेनेटिक मेटीरियल होता है। सिर्फ कोरोना ही नहीं, बल्कि कोई भी वायरस बिना जेनेटिक मेटीरियल के अधूरा है। यदि ये मेटीरियल वायरस में न हो तो यह इंसान को क्षति नहीं पहुंचा सकता। अमृतसर मेडिकल कालेज स्थित वायरल डिजीज रिसर्च लैब में वीपीएल पर शोध करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) से स्वीकृति मांगी गई है। लैब के प्रोफेसरों ने सारा स्ट्रक्चर तैयार कर आइसीएमआर को भेजा है।

दिल्ली में होगा क्लिनिकल ट्रायल

कोरोना वायरस की तरह दिखने वाले वीएलपी से दुनिया भर में कई वैक्सीन तैयार की जा रही हैं। कई वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में पास भी हो चुकी हैं। कोविशील्ड व कोवैक्सीन भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। वीएलपी के रूप में बूस्टर डोज लगाकर शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित की जाती है। अमृतसर में बनने वाले वीएलपी के क्लिनिकल ट्रायल दिल्ली में होंगे। इन्हें आइसीएमआर ही करवाएगा।



जीवन रक्षक है टीका। फाइल

कैसे बनेगी एंटीबॉडी: मेडिकल कालेज में तैयार किए जाने वाले वीएलपी की संरचना एवं आकार कोरोना वायरस जैसे ही होंगे। जैसे ही वैक्सीन के जरिए इन्हें मानव शरीर में भेजा जाएगा तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को आभास होगा कि कोरोना वायरस का अटैक हुआ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता सक्रिय हो जाएगी और शरीर वीएलपी से लड़ना शुरू कर देगा। चूंकि वीएलपी में डीएनए व आरएनए जैसे जेनेटिक मेटीरियल नहीं होंगे, इसलिए इसका दुष्प्रभाव मानव शरीर पर नहीं पड़ेगा, पर इस वायरस से लड़ने के लिए बड़ी मात्रा में एंटीबाडी तैयार हो जाएगी।

कोरोना के नए वैरिएंट्स के निदान में भी सहायक: अहम बात यह है कि निकट भविष्य में यदि कोरोना के कई वैरिएंट्स सक्रिय होंगे तब भी कृत्रिम वीएलपी की मदद से इनका निदान किया जा सकेगा। माइक्रोबायोलाजी विभाग के प्रोफेसर डा. केडी सिंह का कहना है कि टीम आश्वस्त है कि वे वीएलपी बना सकते हैं।

शताब्दी वर्ष तक गांव-गांव लगेंगी संघ की शाखाएं

अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक

राजीव द्विवेदी, चित्रकूट

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को 2025 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। संघ के शीर्ष नेतृत्व की कोशिश है कि शताब्दी वर्ष से पहले ही शाखाओं को ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचा दिया जाए। अभी न्याय पंचायत स्तर तक संचालित हो रहीं संघ की शाखाओं में प्रमुखता से सनातनियों का ही जुड़ाव है। अब तैयारी यह भी है कि संघ की विचारधारा को व्यापक फलक देने के लिए सभी वर्गों को शाखाओं से जोड़ा जाएगा। अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में कार्ययोजना पर विमर्श होने के बाद इसको अमल में लाने के जतन भी शुरू हो जाएंगे।

संघ की स्थापना 27 सितंबर, 1925 को हुई थी। शताब्दी वर्ष तक संघ को गांव-गांव पहुंचाने के प्रयास शुरू हुए हैं। प्रांत प्रचारक बैठक के बाद देश भर में संकल्प को पूरा करने का कार्य शुरू भी हो चुका है। मोदी सरकार बनने से पहले संघ का जो दायरा पूर्वोत्तर व दक्षिण में सीमित था, अब उसे ऊर्जा मिली है। असम और त्रिपुरा के बाद बंगाल में संघ द्वारा तैयार जमीन पर भाजपा मजबूत संगठन खड़ा करने में कामयाब भी रही। बंगाल में अपने कार्यक्रमों की सफलता से संतुष्ट संघ ने अब शताब्दी वर्ष तक देश के हर गांव में शाखा संचालन का संकल्प लिया है। प्रांत प्रचारक बैठक में कार्ययोजना पर विमर्श के बाद उस पर अमल शुरू होगा।

अब तक न्याय पंचायत स्तर तक लगने वाली संघ की शाखाओं को ग्राम पंचायत तक ले जाने की तैयारी है। सरसंघचालक की मंशानुरूप अब शाखाओं में हिंदू ही नहीं, बल्कि हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का प्रयास होगा, जिससे वहां होने वाली शारीरिक क्रियाओं के साथ बौद्धिक से राष्ट्र के प्रति समर्पण व निष्ठाभाव का विकास किया जा सके। संघ-मंडली और उसके बाद मिलन शाखा से शुरुआत करके प्रातः और संध्या के कुछ अंतराल के बाद रात्रि शाखा संचालन का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इस प्रयास को हिंदू राष्ट्रवादी संगठन की छवि के दायरे से निकलकर राष्ट्रवादी संगठन बनने की कोशिश भी माना जा रहा है।

भाजपा को मिलेगी मजबूत जमीन: संघ को भले सांस्कृतिक संगठन कहा गया है पर उससे ऊर्जा भाजपा को ही मिलती रही है। 1975 के आपातकाल में प्रतिबंध लगने के बाद संगठन का सियासत में महत्व बढ़ गया। प्रतिबंध हटने के करीब 25 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई। 15 वर्ष बाद भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार भले बनाई पर संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व उसमें नहीं था। संघ के दायरा बढ़ाने की कोशिश को 2024 के लोकसभा चुनाव तक हर राज्य में भाजपा की मजबूत जमीन तैयार करना माना जा रहा है।



आरोग्यधाम में शुक्रवार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक शुरू हो गई जागरण

इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय होंगे संघ के स्वयंसेवक

जासं, चित्रकूट : अभी तक मीडिया में बात रखने को लेकर बेहद सतर्क रहने वाले संघ के स्वयंसेवक जल्द ही इंटरनेट पर भी सक्रिय दिखेंगे। अपने कार्यक्रमों के जरिये लोगों तक पहुंच बनाने वाले संघ के बड़े पदाधिकारी तो इंटरनेट मीडिया पर हैं पर अब शाखा स्तर तक के स्वयंसेवकों को भी इंटरनेट मीडिया से जुड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। भाजपा के आइटी सेल की तर्ज पर संघ में भी उच्च तकनीकी डिजिटल सूचना संवाद केंद्र की स्थापना होगी। राष्ट्रीय स्तर से गांवों तक संघ अपने विचारों का प्रसार शाखाओं या फिर सेवा कार्यों के जरिए करता रहा है। अखिल भारतीय कार्यकारिणी अधिकारी और सदस्यों में कुछ लोग इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर सक्रिय हैं। 50 से ज्यादा संगठन जो संघ की विचारधारा को आधार मानकर सक्रिय हैं। यह पहली बार होगा जबकि स्वयंसेवक इंटरनेट मीडिया माध्यमों से जुड़कर संघ की विचारधारा को खुला मंच देंगे। वह तर्कों के साथ अपनी बात रखकर लोगों की भ्रांतियां दूर करेंगे।

अमित शाह के फोन के बाद हरकत में आया गुजरात का स्वास्थ्य विभाग

जागरण संवाददाता, अहमदाबाद

▸ गृह मंत्री ने फोन कर गांधीनगर के हैजा पीड़ितों के स्वास्थ्य की ली जानकारी

▸ अब तक पांच लोगों की मौत, उल्टी-दस्त के लगभग सवा सौ मामले मिले

गांधीनगर के कलोल इलाके में फैले हैजे (कालरा) से अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है। उल्टी-दस्त के लगभग सवा सौ मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को फोन कर अधिकारियों से कालरा पीड़ितों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके बाद अधिकारी हरकत में आए और पीड़ितों के उपचार व स्वच्छ पानी की व्यवस्था का जायजा लेने खुद मौके पर पहुंचे।

गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि उनके गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले कलोल के कुछ इलाकों में कालरा के केस मिलने की जानकारी मिली है। इस संबंध में जिला कलक्टर व स्वास्थ्य अधिकारी से बात कर उन्होंने इसे रोकने तथा प्रभावित लोगों के उपचार की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कलोल के कुछ इलाकों में लंबे समय से गंदे व बदबूदार पानी की शिकायत की जा रही थी। मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने कलोल नगर पालिका के दो किमी क्षेत्र को हैजाग्रस्त घोषित कर दिया है। पीड़ितों के उपचार के लिए गांधीनगर सिविल अस्पताल में विशेष वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा क्षेत्र की चाय, पान, मांस की दुकानों को बंद करा दिया गया है। पानी के पाउच बेचने पर भी रोक लगा दी गई है। पानी के 303 नमूने लिए गए हैं।



गृह क्षेत्र पर भी शाह की नजर। फाइल फोटो

प्रवासी श्रमिकों की पीड़ा से संघ आहत

जागरण संवाददाता, चित्रकूट

▸ चित्रकूट में शुरू हुई आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की चार दिवसीय बैठक, श्रमिकों के रोजगार और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए दिखी फिक्रमंदी

कोरोना काल में दर बदर हुए प्रवासी श्रमिकों के लिए भले सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं आई हों, पर उनको हुई तकलीफों की टीस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को अब भी है। अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की चार दिवसीय बैठक के पहले दिन शुक्रवार को प्रवासी श्रमिकों के रोजगार उनके बच्चों की शिक्षा के लिए और प्रयास और बढ़ाने पर बात की गई। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले बचाव और उपचार के बंदोबस्त कर लिए जाने पर जोर दिया गया।

प्रभु श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान (डीआरआइ) के प्रकल्प आरोग्यधाम सेमिनार हाल में बैठक की शुरुआत सरसंघचालक मोहन भागवत ने सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के साथ की। बैठक संघ प्रमुख के बौद्धिक के दौरान पीड़ा झलकी कि लाकडाउन के दौरान रोजी-रोटी का साधन और आशियाना छोड़कर प्रवासी श्रमिकों को कष्ट सहते हुए अपने गांव व कस्बों की तरफ पैदल ही चलना पड़ा। महामारी की जटिलता को समझते हुए वह बिना हो-हल्ला किए शांति से चले गए। उनके कल्याण के उपाय किए गए पर अब भी उनके रोजगार की चिंता करने की जरूरत, उनके बच्चों की शिक्षा का बंदोबस्त करना जरूरी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कोरोना से जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनको सांत्वना देने के साथ मुश्किल वक्त में स्वयंसेवकों को उनके साथ खड़ा भी रहना होगा। सरकार्यवाह ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच तैयार रहने की अपेक्षा करते हुए कहा कि प्रार्थना करनी चाहिए कि मुश्किल घड़ी न आए, अगर आए भी तो उसकी पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। उन्होंने अपेक्षा की कि बचाव के बंदोबस्त के साथ उपचार की तैयारी और उसके लिए प्रशिक्षण भी करते रहना होगा। कार्यकारिणी सदस्यों में भय्या जी जोशी व सुरेश सोनी ने संगठन के बाधित व्यक्ति निर्माण के कार्यों को फिर से शुरू किए जाने पर विमर्श किया। बैठक में सरसंघचालक व सरकार्यवाह के साथ सह सरकार्यवाह डा.कृष्ण गोपाल के अलावा सातों विभागों के प्रमुख व सह प्रमुख के अलावा शामिल हुए।

ट्विटर को झटका... राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कू एप पर किया पदार्पण

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

ट्विटर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मेड इन इंडिया माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट कू से जुड़ने का फैसला किया है। संघ अब अपने सभी बड़े फैसले और अपेक्षित जानकारियां कू के माध्यम से लोगों से उनकी अपनी भाषा में साझा करेगा। आरएसएस. ओआरजी संगठन का अधिकृत अकाउंट है। कू में संघ का प्रवेश इसलिए भी ट्विटर के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि संघ के दुनियाभर में करोड़ों समर्थक हैं। पिछले कुछ महीनों से केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच ब्लू टिक समेत नए नियमों को लेकर काफी तनातनी चल रही थी।

यह है पूरा का मामला: कुछ दिनों पहले ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, सरसंघचालक मोहन भागवत समेत कई नेताओं के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया था। हालांकि, इस फैसले पर बवाल बढ़ने के बाद ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल पर दोबारा ब्लू टिक लगा दिया था। यहां तक की कंपनी ने पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ही कुछ समय के लिए ब्लाक कर दिया था। प्रसाद का ट्विटर अकाउंट करीब एक घंटे बंद रहा था। ट्विटर ने अपने इस कदम के पीछे अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कापीराइट एक्ट के उल्लंघन का हवाला दिया, साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी अपना अकाउंट ब्लाक करने के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी थी। ट्विटर की ओर से अलग-अलग कैटेगरी के अकाउंट को सत्यापित करने के बाद ब्लू टिक प्रदान किया जाता है। एक तरह से अधिकृत पहचान को जाहिर करता है। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक ट्विटर की बढ़ती मनमानियों की वजह से संघ ने कू से जुड़ने का फैसला किया है।

कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार की केंद्र में दस्तक

राज्य ब्यूरो, देहरादून

राह निकालने की कोशिश

कांवड़ यात्रा को लेकर अब उत्तराखंड सरकार केंद्र में दस्तक देने जा रही है। दरअसल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की कांवड़ यात्रा की तैयारियों को देखते हुए प्रदेश सरकार असमंजस में है। कारण यह कि अगर बाहर से कांवड़िये आए तो रोकना आसान नहीं होगा। ऐसे में कोशिश है कि केंद्र की मध्यस्थता में कोई सर्वमान्य हल निकाला जाए।

पहले करीब दो से ढाई करोड़ श्रद्धालु गंगाजल लेने हरिद्वार आते रहे हैं। बीते वर्ष कोरोना संक्रमण की पहली लहर के कारण कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी। इस वर्ष भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चारधाम यात्रा पर हाई कोर्ट के रोक लगाने के बाद सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी। इस बीच उत्तर उत्तर प्रदेश व हरियाणा सरकार ने कांवड़ यात्रा शुरू करने के संकेत दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोन पर भी वार्ता हुई। गुरुवार को धामी ने इस मसले पर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राय बनी कि पड़ोसी राज्यों के रुख और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बेहतर होगा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार से बात कर ली जाए। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व से इस मामले में समाधान निकालने का अनुरोध किया जाए। पुलिस व कांवड़ यात्रा से संबंधित विभागों को अपनी तैयारियां भी रखने को कहा गया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय नेतृत्व के सामने इस मसले को रखेंगे।

This PDF was originally uploaded To The English Newspaper L-- Banna SA (https://t.me/English_Newspaper_L_Banna)one else Backup chennal @NEWS_Backup_L_Banna

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बढ़ेंगी सात सीटें

परिसीमन ▶ 2011 की जनगणना के आधार पर ही होगा परिसीमन, हो जाएंगी कुल 114 सीटें

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आए परिसीमन आयोग ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर ही होगा। परिसीमन के तहत जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मौजूदा 107 सीटों को बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव है। इसमें गुलाम कश्मीर की 24 सीटें भी शामिल हैं। इसके अलावा कुछ निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण भी होना है। अलबत्ता, भौगोलिक परिस्थिति, लोगों की सरकार तक पहुंच, संचार माध्यम समेत समय अन्य मापदंडों को भी ध्यान में रखा जाएगा। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। इसका ड्राफ्ट जल्द ही लोगों के बीच लाया जाएगा ताकि वह आपत्तियां और सुझाव दे सकें। इसके बाद आयोग एसोसिएट सदस्यों के साथ विचार-विमर्श कर फाइनल ड्राफ्ट जारी करेगा।

आयोग का पहला दौरा : जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों समेत विभिन्न वर्गों के लोगों की राय लेने के लिए जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई की अध्यक्षता वाला परिसीमन आयोग पहली बार चार दिवसीय दौरे पर आया था। शुक्रवार को दौरे का आखिरी दिन था। आयोग के सदस्यों ने पहले कश्मीर और फिर जम्मू संभाग के लोगों की राय ली है। दौरे के आखिरी दिन आयोग के सदस्यों ने जम्मू में प्रेस कांफ्रेंस कर कई आशंकाओं को दूर किया। आयोग के सदस्य और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा में कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं को फिर निर्धारित करना एक जटिल मुद्दा है और यह सिर्फ गणित नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों, समाज के विभिन्न वर्गों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ श्रीनगर, पहलगाम, किश्तवाड़ और जम्मू में मुलाकात की है। प्रतिनिधियों ने काफी उत्साह दिखाया। दूरदराज के इलाकों से सफर कर कई लोग मिलने पहुंचे थे। आयोग ड्राफ्ट बनाकर लोगों के बीच ले जाएगा।

▶ चार दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली लौटने से पहले परिसीमन आयोग ने किया स्पष्ट

▶ सुझाव और आपत्तियों के लिए जनता के बीच जल्द लाया जाएगा इससे जुड़ा ड्राफ्ट



जम्मू में शुक्रवार को परिसीमन आयोग के दौरे के अंतिम दिन आयोग के सदस्य (बाएं से) मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई, और जम्मू-कश्मीर के चुनाव आयुक्त केके शर्मा ने प्रेसवार्ता की। जागरण

यह है आयोग का स्वरूप

परिसीमन आयोग की अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हैं। इसमें देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू-कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त केके शर्मा सदस्य हैं। जम्मू-कश्मीर से लोकसभा के पांच सदस्य आयोग के एसोसिएट सदस्य हैं। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। इस परिसीमन पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

अब 20 जिले : चंद्रा ने कहा कि पिछली जनगणना के दौरान जम्मू-कश्मीर में जिलों की संख्या 12 थी जो अब बढ़कर 20 हो गई है। तहसीलों की संख्या भी 58 से 270 हो गई है। पटवार हलकों पर प्रशासनिक काम अति व्यापी हो गया है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। 1995 में हुए परिसीमन में कठिन पहाड़ी इलाकों के मापदंड शामिल नहीं किए गए थे। हालांकि, परिसीमन का मुख्य मापदंड जनसंख्या होती है, लेकिन अब क्षेत्र, भौगोलिक परिस्थिति और संचार सुविधा भी इसमें शामिल है। जम्मू-कश्मीर में 1991 में कोई जनगणना नहीं हुई। जम्मू-कश्मीर में 1981 की जनगणना के आधार पर 1995 में परिसीमन किया गया था।

आयोग फिर करेगा दौरा, नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी: मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि हमने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर स्तर के एक अधिकारी को आयोग के साथ नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। जो लोग नहीं मिल पाए हैं या अभी भी सुझाव देना चाहते हैं, वे नोडल अधिकारी या आयोग के साथ सीधा संपर्क कर सकते है। आयोग का यह दौरा आखिरी नहीं है।

गुलाम कश्मीर की सीटों पर यह कहा: गुलाम कश्मीर के रिफ्यूजियों की 24 सीटों में कुछ सीटों को आरक्षित करने की मांग पर सुशील चंद्रा ने कहा कि हमें जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के तहत हमें जो जनादेश मिला है, हम वही कर रहे हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोरोना से उपजे हालात के कारण आयोग पहले दौरा नहीं कर सका। सरकार ने आयोग के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाया है। उम्मीद है कि हम अपना कार्य निर्धारित समय में पूरा कर लेंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की तरफ से परिसीमन की प्रक्रिया को योजनाबद्ध बताने का आरोप लगाने पर आयोग की अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई ने कहा कि परिसीमन पूरी तरह से पारदर्शी होगा।

अब गैर मुमकिन खड्ड की भी हो पाएगी खरीद-फरोख्त

ललित कुमार, जम्मू

जम्मू-कश्मीर में अब गैर मुमकिन खड्ड की खरीद-फरोख्त भी हो पाएगी। जम्मू-कश्मीर में पिछले करीब डेढ़ दशक से इन खड्ड की खरीद-फरोख्त को लेकर विवाद चल रहा था और पांच साल पूर्व जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने इन जमीनों की फर्द (राजस्व रिकार्ड) जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक तो हालांकि चार साल पहले हटा ली गई थी, लेकिन जम्मू-कश्मीर के पुराने जमीन कानून के तहत यह प्रतिबंध जारी रहा। अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद पुराना जमीन कानून रद होने व नए नियम बनने से खड्ड वाली जमीन के मालिकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि नए कानून में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि गैर मुमकिन खड्ड की फर्द जारी नहीं हो सकती।

जम्मू-कश्मीर के जमीन कानून 2007 के तहत गैर मुमकिन खड्ड की फर्द जारी करने पर रोक थी। इस दौरान सरकारें बदलती रहीं और इसमें बदलाव भी होता रहा। इससे इन खड्ड वाली जमीनों के मालिकों को अपनी ही जमीन बेचने को लेकर भटकना पड़ रहा था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार ने पिछले कानून को खारिज करते हुए 26 अक्टूबर 2020 को नए नियम बनाए। इसके तहत घास चराई व ईंधन उत्पन्न करने वाली जमीन समेत सरकार की ओर से अधिसूचित कई तरह की जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई गई है, लेकिन इन श्रेणियों में गैर मुमकिन खड्ड का कहीं जिक्र नहीं है।

हाई कोर्ट ने 2016 में लगाई थी रोक : जल स्रोतों पर कब्जे और उन पर निर्माण की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने की मांग को लेकर जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी। 2016 को कोर्ट ने गैर मुमकिन खड्ड का राजस्व रिकार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी।

वाटर पालिसी 2017 के तहत ही मिलेगी इजाजत

जम्मू-कश्मीर के नए नियमों के तहत गैर-मुमकिन खड्ड की खरीद-फरोख्त पर चाहे प्रतिबंध न हो, लेकिन वाटर पालिसी 2017 के तहत कई नियम व शर्तें निर्धारित की गई हैं। अगर कोई खड्ड पानी के बहाव के रास्ते में आती होगी तो उस पर निर्माण की अनुमति नहीं मिलेगी।

गैर-मुमकिन खड्ड : ऐसी बंजर जमीन जहां कभी खेतीबाड़ी नहीं हुई। वो जमीन जो न तो उपज के काम आती है और न ही मवेशियों के खाने के लिए वहां किसी तरह का चारा पैदा होता है। ऐसे क्षेत्र जो किसी जमाने में बरसाती पानी के जाने का रास्ता रहे हो।

न्यूज गैलरी

कल्याण सिंह की तबीयत पहले से बेहतर

लखनऊ : संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआइ, लखनऊ) में भर्ती उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तबीयत पहले से बेहतर है। शुक्रवार को संस्थान के निदेशक प्रो. आरके धीमन ने बताया कि उनकी तबीयत में सुधार दिख रहा है। वह अपने आप को पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्हें क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में रखा गया है। (जासं)

डीएनए टेस्ट को तैयार नेगी, सुबूत मिले तो भरण पोषण देंगे

अल्मोड़ा : दुष्कर्म के आरोपों से घिरे अल्मोड़ा के द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में कहा- 'मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं। डीएनए टेस्ट को भी तैयार हूं। मेरे ऊपर दुष्कर्म का मुकदमा है। डीएनए टेस्ट में कुछ होना ही नहीं है। अगर कोई बात होती भी है तो भरण पोषण देंगे।' (जासं)

नेग न देने पर किन्नर ने तीन माह की बच्ची को मार डाला

मुंबई : दक्षिण मुंबई के कफ परेड इलाके में कुछ पैसे, नारियल और साड़ी नहीं देने पर दो लोगों ने तीन माह की बच्ची का अपहरण कर लिया और एक नाले में फेंक दिया। इससे बच्ची की मौत हो गई। अपराध में शामिल दो लोगों में एक किन्नर है। (प्रेट्र)

अधिकारियों को बुलाने के चलन से सुप्रीम कोर्ट असहमत

नई दिल्ली : देश के कुछ हाई कोर्टों द्वारा तुरंत अधिकारियों को तलब करने के चलन के प्रति असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अदालत का सम्मान अर्जित किया हुआ होना चाहिए न कि मांगा हुआ और यह अधिकारियों को समन करने से नहीं बढ़ता। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि जजों को अपनी सीमा पता होनी चाहिए। उनमें विनम्रता होनी चाहिए। सम्राट की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। (प्रेट्र)

मप्र में लव जिहाद, राकेश बन यौन शोषण करता रहा रफी

जबलपुर : मध्य प्रदेश के सतना जिले में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें मोहम्मद रफी नामक व्यक्ति अपना नाम राकेश कुशवाहा बताकर एक हिंदू महिला का 15 साल तक यौन शोषण करता रहा। पुलिस ने मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता कानून के तहत आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। (नईदुनिया)

घुसपैठ की फिराक में 200 से अधिक आतंकी, बड़े हमलों की साजिश

गगन कोहली, राजौरी

जम्मू-कश्मीर में हालात बिगाड़ने के लिए पाक सेना अब प्रशिक्षित आतंकियों को भारत में धकेलने की कोशिश कर रही है। नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार 200 से अधिक आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। वहीं गुलाम कश्मीर में आतंकी शिविरों में गुमराह युवाओं को तेजी से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कश्मीर में आतंकरोधी अभियान तेज होने के बाद पाकिस्तान अब घुसपैठ राजौरी-पुंछ से करवाने के लगातार प्रयास कर रहा है।

29 जून को राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर के दादल से आतंकवादियों का एक दल भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ। आठ जुलाई को घुसपैठ करके भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए आतंकियों की सेना के जवानों की मुठभेड़ हुई, जिसमें दो पाक आतंकी मारे गए। सेना के दो जवान भी शहीद हो गए। दो दिन पहले नौशहरा के कलाल क्षेत्र से घुसपैठ का प्रयास हुआ। भारतीय क्षेत्र के 300 मीटर अंदर आ चुके एक आतंकी को सेना के जवानों ने ढेर कर दिया। इस कार्रवाई में दो जवान घायल हो गए थे।

पाक सेना की अग्रिम चौकियों में डेरा डाले हैं आतंकी : सूत्रों का कहना है कि सीमा पार से भारतीय क्षेत्र में बड़े हमलों की साजिश रची जा रही है। इसके लिए प्रशिक्षित 200 से अधिक आतंकी भारतीय क्षेत्र में घुसने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। ये आतंकी इस समय पाक सेना की अग्रिम चौकियों में डेरा डाले हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि गुलाम कश्मीर में कई आतंकी प्रशिक्षण शिविर फिर से आरंभ हो चुके हैं। भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कई शिविर बंद हो चुके थे। इन शिविरों में पाक सेना के अधिकारी व आतंकी संगठनों के आका दौरा करके युवाओं को दिए जा रहे प्रशिक्षण की निगरानी कर रहे हैं।

हिजबुल मुजाहिदीन के चार आतंकियों के खिलाफ आरोप कर दिए गए हैं तय

जासं, नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से धन प्राप्त करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिलने पर आतंकी फंडिंग मामले में हिजबुल मुजाहिदीन के चार आतंकियों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। विशेष न्यायाधीश परवीन सिंह ने कहा कि आतंकी संगठन ने जम्मू कश्मीर प्रभावित राहत ट्रस्ट (जेकेएआरटी) के नाम से एक फ्रंटल संगठन बनाया था और ट्रस्ट का उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को धन देना था। इस मामले में हिजबुल कमांडर सैयद सलाहुद्दीन भी शामिल है। अदालत ने मुहम्मद शफी शाह, तालिब लाली, मुजफ्फर अहमद डार और मुश्ताक अहमद लोन के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की एक बड़ी साजिश रचने के आरोप तय किए। इन सभी पर यूएपीए की धारा 17 और 40, आतंकवादी संगठन का सदस्य होने के लिए यूएपीए की धारा-20 समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए गए हैं।

बांडीपोरा में लश्कर का आतंकी पकड़ा गया, कुलगाम में घेराबंदी तोड़ दो भागे

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा में लश्कर-ए-तैयबा के एक स्थानीय आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच, दक्षिण कश्मीर के रेडवनी (कुलगाम) में सुरक्षाबलों की घेराबंदी में फंसे दो आतंकी भाग गए। जानकारी के अनुसार, पुलिस को सुबह अपने तंत्र से पता चला कि हाजिन, बांडीपोरा में आतंकी एक टारगेट किलिंग को अंजाम देने वाले हैं। इसके लिए एक स्थानीय आतंकी को जिम्मा सौंपा गया है। इसके आधार पर पुलिस ने सेना की 13 राष्ट्रीय राइफल (आरआर) और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर कुछ खास जगहों पर नाके लगाए। गुंड जहांगीर इलाके में नाका पार्टी ने वहां से संदिग्धावस्था में गुजर रहे एक युवक को रोका। इस युवक ने खुद को फंसता देख नाका पार्टी पर कथित तौर पर फायर करने का भी प्रयास किया था। अलबत्ता, जवानों ने उसे कोई मौका दिए बगैर पकड़ लिया। उसके पास से एक पिस्तौल, मैगजीन व कुछ कारतूस मिले हैं। उसकी पहचान चंदरगीर हाजिन के रहने वाले मुजम्मिल शेख उर्फ अबू माविया के रूप में हुई है। वह कुछ माह पहले आतंकी बना था। इस बीच, गुरुवार को आधी रात के बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के सयुक्त कार्यदल पर रेडवनी कुलगाम में आतंकियों ने हमला किया। इसमें वह बच गए और उन्होंने उसी समय त्वरित कार्रवाई करते हुए आतंकियों को घेर लिया। करीब दो घंटे तक दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग होती रही। इसके बाद आतंकियों की तरफ से गोली चलना बंद हो गई।

अपनी परिसंपत्तियों के ऊपर ड्रोन की उड़ान पर नौसेना ने प्रतिबंध लगाया

कोच्चि, प्रेट्र : नौसेना ने शुक्रवार को नौसैनिक अड्डे, नौसैनिक इकाई और नौसैनिक परिसंपत्तियों के तीन किलोमीटर के दायरे में ड्रोन जैसे गैर पारंपरिक हवाई वस्तुओं के उड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस सिलसिले में जारी एक बयान में कहा गया है कि दूर से संचालित हवाई प्रणाली समेत किसी भी गैर पारंपरिक हवाई वस्तु को इस प्रतिबंध का उल्लंघन करते पाए जाने पर उसे नष्ट कर दिया जाएगा या भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत उसके संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले माह जम्मू में वायु सेना के शिविर पर ड्रोन हमले की पृष्ठभूमि में नौसेना ने यह फैसला लिया है। अधिकारियों का कहना है कि हमले में ड्रोन का उपयोग देश की सुरक्षा के लिए नई चुनौती उत्पन्न कर दी है।

आनलाइन नक्शा देने वाला देश का पहला राज्य बनेगा बिहार

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार में दूर-दराज के इलाके के रैयत अब घर बैठे अपने मौजे का नक्शा मंगा सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। भू-अभिलेख निदेशक जय सिंह ने शुक्रवार को बताया कि इसी महीने नक्शे की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इसके लिए डाक विभाग और बैंकों से करार हो गया है। सिक्योरिटी आडिट भी हो चुकी है। नक्शे की होम डिलीवरी करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा।

नक्शा प्राप्त करने के लिए भुगतान पेमेंट गेटवे के जरिए किया जाएगा। सभी प्रमुख बैंक इससे जुड़ गए हैं। बैंक अलग से चार्ज नहीं लेगा। स्पीड पोस्ट के जरिए नक्शे की डिलीवरी होगी। डाक विभाग ने पांच लाख बार कोड का आवंटन किया है। नक्शा भेजने के लिए कंटेनर बनाए गए हैं। इन पर बार कोड दर्ज रहेगा।

यह करना होगा : सबसे पहले भू-अभिलेख और परिमाप निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम पर क्लिक करना है। इसमें जिला, राजस्व थाना एवं मौजा चुनने का विकल्प आएगा। संबंधित सेलेक्शन के अनुरूप उस गांव का नक्शा एक या एक से अधिक शीट में दिखाई देगा। एक बार में अधिकतम पांच शीट सेलेक्ट किया जा सकता है। शुल्क शीट, संख्या और वजन के मुताबिक निर्धारित है। पेमेंट गेटवे में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआइ से भुगतान की सुविधा दी गई है।

शुल्क कितना लगेगा : अधिकतम पांच नक्शा रखने की क्षमता वाले एक कंटेनर की कीमत 35 रुपये तय है। तीन नक्शा समेत कंटेनर का डाक शुल्क सौ रुपये निर्धारित किया गया है। तीन से ज्यादा नक्शे का डाक शुल्क डेढ़ सौ रुपये है। परीक्षण के लिए बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग द्वारा कंटेनर की खरीद भी की जा चुकी है।

सदर अंचलों में प्लाटर मशीन

भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा शाहाबाद के चार जिलों को छोड़ कर बिहार के 34 जिलों के सदर अंचलों में प्लाटर लगाया गया है। इन प्लाटरों के जरिये दस साइज के बड़े पन्नों पर गांव का नक्शा प्रिंट किया जाता है। गुलजारबाग, सर्वेक्षण कार्यालय में पूरे सूबे का नक्शा मिलता है।

गढ़वाल विवि के पूर्व वीसी के आवास समेत 14 जगह सर्च

जागरण संवाददाता, देहरादून : छह निजी शिक्षण संस्थानों को नियमों को ताक पर रखकर सीटें बढ़ाने की अनुमति और कई पाठ्यक्रमों को संबद्धता देने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने शुक्रवार को उप्र में नोएडा, उत्तराखंड में श्रीनगर और देहरादून में 14 स्थानों पर सर्च किया। इनमें हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रो. जेएल कौल, उनके ओएसडी डीएस नेगी और पांच शिक्षण संस्थानों के संचालकों के आवास और कार्यालय शामिल हैं। इस दौरान तीन बैंक लाकरों का पता चला, जिनमें दो को सील कर दिया गया। सर्च में सीबीआइ को अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं।

मामला वर्ष 2014 से 2016 के मध्य का है। तब हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेएल कौल थे। आरोप है कि इस दौरान देहरादून में संचालित छह निजी शिक्षण संस्थानों में नियमों के विपरीत सीटें बढ़ाई गईं। इनमें कई ऐसे पाठ्यक्रमों को संबद्धता दी गई, जिनके लिए उनके पास न संसाधन थे और न ही मानकों के अनुरूप फैकल्टी। प्रकरण सामने आने के बाद 2017 में कुलपति कौल को हटा दिया गया।

वीरभद्र के अंतिम दर्शन को उमड़े लोग, जेपी नड्डा व राहुल गांधी भी पहुंचे

जागरण संवाददाता, शिमला

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन के लिए शुक्रवार को शिमला में लोग उमड़ पड़े। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शिमला पहुंचे। शनिवार को रामपुर में राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी।

गौरतलब है कि गुरुवार को वीरभद्र सिंह का निधन हो गया था। शुक्रवार को उनकी पार्थिव देह को शिमला स्थित आवास से रिज मैदान और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। बारिश के बावजूद प्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए लोग डटे रहे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रिज मैदान पर उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने अपना मार्गदर्शक खो दिया है। नेता प्रतिपक्ष रहते वीरभद्र से काफी कुछ सीखने को मिला। उनके जाने से मुझे व्यक्तिगत तौर पर क्षति हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मंत्रिमंडलीय सहयोगियों व भाजपा विधायकों ने रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन पहुंचे और वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने प्रतिभा सिंह व विक्रमादित्य सिंह से भी बात की।


स्वजन को सांत्वना देते भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। जागरण

सोनिया ने नामित किया चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल: कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नामित किया है। प्रतिनिधिमंडल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पवन बंसल, आनंद शर्मा व राजीव शुक्ला शामिल हैं। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव भी पहुंचे। वीरभद्र सिंह उनके मौसा थे।

विक्रमादित्य का आज होगा राजतिलक: शनिवार को अंतिम संस्कार से पहले वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य सिंह का रामपुर के राजमहल में राजतिलक होगा।

सर्वे

मुस्लिम महिलाओं के नौकरी व कारोबार शुरू करने का पति ही करते सबसे ज्यादा विरोध, मुस्लिम बहुल ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वे में आई हैरान करने वाली जानकारी

मुस्लिम महिलाएं आर्थिक पिछड़ेपन की शिकार

केएस मोबिन, रोहतक

उत्तर भारत के अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम महिलाएं सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा व आर्थिक भेदभाव का शिकार हैं। इन पर सबसे ज्यादा रोक-टोक पति ही करते हैं। घर से बाहर नौकरी पर जाने, किसी अन्य तरह की आर्थिक गतिविधि करने सबसे ज्यादा विरोध भी पति ही करते हैं। यह खास तौर पर समुदाय के उस वर्ग में हो रहा है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है। खुद मुस्लिम महिलाएं मानती हैं कि पिता की जायदाद में बेटी का हिस्सा नहीं होना भी बड़ी आर्थिक हिंसा है।

रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) के प्रोफेसर डा. रामफूल ओहल्याण के एक अध्ययन में ये तथ्य सामने आए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के एक प्रोजेक्ट के तहत प्रोफेसर ओहल्याण ने हरियाणा के नूंह, राजस्थान के नागौर और पंजाब के संगरूर की मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों को जानने के लिए सर्वे किया गया।


कभी तो बदलेगी तस्वीर। फाइल फोटो

परिवार नियोजन में भी पिछड़ रही मुस्लिम महिलाएं

डा. ओहल्याण बताते हैं कि शैक्षणिक-आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन की वजह से मुस्लिम महिलाएं परिवार नियोजन में भी पिछड़ रही हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक गर्भनिरोधक विधियों के इस्तेमाल में मुस्लिम महिलाएं राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं। अध्ययन में शामिल महिलाओं के परिवार में औसत सात सदस्य थे।

डा. ओहल्याण बताते हैं कि आर्थिक भेदभाव की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षिक प्राप्ति, सामाजिक गतिशीलता और रोजगार के अवसर भी मुस्लिम महिलाओं की पहुंच से दूर हैं। आर्थिक शोषण का बड़ा पहलू महिलाओं के रोजगार के अवसरों को नियंत्रित करने का है। ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए अधिक मुखर न हों। सर्वे में शामिल एक महिला तो यह भी कह देती है कि उन्हें लगता है कि मजहब में भी आर्थिक हिंसा कायम है। यदि वह हिंदू परिवार में जन्म लेती तो पिता की संपत्ति में भी हिस्सा मिलता।

18 से 50 वर्ष की 387 महिलाओं को किया गया शामिल: घरेलू आर्थिक परिस्थितियों को समझने के लिए 387 महिलाओं को अध्ययन में शामिल किया गया। 18 से 50 वर्ष की शादीशुदा महिलाओं से विभिन्न सवाल पूछे गए। इनकी औसत आयु 38 वर्ष रही। 77 फीसद महिलाएं एकल परिवार से रहीं, 23 फीसद संयुक्त परिवार की महिलाओं ने जवाब दिए। ज्यादातर के परिवार रोजगार के लिए श्रम और कृषि पर निर्भर थे।

एक ट्वीट से आम से खास हो गया उत्तराखंड का खोला गांव

अभिषेक राज, हल्द्वानी

समुद्र तल से आठ हजार की ऊंचाई पर बसा सीमांत पिथौरागढ़ का खोला गांव शुक्रवार को देखते ही देखते आम से खास हो गया। असल में यहां के युवाओं ने गांव के बाहर बने प्राकृतिक जलस्रोत को पत्थर व सीमेंट की मदद से स्वीमिंग पूल का रूप दे दिया है। यहीं पर वे खेती का काम निपटाकर तैराकी करते हैं। इसी स्वीमिंग पूल की फोटो गांव के ही नरेश धामी ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसे मंगलवार को उद्योगपति आनन्द महिंद्रा ने रीट्विट कर कैप्शन लिखा, 'इसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैंने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा। अब से यह मेरी ट्रैवल बकेट लिस्ट में शामिल है।' इसके बाद तो खोला गांव की फोटो 'स्वर्ग में स्वीमिंग पूल' हैशटैग के साथ ट्रेंड करने लगी। इसे शुक्रवार रात तक 7606 लाइक मिले।

तवाघाट से सात किमी की दूरी

धारचूला तहसील का खोला गांव तवाघाट से सात किमी दूर है। यहां तक सड़क से जाया जा सकता है। इसके बाद सीधी चढ़ाई है। यहीं से उच्च हिमालयी गांव दारमा व लिपुलेख भी जा सकते हैं। गांव के स्वामी वीरेंद्रानन्द व दुर्गा सिंह धामी बताते हैं कि आबादी करीब एक हजार है। गांव के अधिकतर युवा बाहर ही काम करते हैं। यहां जो हैं वे खेती में रमे हैं। उन्होंने ही खुद पहल कर गांव के बाहर स्वीमिंग पूल तैयार किया है।

परिवहन और संचार सेवा से वंचित खोला गांव

सीमांत का खोला गांव आज भी परिवहन, संचार और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यही कारण है कि अधिकतर युवा यहां से पलायन कर चुके हैं।

एसीबी ने चार जुलाई को ही पुलिस को सौंप दिए थे दस्तावेज

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि जीपी सिंह के घर से मिले दस्तावेज से पता चलता है कि राज्य सरकार के प्रति घृणा पैदा करना और धार्मिक सौहार्द को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। एसीबी को डायरी और पेन ड्राइव के रूप में मिले दस्तावेज से सरकार विरोधी गतिविधियों के साफ संकेत मिले हैं। एसीबी ने दस्तावेज का ब्योरा चार जुलाई को ही कोतवाली पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने कार्रवाई के पहले उनका परीक्षण किया। उसके बाद छापेमारी में शामिल अधिकारियों के बयान लिए। बयानों और दस्तावेज के आधार पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया।

This PDF was originally uploaded To The English Newspaper L-- Banna SA (https://t.me/English_Newspaper_L_Banna)one else Backup chennal @NEWS_Backup_L_Banna

राष्ट्रीय संस्करण
शनिवार 10 जुलाई, 2021
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

4जी डाउनलोडिंग स्पीड में रिलायंस जियो फिर अव्वल

नई दिल्ली : 4जी इंटरनेट सेग्मेंट में रिलायंस जियो लगातार अव्वल बनी हुई है। 21.9 मेगाबिट प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) की डाउनलोडिंग स्पीड के साथ जून में भी कंपनी इस चार्ट में सबसे ऊपर रही। टेलीकॉम नियामक ट्राई के मुताबिक, इस मामले में जियो की नजदीकी प्रतिद्वंद्वी वोडाफोन आइडिया रही, जिसकी औसत डाउनलोडिंग स्पीड 6.5 एमबीपीएस पाई गई। एयरटेल इस मामले में सबसे पीछे है। कंपनी की औसत डाउनलोडिंग स्पीड पांच एमबीपीएस रही। (प्रेट्र)

अगले पांच साल में हम किसानों के फायदे के साथ-साथ सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। उत्पादकता बढ़ाने और अच्छी गुणवत्ता के बीज इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
– निधि खरे, एडिशनल सेक्रेटरी (कंज्यूमर अफेयर्स)



सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल
52,386.19	15,689.80	₹46,844	₹67,465	₹74.64	$ 74.92
182.75	38.10	₹451	₹559	₹00	

एक नजर में

ब्रिटेन की कंपनियों को बीमा क्षेत्र में निवेश का न्योता

नई दिल्ली: भारत ने ब्रिटेन की कंपनियों को बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही, ब्रिटेन ने भारतीय कंपनियों के लिए लंदन शेयर बाजार में सीधे सूचीबद्ध होने की पेशकश की है। भारत ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74 फीसद कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने कंपनियों को घरेलू बाजार में सूचीबद्ध हुए बिना विदेश में सूचीबद्ध होने की अनुमति भी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच गुरुवार देर शाम वर्चुअल प्लेटफार्म पर इंडिया-यूके फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग की पहली बैठक हुई। वित्तीय क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अक्टूबर, 2020 में इसे स्थापित किया गया था। (प्रेट्र)

निवेशकों के हितों की रक्षा करेंगे बीएसई, एनएसई

मुंबई: घरेलू शेयर बाजारों एनएसई और बीएसई ने सूचीबद्ध कंपनियों के इंसाल्वेंसी मामलों में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ऐसे मामले में निवेशकों को आगाह किया जाएगा और कंपनी से जुड़ी सभी जानकारियां उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी। दोनों शेयर बाजारों ने अपने बयान में कहा, 'हाल में देखा गया है कि दिवालिया मामलों में कंपनियों की डीलिस्टिंग या मौजूदा इक्विटी शेयरों के राइट ऑफ/कैंसिलेशन के मामलों में मौजूदा शेयरधारकों का ध्यान नहीं रखा जाता है। (आइएएनएस)

दिसंबर तक काम करने लगेगा लैंड बैंक सिस्टम

नई दिल्ली: इंडस्ट्रियल लैंड बैंक सिस्टम को 17 राज्यों में उद्योग आधारित जीआइएस सिस्टम से जोड़ दिया गया है। दिसंबर के आखिर तक इसे पूरे देश में एकीकृत कर दिया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को यह बात कही। इस सिस्टम में जीआइएस आधारित पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें कनेक्टिविटी, प्राकृतिक संसाधन, खाली प्लाट से जुड़ी सूचनाओं समेत औद्योगिक इन्फ्रा से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध कराई जाती हैं। (प्रेट्र)

तेज टीकाकरण और हेल्थ इन्फ्रा से ही निकलेगी रिकवरी की राह

सितंबर में त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले 67 करोड़ डोज लगने का अनुमान

मंत्रालय ने कहा

- चालू वित्त वर्ष में केंद्र की वित्तीय स्थिति पिछले साल से काफी मजबूत
- अप्रैल-मई में केंद्र का राजकोषीय घाटा 1.23 लाख करोड़ रुपये रहा



जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था में टिकाऊ सुधार के लिए तेज गति से टीकाकरण और शहरी एवं ग्रामीण इलाके में हेल्थ इन्फ्रा का विकास सबसे अहम होगा। वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि सितंबर में त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले देश में टीके की 67 करोड़ डोज लग जाएंगी।

मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण की गति को तेज करके और कोरोना से बचने के लिए जरूरी सतर्कता बरतकर तीसरी लहर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। हालांकि कोरोना से मुक्त होने के लिए वैश्विक स्तर पर टीकाकरण की जरूरत है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, जून में टीकाकरण की दैनिक औसत दर 41.2 लाख रही, जो मई की 19.3 लाख के मुकाबले दोगुनी है। इस हिसाब से सितंबर में त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले टीके की 67 करोड़ डोज लग जाने की उम्मीद है, जिससे घरेलू मांग को प्रोत्साहन मिलेगा।

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर अच्छी तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीने अप्रैल व मई में केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति पिछले साल अप्रैल-मई के मुकाबले काफी बेहतर है। इस साल अप्रैल-मई में केंद्र का राजकोषीय घाटा 1.23 लाख करोड़ रहा, जो बजट अनुमान का सिर्फ 8.2 फीसद है। पिछले पांच साल में देखा गया है कि इन दो महीनों में घाटा अनुमान के औसतन 55.4 फीसद के आसपास हो जाता था। चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में कर व गैर कर दोनों मदों से मिलने वाला राजस्व भी पिछले साल के मुकाबले अधिक है। अप्रैल-मई, 2021 में केंद्र को टैक्स के रूप में 2.34 लाख करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई, जो सालभर पहले मात्र 33,850 करोड़ रुपये था। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस साल गैर कर राजस्व की प्राप्ति में पिछले साल अप्रैल-मई के मुकाबले 976.2 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

मंत्रालय ने कहा कि टीकाकरण के मामले में राज्यों की स्थिति का जायजा लेने से पता चलता है कि असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और झारखंड में टीकाकरण की रफ्तार तेज करने की जरूरत है। रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर टीकाकरण की स्थिति पर चिंता जताई गई है। दुनियाभर में महज 24.7 फीसद आबादी को टीका लगा है। कम आय वाले देशों में यह एक फीसद ही है। टीके की उपलब्धता में असंतुलन दूर करने की जरूरत है।

सेविंग्स और एफडी पर कम ब्याज ने बढ़ाया शेयर बाजारों की ओर रुझान

राजीव कुमार • नई दिल्ली

2 करोड़ नए डीमैट खाते खुले पिछले 16 महीने में, एसआइपी अकाउंट भी लगातार बढ़ रहा

- एफडी पर चार-पांच फीसद का ब्याज मिल रहा, बाजार में 10-12 फीसद रिटर्न की उम्मीद

खुदरा निवेशकों को बैंक नहीं बाजार लुभा रहा है। यही वजह है कि पिछले 16 महीनों में बाजार में निवेश करने के लिए दो करोड़ नए डीमैट खाते खोले गए। बैंकों में बचत खाते से लेकर फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में लगातार कमी से अब आम निवेशक स्टाक मार्केट की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक सरकार भी यही चाहती है कि लोग अपना पैसा बाजार में लगाएं। इससे नई-नई कंपनियों को बाजार में उतरने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं, बाजार से होने वाली कमाई के मामले में टैक्स चोरी नहीं की जा सकती है।

स्टाक मार्केट से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जून के आखिर में सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस (सीडीएसएल) और नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी (एनएसडीएल) पर डीमैट खातों की संख्या छह करोड़ हो गई। पिछले साल फरवरी में इन दोनों प्लेटफार्म पर 4.02 करोड़ डीमैट खाते थे। डीमैट के साथ एसआइपी खाते भी बढ़ रहे हैं। एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल 31 मई तक एसआइपी खातों की संख्या 3,88,35,530 थी, जो 30 जून तक बढ़कर 4,02,02,651 हो गई।

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक रेपो रेट चार फीसद होने के बाद से फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दर 2.9 से 5.4 फीसद के बीच चल रही है। सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.6 फीसद, वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम पर 7.4 फीसद, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर 7.1 फीसद और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 6.8 फीसद की दर से ब्याज मिल रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि बाजार में पांच साल के लिए पैसा लगाने पर 10-12 फीसद की दर से रिटर्न मिल जाता है। कोरोना काल में लोग स्टाक मार्केट में ट्रेडिंग के प्रति आकर्षित हुए। सेंसेक्स अभी 52,000 के स्तर को पार कर चुका है जबकि पिछले साल मार्च में सेंसेक्स 26,000 के स्तर था। इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले साल अप्रैल-मई में बाजार में निवेश करने वालों को काफी अच्छी कमाई हुई।

हालांकि विशेषज्ञ इस बात को लेकर भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि रिटेल निवेशकों का रुझान सेंसेक्स के बेहतर प्रदर्शन पर निर्भर करता है। स्टाक मार्केट में जो तेजी है, वह किस हद तक स्थायी है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। एक तरफ स्टाक मार्केट बढ़ रहा है, जबकि वास्तविक अर्थव्यवस्था प्रभावित दिख रही है। वहीं, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) ने पिछले वित्त वर्ष में भारत में 36.18 अरब डॉलर का निवेश किया है। बाजार में तेजी का यह भी कारण हो सकता है।

राजमार्गों के किनारे टाउनशिप को कैबिनेट से ली जाएगी मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र: राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्मार्ट सिटी, टाउनशिप, लॉजिस्टिक पार्क और इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्थापित करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय कैबिनेट से मंजूरी लेने की तैयारी में है। इस संबंध में कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को यह बात कही।



नितिन गडकरी ने कहा- मंत्रालय मौजूदा परियोजनाओं से पूंजी जुटाने के लिए योजना पर कर रहा है काम • जागरण आर्काइव

गडकरी ने कहा कि उनका लक्ष्य विश्वस्तरीय हाईवे नेटवर्क स्थापित करना है। मंत्रालय मौजूदा राजमार्ग परियोजनाओं से पूंजी जुटाने के लिए योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय 2.5 लाख करोड़ रुपये लागत की सुरंग भी बना रहा है। स्टील और सीमेंट की बढ़ती कीमतों को देखते हुए गडकरी ने गुणवत्ता से समझौता किए बिना इनोवेशन एवं शोध के जरिये सड़क निर्माण में इनका इस्तेमाल कम करने पर भी जोर दिया। साथ ही सड़क निर्माण की मशीनों में सीएनजी, एलएनजी और एथनॉल के प्रयोग की बात भी कही।

उन्होंने कहा कि करीब 63 लाख किलोमीटर के साथ भारत रोड नेटवर्क के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है।

बैंकर्स को मिलेगी 10 दिन की सरप्राइज लीव

मुंबई, प्रेट्र : रिजर्व बैंक ने ट्रेजरी ऑपरेशंस एवं करेंसी चेस्ट समेत विभिन्न संवेदनशील भूमिकाओं में काम करने वाले बैंकर्स के लिए सरप्राइज लीव का निर्देश दिया है। केंद्रीय बैंक ने अपने रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस में बैंकों से ऐसे अधिकारियों को साल में एक बार एकमुश्त कम से कम 10 दिन की छुट्टी देने को कहा है।

बैंकों को उन भूमिकाओं की सूची तैयार करने को कहा गया है, जिन्हें अनिवार्य अवकाश की इस नीति में शामिल किया जाएगा। नए निर्देशों का पालन बैंकों को छह महीने में करना होगा। रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 2015 में इस तरह का दिशानिर्देश जारी किया था, लेकिन उसमें छुट्टियों के दिन स्पष्ट नहीं थे। उस सर्कुलर के अनुसार, ट्रेजरी, करेंसी चेस्ट, रिस्क मॉडलिंग और मॉडल वैलिडेशन से जुड़े लोगों को इसके लिए पात्र माना गया है।

दर्जनभर आइपीओ से गुलजार होगा शेयर बाजार

तैयारी

- जोमैटो, ग्लेनमार्क साइंसेज, श्रीराम प्रापर्टीज जैसी कंपनियों के आइपीओ इसी महीने
- एलआइसी, पेटीएम, ओला कैब के आइपीओ की तैयारी अंतिम चरण में



इस महीने कतार में हैं 11 कंपनियों के आइपीओ • फाइल फोटो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: शेयर बाजार में निवेश के इच्छुक लोगों के लिए शानदार मौका आ रहा है। अकेले जुलाई में 11 कंपनियों के इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (आइपीओ) कतार में हैं। यह 11 साल में किसी भी एक महीने में आइपीओ की सबसे बड़ी संख्या है। इस साल करीब दो दर्जन कंपनियां बाजार से 32 हजार करोड़ जुटा चुकी हैं।

जुलाई में बाजार से 31 हजार करोड़ रुपये जुटाने की और कोशिश होगी। पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास आए आवेदनों की बात करें तो अगले चार-पांच महीने में 40 कंपनियों की ओर से 80 हजार करोड़ के आइपीओ आ सकते हैं। निवेशकों को जोमैटो, पेटीएम, ओला, एलआइसी जैसी जानी मानी कंपनियों में निवेश का मौका मिलेगा। ग्लेनमार्क साइंसेज और श्रीराम प्रापर्टीज के आइपीओ भी इसी महीने आने हैं।

आइपीओ लेकर बढ़ी हलचल के बीच सेबी भी सतर्क है। पूर्व में कुछ कंपनियां शेयर बाजार की तेजी का फायदा उठाकर आइपीओ से पैसे जुटाकर भाग चुकी हैं। सेबी अब ऐसी स्थिति नहीं आने देने के लिए सतर्क है। कंपनियों की जांच सख्त की गई है। जोमैटो, पेटीएम, पॉलिसीबाजार जैसे स्टार्टअप के आइपीओ को देखते हुए भी नियामक एजेंसी ज्यादा सतर्कता बरत रही है। जोमैटो के आइपीओ का आकार 8000-9000 करोड़ रुपये का माना जा रहा है। यह एसबीआइ कार्ड्स के बाद सबसे बड़ा आइपीओ होगा।

वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी फिंटू (एफआइएनटीओओ) के संस्थापक मनीष पी हिंगर का कहना है कि 2021 में अब तक 23 आइपीओ आ चुके हैं। इससे बाजार से जितनी राशि जुटाई गई है, उतनी अकेले जुलाई में जुटाई जा सकती है। इससे बाजार में तरलता की स्थिति का भी पता चलेगा। एक साथ इतने आइपीओ आने का एक खतरा होता है कि अगर एक-दो बड़ी कंपनियों के आइपीओ फेल हो जाते हैं तो उसका असर अन्य आइपीओ व पूरे बाजार पर पड़ता है। उन्होंने खुदरा निवेशकों को हर आइपीओ में आवेदन करने के बजाय अध्ययन के बाद ही कंपनी चुनने का सुझाव दिया।

इक्विटी 99 एडवाइजर के को-फाउंडर राहुल शर्मा का कहना है कि खुदरा निवेशकों को हमेशा कंपनी के बिजनेस मॉडल और उसके पुराने प्रदर्शन को निवेश का आधार बनाना चाहिए। आइपीओ के जरिये कम समय में पैसा कमाने की कोशिश में कई बार बड़ा नुकसान होता है। यह भी ध्यान रखें कि अगर कंपनी अच्छी है, तो आइपीओ आने के बाद उसके शेयरों की कीमत उसके सही मूल्य पर पहुंच ही जाएगी।

जीआर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के आइपीओ शुक्रवार को बंद हुए हैं और इसके शेयरों के लिए 108 गुना ज्यादा आवेदन आए हैं। क्लीन साइंस का आइपीओ भी 93.41 गुना सब्सक्राइब हुआ है। यह बताता है कि आम निवेशकों में आइपीओ को लेकर काफी उत्साह है।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

पूर्व सीजेआइ बोवडे को डाक्टर आफ ला की मानद उपाधि

मुंबई: देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) एसए बोबडे को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने डाक्टर आफ ला की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के 108वें दीक्षा समारोह में कोश्यारी ने बोबडे को यह मानद उपाधि दी। (प्रेट्र)

गैंगस्टर सुक्खा पर बनी फिल्म पर प्रतिबंध का मामला कोर्ट में

चंडीगढ़ : पंजाब के गैंगस्टर सुक्खा काहलवां पर बनी फिल्म शूटर के हरियाणा-पंजाब में रिलीज करने पर लगी रोक के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। फिल्म के निर्माता केवल सिंह की तरफ से दायर याचिका में मांग की गई है कि हरियाणा व पंजाब सरकार द्वारा रोक लगाना गलत है। (राब्यू)

नाइजीरियन युवक और मणीपुरी युवती गिरफ्तार

उत्तरकाशी: 84 लाख डालर का लालच देकर कस्टम ड्यूटी के नाम पर ढाई लाख रुपये की ठगी करने वाले नाइजीरिया मूल के अबी थियोफिलस और मणिपुर की जेनत छेत्री को दिल्ली से गिरफ्तार किया। ये कई व्यक्तियों से धोखाधड़ी कर चुके हैं। दोनों दिल्ली के वसंत कुंज में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। (जासं)

आसाराम को जेल में ही मिलेगा आयुर्वेद उपचार

जोधपुर : आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से आंशिक राहत मिली है। आसाराम अब जोधपुर जेल में ही आयुर्वेदिक डाक्टर से इलाज करा सकेगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने उसके पुत्र नारायण साई की याचिका पर यह फैसला दिया है। गौरतलब है कि आसाराम अपने ही आश्रम की लड़की से दुष्कर्म के दोष में जेल में बंद है। (संसू)

ओणम पर 90 लाख परिवारों को खाद्य सामग्री देगी

तिरुअनंतपुरम: केरल सरकार ओणम त्योहार के अवसर पर 90 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को खाद्य सामग्री देगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस सिलसिले में फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री पी विजयन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। (प्रेट्र)

मैं नार्को के लिए तैयार, साथ में कुंवर विजय प्रताप का भी हो : उमरानंगल

कोटकपूरा गोलीकांड

संवाद सहयोगी, फरीदकोट

कोटकपूरा गोलीकांड में एसआइटी की जांच दायरे में आए सस्पेंड चल रहे आइजी परमराज सिंह उमरानंगल शुक्रवार को जिला अदालत के समक्ष पेश हुए। एसआइटी की मांग पर नार्को टेस्ट को तैयार हुए उमरानंगल ने यह कहते हुए एसआइटी को असमंजस में डाल दिया कि उनके साथ पूर्व आइजी कुंवर विजय प्रताप सिंह का भी नार्को टेस्ट हो।

कोटकपूरा गोलीकांड मामले में एलके यादव के नेतृत्व में बनी नई एसआइटी की तरफ से पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, पूर्व एसएसपी चरनजीत शर्मा और आइजी परमराज सिंह उमरानंगल के नार्को टेस्ट की इजाजत लेने के लिए अदालत में आवेदन किया गया है। इस आवेदन पर पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी और पूर्व एसएसपी चरनजीत शर्मा ने नार्को टेस्ट करवाने से इन्कार कर दिया था, जबकि सस्पेंड चल रहे आइजी उमरानंगल की तरफ से अपनी सहमति जताई गई थी। इसी के चलते शुक्रवार को उमरानंगल की तरफ से अदालत में पेश होकर अपने वकील के माध्यम से अदालत में अपना सहमति पत्र दर्ज करवा दिया। अब सबकी नजरें आगे की जांच पर टिकी हुई है।



फरीदकोट की जिला अदालत से बाहर आते आइजी परमराज उमरानंगल (मध्य में)। फोटो जागरण

सरयू में डूबकर छह की मौत, तीन लापता

जागरण संवाददाता, अयोध्या

सरयू नदी में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। आगरा से रामनगरी दर्शन के लिए आए एक ही परिवार के 12 सदस्य सरयू की धारा में फंस गए। हादसे में छह लोगों की नदी में डूबने से मौत हो गई, जबकि तीन लापता हैं और तीन लोगों को बचा लिया गया, जिसमें एक सात साल की बच्ची भी शामिल है। डीएम अनुज झा ने बताया कि लापता लोगों की तलाश के लिए एसएसपी शैलेश पांडेय के नेतृत्व में जल पुलिस लगातार रेस्क्यू कर रही है। हादसा पौराणिक स्थल गुप्तारघाट के करीब हुआ।

आगरा के सिकंदरा की शास्त्रीपुरम कालोनी के ब्लाक एक निवासी अशोक कुमार अपने परिवार के 15 सदस्यों के साथ रामनगरी दर्शन के लिए आए थे। शुक्रवार को जब वे गुप्तारघाट पहुंचे तो तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश धीमी होने के दौरान महिलाएं घाट पर हाथ-पांव धुल रही थीं। इसी बीच एक महिला का पांव फिसलने से वह नदी में गिर गईं। उन्हें बचाने के प्रयास में एक-एक कर साथ आए बच्चों सहित 12 लोग नदी में उतर गए। नदी का बहाव तेज होने के कारण सभी लहरों में फंस गए।

तैरना नहीं जानती थी...पर नन्ही धैर्या ने धैर्य और साहस का दिया परिचय

जासं, अयोध्या

- तट से सौ मीटर दूर तीव्र प्रवाह से तैर कर बाहर निकली सात वर्षीय बच्ची



मासूम ने दी हादसे को मात। जागरण

सरयू की अपार जलराशि के सामने जब परिवार के बड़े सदस्य हिम्मत हार गए, तब सात वर्षीय धैर्या ने अपने नाम के अनुरूप अपूर्व धैर्य और साहस का परिचय दिया। इस नन्ही सी जान का तैराकी से कोई वास्ता नहीं था, किंतु मुसीबत ने उसे तैरना सिखा दिया। मां, पिता, बुआ और संयुक्त परिवार के 12 सदस्यों के साथ शुक्रवार को दुर्घटनावश सरयू की मझधार में फंसने वालों में धैर्या भी थी और जब तक उसे कुछ होश आता, वह तट से तकरीबन सौ मीटर दूर तीव्र प्रवाह में हिचकोले खा रही थी। कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और धैर्या इस विश्वास की पर्याय बन कर हाथ-पांव मारने लगी। तैराकी से उसका कोई वास्ता नहीं था, पर कोशिश रंग लाने लगी। दर्जन भर लोगों को खो देने के बाद बाजी हार कर तट पर जमा स्वजन व संवेदना जता रहे लोगों में तो किनारे की ओर आ रही धैर्या जैसे नई उम्मीद और नव जीवन का संचार करती हुई आगे बढ़ी। खुद बचने के बावजूद धैर्या की नम आंखें बता रही थी कि उसे स्वजन को खो देने का भान हो गया है।

नवाब खानदान की 300 करोड़ की संपत्ति पर सरकार ने जताया दावा

जागरण संवाददाता, रामपुर

- जिला जज की अदालत में दावा जताते हुए कब्जा दिलाने की मांग की
- पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल की पत्नी की रामपुर में है जायदाद

पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल स्वर्गीय अब्दुल रहीम खान की पत्नी मेहरुन्निशा बेगम की उम्र के रामपुर में करीब 300 करोड़ की संपत्ति है। भारत सरकार के सह अभिरक्षक शत्रु संपत्ति ने जिला जज की अदालत में इस पर दावा जताया है। साथ ही कब्जा दिलाने की मांग की है।

रामपुर में नवाब खानदान की 2,600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई, 2019 को शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश देते हुए जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी। संपत्ति का सर्वे और मूल्यांकन का काम पूरा हो चुका है। किसे कौन सी संपत्ति दी जानी है, यह तय होना बाकी है। संपत्ति में कुल 18 पक्षकार थे। इनमें दो की मौत हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मेहरुन्निशा का बन रहा है। इस संपत्ति में उनका हिस्सा 7.292 फीसद है, जबकि उनकी मां तलत जमानी बेगम का 4.167 फीसद तय हो चुका है। उनकी मां का इंतकाल हो चुका है, इसलिए उनका हिस्सा भी इन्हें ही मिलेगा। दोनों का मिलाकर 11.459 फीसद हिस्सा बन रहा है और इतने हिस्से में करीब 300 करोड़ की संपत्ति आ रही है। मेहरुन्निशा रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खां की बेटी हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार के सह अभिरक्षक की ओर से उन्होंने शुक्रवार को जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर उक्त संपत्ति पर दावा जताया है।

अभिनेता सलमान खान पर व्यापारी ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप

जासं, चंडीगढ़ : चंडीगढ़ के एक व्यापारी ने अभिनेता सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा खान और उनकी कंपनी बीइंग ह्यूमन सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस ने अभिनेता व अन्य को समन भेजकर जवाब मांगा है।

पुलिस के मुताबिक, व्यापारी अरुण गुप्ता ने सलमान खान सहित सभी पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों खर्च कराने के बाद सामान नहीं भेजकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। अरुण ने सलमान खान के कहने पर मनीमाजरा स्थित एनएसी एरिया में बड़ा शोरूम खोला था। इसे डेकोरेट करने और संचालित करने के लिए तकरीबन तीन करोड़ रुपये और खर्च कर दिए। शोरूम खुलवाने के बाद उनका एग्रीमेंट एक कंपनी से कराया गया, जो बीइंग ह्यूमन का हिस्सा है। नियम और शर्तों के तहत उन्होंने एक करोड़ रुपये शोरूम को बनाने में लगाया।

हर किसी को न मिले क्राउडफंडिंग की इजाजत : केरल हाई कोर्ट

- दुर्लभ बीमारी के उपचार के लिए चंदा एकत्र करने के तरीके पर जताई चिंता

कोचि, प्रेट्र : दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए जिस तरह लोगों से चंदा वसूला जा रहा है उसको लेकर केरल हाई कोर्ट ने चिंता जताई और कहा कि हर 'टाम, डिक और हैरी' को इस तरह के क्राउडफंडिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि ऐसे एकत्र धन पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि दुर्लभ रोग से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए जिसको देखो 'टाम, डिक और हैरी' की तरह धन इकट्ठा करने लगता है। यह चिंता की बात है और राज्य सरकार से पूछा कि क्या उसके पास इस तरह के लेनदेन पर कोई नियंत्रण है। न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने कहा कि कोर्ट इस तरह की क्राउडफंडिंग को लेकर कोई निर्देश नहीं जारी करना चाहता, लेकिन कोर्ट चाहता है कि वह धन किसी व्यक्ति विशेष के खाते में न जाकर सरकार के पास जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वह व्यक्ति जरूरतमंद को वह राशि दे या न दे। हम जानना चाहते हैं कि वह राशि कहां जा रही है। कोर्ट ने कहा कि जब लोग इस तरह धन एकत्र कर सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि फ्री वैक्सीन के लिए राज्य सरकार सिर्फ 68 लाख इकट्ठा कर पाती है जबकि दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी से पीड़ित एक बच्चे के इलाज के लिए लोग एक सप्ताह में ही 18 करोड़ रुपये एकत्र कर लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के एकत्र राशि की उचित निगरानी न करने पर अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। कोर्ट एक आटोरिक्शा ड्राइवर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसका छह माह का बच्चा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है और दवा की कीमत 18 करोड़ रुपये है।

रेलवे स्टेशन पर मिलेगी स्थानीय मिठाई और खाना

प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद : ट्रेन में सफर के दौरान रेलवे स्टेशनों पर उस क्षेत्र का प्रचलित खाना यात्रियों को उपलब्ध होगा। मंडल रेल प्रशासन स्थानीय प्रचलित खाना व मिठाई कंपनी को प्रोत्साहित करेगा और स्टेशन के स्टाल पर बिक्री कराने के लिए अनुरोध करेगा। रेलवे स्टेशनों पर बहुत जल्द ही यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए स्थानीय खान-पान कंपनी से रेलवे की ओर से आवेदन मांगे जा रहे हैं।

रेलवे स्टेशन या ट्रेन में किस कंपनी के पैकेट बंद खाने की बिक्री होगी या किस कंपनी का बोतल बंद पानी, कोल्ड ड्रिंक, दूध आदि की बिक्री होगी, पहले इसको जोनल रेलवे द्वारा निर्धारित किया जाता था। रेलवे बोर्ड ने स्थानीय प्रचलित पैकेट बंद खाने की बिक्री कराने के लिए जोनल रेल के स्थान पर मंडल रेल प्रशासन को चयन करने का अधिकार दे दिया है। मंडल रेल प्रशासन ने प्रमुख रेलवे स्टेशनों व ट्रेन के अंदर बिक्री करवाने का प्रयास शुरू कर दिया है।

This PDF was originally uploaded To The English Newspaper L-- Banna SA (https://t.me/English_Newspaper_L_Banna)one else Backup chennal @NEWS_Backup_L_Banna

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 10 जुलाई, 2021

दैनिक जागरण

धैर्य से किया गया कार्य ही उत्कृष्टता की ओर ले जाता है

जल्द बने समान संहिता

दिल्ली उच्च न्यायालय ने तलाक के एक मामले की सुनवाई करते हुए समान नागरिक संहिता को वक्त की जरूरत बताकर एक बार फिर इस मसले पर जारी बहस को बल प्रदान करने का काम किया है। अब इस मसले पर केवल बहस ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि आगे भी बढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने में जरूरत से ज्यादा देर हो चुकी है। समान नागरिक संहिता का निर्माण करने की दिशा में केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ा जाना चाहिए कि संविधान निर्माताओं ने ऐसी अपेक्षा की थी, बल्कि इसलिए भी बढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इससे कई समस्याओं का निराकरण होगा और हमारा समाज अधिक समरस एवं एकजुट दिखेगा। ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि समान नागरिक संहिता बन जाने के बाद अलग-अलग समुदायों के लिए शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेने की प्रक्रिया और विरासत से जुड़े अधिकार एक जैसे हो जाएंगे। आखिर इसमें क्या कठिनाई है? कठिनाई है तो इच्छाशक्ति का अभाव और कुछ राजनीतिक दलों की संकीर्णता।

यह समझ आता है कि संविधान लागू होने के तत्काल बाद का वक्त समान नागरिक संहिता के निर्माण के लिए अनुकूल न रहा हो, लेकिन बीते सात दशकों में बहुत कुछ बदल चुका है और अब भारतीय समाज इस संहिता में ढलने के लिए तैयार है। इसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी यह कहकर रेखांकित किया कि आज का भारत जाति, मजहब और समुदाय से ऊपर उठ चुका है और इनसे जुड़ी बाधाएं तेजी से टूट रही हैं। उसने यह भी पाया कि तेजी से हो रहे इस परिवर्तन के कारण अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाह में समस्या आ रही है। वास्तव में बात केवल इतनी ही नहीं है, बात यह भी है कि कुछ समुदायों के विवाह, तलाक, गोद लेने के मामलों में पर्सनल लॉ लागू होने के कारण महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। बेहतर होगा कि केंद्रीय सत्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के विचारों को गंभीरता से ले और समान नागरिक संहिता पर सार्थक बहस के लिए इस संहिता का कोई मसौदा तैयार करे। यह काम इसलिए भी होना चाहिए, क्योंकि समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट भी समान नागरिक संहिता की जरूरत जता चुका है। एक तथ्य यह भी है कि गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है और इस राज्य के किसी भी समुदाय ने शायद ही कभी यह कहा हो कि उसे इस संहिता से समस्या पेश आ रही है। आखिर जो काम गोवा में हो सकता है, वह शेष देश में क्यों नहीं हो सकता? यह वह सवाल है जिस पर उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो संकीर्ण राजनीतिक कारणों से समान नागरिक संहिता के खिलाफ खड़े रहते हैं।

छूट के साथ बढ़ी जिम्मेदारी

कोरोना की दूसरी लहर काफी हद तक शांत होने के बाद पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू खत्म करके उचित ही किया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी कहा है कि पाजिटिव केस अब बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए कोरोना को लेकर सरकार को कोई निर्देश जारी करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू खत्म करने के साथ ही बार, रेस्टोरेंट, सिनेमा हाल इत्यादि खोलने की मंजूरी देना भी समय की मांग थी, क्योंकि लंबे समय से पाबंदियों के कारण आर्थिक हालत पतली हो गई है। अनेक लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यह बहुत जरूरी है कि यथाशीघ्र अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, लेकिन इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को नजरअंदाज न किया जाए। मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियम का पालन बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने छूट देने के साथ ही टीकाकरण पर जिस तरह जोर दिया है वह बहुत आवश्यक है। बार, रेस्टोरेंट में जाने वालों के लिए वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगी होने की शर्त लगाकर सरकार ने उचित ही किया है। दरअसल प्रदेश में टीकाकरण की रफ्तार अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। अभी तक राज्य में 70 लाख लोगों यानी लगभग एक चौथाई आबादी को ही पहली डोज लग सकी है। दूसरी डोज तो सिर्फ 13 लाख लोगों को लगी है। सोलह जिलों में वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण टीकाकरण का कार्य ठप हो गया है। कई जिलों में टीकाकरण केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें निराश लौटना पड़ रहा है। यह अच्छी बात है कि अब लोगों में वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूकता देखी जा रही है। रोजाना कम से कम एक लाख लोगों को टीका लगाया जाना था, लेकिन आजकल आंकड़ा 25 हजार से ऊपर नहीं पहुंच रहा है। प्रदेश सरकार को इसे गंभीरता से लेना होगा। केंद्र सरकार से लगातार तालमेल बनाकर वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। चूंकि प्रदेश में एक दिन में छह लाख लोगों के टीकाकरण का रिकार्ड बन चुका है, इसलिए यदि वैक्सीन की कमी न हो तो यथाशीघ्र ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने में संसाधनों की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोरोना से प्रदेश में अब भी रोजाना आठ-नौ लोगों की जान जा रही है, इसलिए टीकाकरण में किसी भी तरह की सुस्ती भारी पड़ सकती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है मतांतरण



दिव्य कुमार सोती

यह सामान्य समझ की ही बात है कि मतांतरण कराने के लिए कोई विदेश से अरबों रुपये यूं ही क्यों भेजेगा?

पिछले दिनों एक बड़े मतांतरण रैकेट का पता चला। इस्लामिक दावा सेंटर के साये में चल रही मतांतरण की इस मुहिम में लगे इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सैकड़ों की संख्या में मूक-बधिरों तक का मतांतरण करा डाला। मतांतरण में लिप्त लोग 'दावा' की उसी इस्लामी संकल्पना पर काम कर रहे थे, जिसे आगे बढ़ाने के लिए हाफिज सईद जमात उद दावा चलाता है। यह चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन इस ओर इंगित करता है कि मतांतरण के अंतरराष्ट्रीय अभियान से जुड़ी संस्थाएं समाज के उन वर्गों का भी गहराई से सर्वेक्षण करती रहती हैं, जिनकी ओर आम जनमानस और सरकारों का ध्यान कम ही जाता है। यह पूरा मामला यह भी दिखाता है कि मतांतरण को अपना मिशन बनाने वाली संस्थाएं मूक-बधिर, दिव्यांग और अनाथ बच्चों के बीच में जो भी काम करती हैं, वह मानवीयता से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि अपने मत-मजहब के अनुयायियों की संख्या थोक के भाव बढ़ाने के मकसद से करती हैं। इस्लामिक दावा सेंटर को विदेशी फंडिंग मुहैया कराने वाली कई संस्थाएं तथाकथित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन मतांतरण से जुड़े प्रश्न यहीं तक सीमित नहीं हैं।

मतांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड उमर गौतम नामक एक व्यक्ति स्वयं पहले हिंदू धर्म से इस्लाम में मतांतरित हुआ था। उसके बाद उसने जो कुछ किया, वह स्वामी विवेकानंद के भारतीय परिप्रेक्ष्य में मतांतरण पर दिए उस वक्तव्य को ही चरितार्थ करता है कि हिंदू धर्म छोड़कर जाने वाला व्यक्ति अपने मूल धर्म के प्रति शत्रुता का भाव रखने लगता है। इस शत्रुता भाव ने भारत के इतिहास में नृशंस नरसंहारों से लेकर देश के बंटवारे तक को घटित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दक्षिण भारत के मंदिरों को ध्वस्त करने वाले मलिक काफूर से लेकर मजहब के नाम पर देश का विभाजन कराने वाले मोहम्मद अली जिन्ना तक इसके असंख्य उदाहरण हैं। आज भी कश्मीर में बड़े आतंकी कमांडरों के हिंदू उपनाम बताते हैं कि उनके पूर्वजों का मतांतरण कुछ पीढ़ी पहले ही हुआ है। पूर्वोत्तर भारत में दशकों से सक्रिय एनडीएफबी, एनएलएफटी जैसे उग्रवादी संगठन पूरी तरह ईसाई कट्टरपंथी संगठन ही हैं। इन प्रदेशों का ईसाईकरण और इन अलगाववादी आंदोलनों का जन्म साथ-साथ हुई घटनाएं हैं। मध्य भारत के नक्सल प्रभावित भागों में भी ईसाई मिशनरी बेहद सक्रिय हैं। ऐसे में मतांतरण के राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को भला कैसे नकारा जा सकता है, विशेषकर भारत जैसे देश में, जिसका मजहब के आधार पर विभाजन हुए सात दशक ही बीते हों। भारत योजनाबद्ध रूप से कराए जा रहे मतांतरण को कैसे अनदेखा कर सकता है?



अवधेश राजपूत

आखिर भारत के वही प्रदेश अलगाववादी मुहिम के चलते हिंसाग्रस्त क्यों हैं, जहां पिछली कुछ सदियों में बड़े पैमाने पर मतांतरण हुआ? स्वतंत्र भारत का इतिहास यह पाठ पढ़ाता है कि देश में दो बार बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ। एक बार 1990 में इस्लामिक कट्टरपंथ के चलते कश्मीर से हिंदुओं को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा और दूसरी बार 1997 में रिआंग या ब्रू हिंदुओं को मिजोरम से ईसाई कट्टरपंथियों के हमलों के चलते भागना पड़ा। दोनों ही मामलों में यह पलायन लगभग स्थायी ही बन गया और ये लोग कभी वापस नहीं लौट पाए। मतलब भारत के बहुसंख्यक समाज को उन प्रदेशों से पलायन करना पड़ा, जहां पिछले कुछ सौ वर्षों में बड़े पैमाने पर मतांतरण के चलते वे अल्पसंख्यक हो गए थे।

भारत विश्व का अकेला देश है, जहां अल्पसंख्यक मतों के लोग मतांतरण अभियान चलाने का संवैधानिक अधिकार बनाए रखना चाहते हैं और बहुसंख्यक मतांतरण पर रोक लगाना चाहते हैं। अन्यथा स्वाभाविक प्रक्रिया यह होती है कि अपने अनुयायियों को बहुसंख्यकों द्वारा मतांतरण कराए जाने से बचाने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय मतांतरण पर प्रतिबंध की मांग किया करते हैं, जो स्वाभाविक भी है। यह सामान्य समझ की बात है कि विदेश से मतांतरण कराने के लिए अरबों रुपये यूं ही कोई क्यों भेजेगा? दरअसल मतांतरण ईसाई और इस्लामिक देशों द्वारा अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है और अक्सर भूराजनीतिक बिसात पर इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए नेपाल में पैर पसारते माओवाद और उसके माध्यम से बढ़ते चीनी प्रभाव को कम करने के लिए पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां ईसाई मिशनरियों का उपयोग करती आई हैं, जिसका असर नेपाल में बढ़ते मतांतरण और घटते भारतीय प्रभाव के रूप में दिखता है।

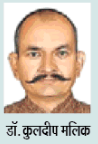
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बढ़ती ताकत को काबू करने के लिए पश्चिमी देश खुद चीन के भीतर ईसाई मिशनरी गतिविधियों को प्रोत्साहन देते आए हैं। कुछ वर्ष पहले अमेरिका के तत्कालीन उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने सार्वजनिक रूप से इस पर प्रसन्नता जताई थी कि 13 करोड़ चीनी ईसाई बन चुके हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के इस व्यवहार की तुलना नेपाल के हिंदू राष्ट्र न रह जाने को लेकर भारतीय उदासीनता से देखते ही बनती है। बहरहाल यह संख्या (13 करोड़) चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या से चार करोड़ ज्यादा है और आने वाले कुछ दशकों में चीन विश्व की सबसे बड़ी ईसाई आबादी का घर बन सकता है। इससे चिंतित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कन्फ्यूशियस के उन आध्यात्मिक विचारों पर आधारित प्राचीन चीनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने पर करोड़ों डॉलर खर्च करने में लगी हुई है, जिन्हें ध्वस्त करने के लिए एक समय माओ ने सांस्कृतिक क्रांति जैसा खूनी अभियान चलाया था।

अमेरिका के जाने माने सामरिक चिंतक रॉबर्ट कापलान लिख चुके हैं कि किस तरह अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अमेरिकी फौज से सेवानिवृत्त हुए लोगों को ईसाई मिशनरी बनाकर उनका उपयोग म्यांमार जैसे देशों में आदिवासियों का मतांतरण कराने और उन्हें सशस्त्र संघर्ष में सहायता करने के लिए करती आई हैं। अपने चारों ओर मतांतरण के जरिये चल रहे इस भूराजनीतिक खेल की हम अनदेखी नहीं कर सकते। मतांतरण में लिप्त जिन शक्तियों से हमारा मुकाबला है उनके लिए मजहब न तो राजनीति से अलग है और न ही भू-राजनीति से। दूसरे देशों में मतांतरण कराना इन शक्तियों की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

(लेखक काउंसिल ऑफ स्ट्रेटजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

जरूरी है आबादी पर नियंत्रण की पहल



डॉ. कुलदीप मलिक

अपने देश में जनसंख्या-संसाधन अनुपात असंतुलित होना गंभीर चिंता का विषय बनना चाहिए

हम दो-हमारे दो, छोटा परिवार-सुखी परिवार, बढ़ती जो आबादी है-देश की बर्बादी है। ये ऐसे नारे हैं जो भारत में बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर लोगों में जागरूकता लाने के लिए समय-समय पर सरकार एवं समाजसेवी संस्थाओं ने दीवारों पर लिखकर या फिर विज्ञापनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम आजादी के बाद जारी रखा। निःसंदेह इन नारों का कुछ असर भी हुआ होगा, लेकिन कुल मिलाकर परिणाम यह हुआ कि आजादी के बाद की 34 करोड़ की जनसंख्या वर्तमान में 138 करोड़ को पार कर चुकी है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चीन को पछाड़कर विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में होंगे, जबकि हमारा कुल क्षेत्रफल चीन के क्षेत्रफल का एक तिहाई भी नहीं है। अगर इसी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती रही तो अगले 10 से 12 साल में हमारी जनसंख्या 1.5 अरब को पार कर जाएगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब 1857 में भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, तब भारत की जनसंख्या मात्र 35 करोड़ थी और आज वर्तमान में जब भारत का क्षेत्रफल घटकर मात्र 33 लाख वर्ग किमी ही बचा है, तब भारत की जनसंख्या 138 करोड़ को पार कर चुकी है। दुनिया की लगभग 18 प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, जबकि दुनिया की केवल 2.4 प्रतिशत जमीन, चार प्रतिशत पीने का पानी और 2.4 प्रतिशत वन क्षेत्र ही भारत में उपलब्ध है। यह एक बहुत ही चिंतनीय विषय है कि अपने देश में जनसंख्या-संसाधन अनुपात असंतुलित है।

बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ देश में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनमें खराब होता पर्यावरण, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती बेरोजगारी, महंगाई आदि शामिल हैं। अगर देश में शुद्ध पानी की बात करें तो आजादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी 75 प्रतिशत भारतीय परिवारों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं है। पानी की गुणवत्ता के मामले में गुणवत्ता सूचकांक पर हम 122 देशों की सूची में 119वें स्थान पर हैं यानी भारत खराब पानी पीने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। शुद्ध हवा के मामले में भी एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 भारतीय शहर शामिल हैं। दुनिया के तमाम देशों की राजधानियों में दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में कुख्यात हो चली है। प्रदूषण के कारण दुनिया में मरने वाले 28 प्रतिशत लोग भारतीय हैं। वर्तमान में अगर कैंसर, टीबी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी तमाम बीमारियों के सबसे ज्यादा मरीज दुनिया में कहीं पर हैं तो अपने देश में ही हैं।



जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की तेज होती मांग। प्रेट्र

देश में मौजूद समस्याओं के बहुत से कारण हो सकते हैं, परंतु सभी समस्याओं का सबसे प्रमुख और बुनियादी कारण हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या का प्रकोप भी है। क्या यह अजीब नहीं कि 45 साल पहले 1975 में जब भारत की आबादी 55 से 56 करोड़ थी, तब देश की बढ़ती जनसंख्या इस देश के प्रमुख नेताओं के लिए एक गंभीर मुद्दा था, लेकिन 1975-77 के बाद सभी राजनीतिक दलों ने इतने गंभीर मुद्दे से किनारा कर लिया। कितना आश्चर्यजनक है कि आजादी के 74 साल बीत जाने के बाद कोई भी राजनीतिक दल बढ़ती जनसंख्या जैसे मुद्दे को आज तक अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल नहीं कर सका है। यह ठीक है कि आपातकाल में नसबंदी को लेकर जैसी जोर-जबरदस्ती की गई, उससे नेताओं ने जनसंख्या नियंत्रण पर बात करनी बंद कर दी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था कि यह बात नए सिरे से न शुरू की जाती। यदि बीते कुछ दशकों में बढ़ती जनसंख्या की अनदेखी नहीं की गई होती तो शायद आज जो गंभीर स्थिति है, उससे बचा जा सकता था। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि धीरे-धीरे भारत की जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार थम रही है, लेकिन इसके बावजूद तथ्य यही है कि भारत जल्द ही चीन को पछाड़कर सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने की राह पर है। कम क्षेत्रफल और सीमित संसाधनों के बीच भारत का जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर आना कोई अच्छी बात नहीं होगी। विश्व जनसंख्या दिवस (11 जुलाई) के अवसर पर आबादी के मुद्दे पर गंभीर चर्चा होना आवश्यक है।

यह एक शुभ संकेत है कि करीब 45 साल बाद जनसंख्या के मुद्दे पर सरकारें जगती नजर आ रही हैं। वर्ष 2019 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से छोटे परिवार को देश प्रेम कहने के बाद अब असम और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। वह जल्द ही जनसंख्या को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। यदि उत्तर प्रदेश में यह कानून आता है तो दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को आने वाले समय में सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से वंचित रहना पड़ सकता है। जो भी हो, यह सही समय है कि सभी राज्य सरकारें आम जनता को बड़े परिवार से होने वाले नुकसान से परिचित कराएं। उन लोगों तक यह संदेश खासतौर पर पहुंचाया जाना चाहिए, जो परिवार नियोजन की महत्ता से परिचित नहीं हैं या फिर उसके प्रति बेपरवाह हैं। यही सही है कि आबादी का एक वर्ग छोटे परिवार की महत्ता से अवगत हो गया है, लेकिन अशिक्षित और गरीब तबके में तमाम लोग ऐसे हैं जो बड़े परिवार से होने वाले नुकसान से परिचित नहीं। जनसंख्या नियंत्रण के मामले में अब आवश्यकता यह है कि सभी राजनीतिक दल जाति, मजहब और संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय स्तर पर भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने में मदद करें, ताकि देश की जनता को प्रदूषण, खराब सेहत, बेरोजगारी, अशिक्षा और अन्य समस्याओं से छुटकारा मिल सके।

(लेखक प्रोफेसर एवं वेदार्णा फाउंडेशन के निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अनमोल शिक्षा

ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम भारत की महान विभूतियों में शामिल किया जाता है। वह एक मूर्धन्य समाज सुधारक और शिक्षक रहे, परंतु क्या आपको पता है कि उनके भीतर इन मूल्यों की अलख किसने जगाई थी? विद्यासागर को ये संस्कार किसी और से नहीं, बल्कि उनकी मां से मिले थे। इस मामले में एक दृष्टांत उल्लेखनीय है। विद्यासागर जब छोटे थे तो एक दिन सुबह उनके द्वार पर एक भिखारी आया। उसे हाथ फैलाए देखकर उनके मन में करुणा उमड़ी। वह तुरंत घर के भीतर गए और अपनी मां से कहा कि भिखारी को कुछ दे दिया जाए। मां के पास उस समय कंगन के सिवाय देने के लिए कुछ और न था। उन्होंने अपना कंगन उतारकर बालक ईश्वरचंद के हाथ में रख दिया और कहा कि जिस दिन तुम बड़े हो जाओगे, उस दिन मेरे लिए दूसरा बनवा देना। अभी इसे बेचकर जरूरतमंद की मदद करो।

बड़े होने पर ईश्वरचंद विद्यासागर अपनी पहली कमाई से मां के लिए सोने के कंगन बनवाकर ले गए और उनसे कहा, 'मां, आज मैंने बचपन का तुम्हारा वह कर्ज उतार दिया।' इस पर उनकी मां ने कहा, 'बेटे! मेरा कर्ज तो उस दिन उतर पाएगा, जिस दिन किसी और जरूरतमंद के लिए मुझे ये कंगन दोबारा नहीं उतारने होंगे।' मां की यह सीख ईश्वरचंद विद्यासागर के दिल को छू गई और उन्होंने प्रण किया कि वह अपना जीवन गरीब-दुखियों की सेवा करने और उनके कष्ट निवारण में व्यतीत करेंगे और उन्होंने जीवनपर्यंत ऐसा किया भी।

यह दृष्टांत दर्शाता है कि हमारे समाज में परिवार को पहली पाठशाला और मां को पहली गुरु क्यों कहा गया है? माता द्वारा दी गई शिक्षा-दीक्षा ही हमारे जीवन को एक सही दिशा देती है। जो लोग उस शिक्षा को सही रूप में आत्मसात कर लेते हैं, उनका जीवन मिसाल बन जाता है। प्रत्येक महापुरुष का जीवन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वहीं जो लोग उस शिक्षा की अनदेखी करते हैं, वे राह से भटककर अपने जीवन को निरर्थक बना देते हैं।

मोनिका राज

एआइ के नवाचार से कृषि का उद्धार

देवेंद्रराज सुथार

एआइ जैसी तकनीक कृषि के समक्ष चुनौतियों का समाधान निकालने में सक्षम है। उसे बड़े पैमाने पर आजमाना चाहिए

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस दौर की एक चमत्कृत तकनीक बन गई है। चूंकि यह मौसमी दुविधाओं को दूर करने में भी सक्षम है तो इसमें कृषि क्षेत्र की कायपलट करने की भरपूर कूवत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि एआइ की मदद से किसानों को बाजार, इनपुट, डाटा, सलाह, क्रेडिट और बीमा जैसी सुविधाएं आसानी से मुहैया कराई जा सकती हैं। इससे किसान सशक्त होंगे। प्रधानमंत्री की सोच को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान यूनिलीवर और गूगल ने कई ऐसे क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने की कोशिश की है जो पानी से जुड़े हैं। साथ ही सामाजिक उद्यमियों, विशेषज्ञों और सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा, तकनीकी विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान कर रहे हैं, ताकि इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर समझा जा सके।

पिछले कई वर्षों से विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि एआइ किसानों के काम का बोझ घटाने में उपयोगी है। उनका मानना है कि अगर भारत के कृषि क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाए तो समग्र खाद्य श्रृंखला आपूर्ति में सुधार किया जा सकता है। एआइ की मदद से किसानों को मौसम में बदलाव, प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है। यदि किसानों को मौसम या प्रदूषण के स्तर को लेकर समय से सटीक जानकारी मिल जाए तो वे जान सकते हैं कि किस फसल के लिए कब तैयार होना है। इसके अलावा आज जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं, उसका असर मिट्टी पर भी पड़ रहा है। एआइ की मदद से किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में बेहतर जानकारी भी दी जा सकती है।

एक जर्मन स्टार्ट-अप पीट ने एआइ पर आधारित 'प्लाँटिक्स' नामक एप विकसित किया है। इस एप की मदद से किसानों को मिट्टी के पोषक तत्वों की जानकारी दी जाती है। यह भी बताया जाता है कि पेड़ में किस तरह के कीड़े मिल सकते हैं और कौनसा कीटाणुनाशक उनके लिए सही रहेगा। यह एप इमेज रिकग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। किसानों को बस अपने स्मार्टफोन से पेड़ की फोटो खींचनी है और उन्हें हर जानकारी तुरंत मिल जाती है।

विश्व की जनसंख्या में वृद्धि के साथ कृषि योग्य भूमि की कमी एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। इसलिए लोगों को कृषि के संदर्भ में अधिक रचनात्मकता होने एवं नए कौशल सीखने की आवश्यकता है। इसके तहत कम भूमि में उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष जोर देना होगा। आजादी के बाद से भारत में कृषि में सुधार के कई बड़े प्रयासों के बावजूद आज भी यह क्षेत्र मानसून की अनिश्चितता, आधुनिक उपकरणों की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। इस संदर्भ में जलवायु परिवर्तन और खाद्य असुरक्षा जैसी चुनौतियों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसा नवाचार कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

अब एजेंडे को अमल में लाने की चुनौती

'मंत्रिपरिषद विस्तार का राजनीतिक संदेश' शीर्षक से लिखे आलेख में हर्ष वर्धन त्रिपाठी द्वारा फर्श से अर्श पर पहुंचने वाली भारतीय जनता पार्टी में समय के सापेक्ष होने वाले बदलाव को उसकी सफलता का राज बताना अपनी जगह सही है। हालांकि आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान जिनके नाम से हो रही है, वह संघ शाखा की मिट्टी से निकले भाजपा के ऐसे सारथी और महारथी हैं, जिनकी भाजपा को राष्ट्र का राजनीतिक विकल्प बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। व्यक्ति को पहचानने और उसके काम को परखने की पैनी निगाह जैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, उसका प्रदर्शन अभी हाल में हुए मंत्रिपरिषद विस्तार में पूरे देश ने देखा है। अपनी टीम के स्तंभ माने जाने वाले रविशंकर प्रसाद, डॉ. हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक और प्रकाश जावडेकर जैसे दिग्गज नेताओं को मोदी ने बहुत संजीदगी के साथ अपनी कैबिनेट से हटा दिया। वहीं मनसुख मांडविया, अश्विनी वैष्णव, मीनाक्षी लेखी और आरके सिंह जैसे दक्ष और अपने कार्यक्षेत्र में निपुण लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने का साहस जुटा पाना मोदी जैसे दृढ़ इच्छाशक्ति वाले प्रधानमंत्री के ही बस की बात है। इसके पीछे की वजह साफ है कि वह जो कुछ भी करते हैं, लोकहित में ही करते हैं। उनके फैसले अडिग और दूरगामी होते हैं। उनके लिए व्यक्ति से अधिक देश महत्वपूर्ण है। इस विस्तार में उन्होंने न केवल जातिगत समीकरण का खयाल रखा, अपितु केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिक से अधिक राज्यों का प्रतिनिधित्व संभव हो सके, इस बात की भी पूरी कोशिश की है। हालांकि अब सरकार के पास अपने एजेंडे को पूरा करने का समय काफी कम बचा है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण सरकारी प्राथमिकताएं तात्कालिक रूप से बदल गई हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अपनी टीम में जो बदलाव किए हैं उनका असर जमीनी स्तर पर प्रदर्शन में दिखना भी चाहिए। यकीनन यह एक बड़ी चुनौती होगी।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

दिलीप कुमार के जीवन से सीखें युवा

अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर राष्ट्र ने ही नहीं, अपितु कई अन्य देशों ने भी जिस प्रकार उनको श्रद्धांजलि दी, वह स्वामी विवेकानंद के इस कथन कि मनुष्य अपार शक्ति का भंडार है, आवश्यकता उसे सही दिशा देने की है, को ही चरितार्थ करती है। एक फल विक्रेता के पुत्र को फिल्म उद्योग के साथ-साथ अनगिनत संस्थाओं की ओर से सम्मान मिला तो यह उनकी कड़ी मेहनत, लगन व ऊर्जा से। युवा पीढ़ी को इससे सीख लेनी चाहिए। भारतीय सिनेमा के इस भीष्म पितामह के साथ वास्तव में राज कपूर, देवानंद, शम्मी कपूर वाले एक युग का अवसान हुआ है। कालजयी फिल्म आनंद में एक संवाद है कि जिंदगी लंबी नहीं अपितु बड़ी होनी चाहिए। दिलीप साहब ने तो दोनों तरह के जीवन का आनंद लिया। अधिसंख्य युवाओं वाले इस राष्ट्र को ऐसी हस्ती की जिंदगी से प्रेरणा लेना ही उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि होगी। सिनेमा पर उनकी गहरी छाप इतिहास में हमेशा कायम रहेगी।

डा. मनोज कुमार शर्मा, स्याना

कोविड नियमों का करते रहें पालन

आइआइटी कानपुर के प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने गणितीय माडल सूत्र के आधार पर आकलन करते हुए कोरोना की तीसरी लहर के आंकड़े अक्टूबर के पहले सप्ताह से बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। उनके मुताबिक यह लहर एक नवंबर से बढ़ सकती है, जो 15 नवंबर के बाद कम होगी। यह दूसरी लहर जैसी खतरनाक होगी या नहीं, इसका अंदाजा लगाना बाकी है। तीसरी लहर को कम करने के लिए अभी से सावधानियां बरतनी होंगी। कोविड-19 के जो नियम हैं, उनका पालन करना होगा। तीसरी लहर को घातक होने से रोकने के लिए मास्क पहनना व शारीरिक दूरी रखना बेहद जरूरी है। केंद्र व राज्यों की सरकारों को भी अपने जितने भी अस्पताल है, उन्हें हर दृष्टि से सर्वगुणसंपन्न करना होगा। इसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सरकार तैयारियां तो भरपूर कर रही है, लेकिन कहीं कमी बेशी न रहे इसके उपाय भी करते रहने होंगे। देश दूसरी लहर में काफी कुछ खो चुका है।

हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721

This PDF was originally uploaded To The English Newspaper L-- Banna SA (https://t.me/English_Newspaper_L_Banna)one else Backup chennal @NEWS_Backup_L_Banna

12 हजार वोट ही ज्यादा प्राप्त हुए थे पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष को विपक्ष की तुलना में। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान के नेतृत्व में 25 लाख से ज्यादा वोट लोजपा को मिले थे।

आजकल



शिखा गौतम
शोधार्थी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

दस्तक देती आइएस के आतंक की आहट

लव जिहाद हमारे देश में अनेक स्वरूपों में सामने आ रहा है। मतांतरण के बाद आइएस के लड़ाकों से विवाह करने वाली केरल की चार युवतियां परिस्थितिजन्य कारणों से वर्तमान में अफगानिस्तान की जेल में बंद हैं। हालांकि इनके पतियों की मौत हो चुकी है और अब इन युवतियों ने वतन वापसी की इच्छा जताई है, जिस पर विचार भी किया जा रहा है, लेकिन इस मामले में भारत सरकार को बहुत ही सोच–समझकर निर्णय लेना होगा, क्योंकि संबंधित फैसले से भविष्य में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रभावित होने की आशंका बनी रह सकती है



आइएस के प्रति भारतीय युवतियों के बढ़ते आकर्षण को देखते हुए भारत सरकार को समय रहते सतर्क होना होगा, ताकि आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से पैदा होने वाली किसी भी चुनौती से समय रहते निपटा जा सके। फाइल

हाल ही में यह मामला संज्ञान में आया है कि केरल की चार युवतियां अफगानिस्तान की जेल में हैं। पड़ताल से यह भी पता चला है कि मतांतरण के बाद ये सभी युवतियां आइएसआइएस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान के खुरासान प्रांत गईं और फिलहाल वहां की जेल में बंद हैं। उनके स्वजनों ने भारत सरकार से उन्हें वापस लाने की गुहार लगाई है। वहीं अफगानिस्तान की सरकार भी इन युवतियों को वापस भेजने के लिए तैयार है। दरअसल ये चार युवतियां वही हैं जो मतांतरण के बाद मुस्लिम बनीं। माना जाता है कि इनके मतांतरण की वजह ऐसे मुस्लिम युवकों से संबंध रहे जो आइएसआइएस से जुड़े थे या फिर उससे प्रभावित थे। ये युवतियां उन्हीं के साथ अफगानिस्तान गई थीं। इस मामले का एक पहलू यह भी है कि आइएस से इनका जो भी जुड़ाव रहा, वह मुस्लिम युवकों से उनके संबंधों के कारण ही रहा। उल्लेखनीय यह भी है कि वे सभी युवक विभिन्न हमलों में मारे जा चुके हैं।

इसी घटनाक्रम के तहत मतांतरित युवतियों में से एक (निमिषा उर्फ फातिमा) की मां के द्वारा केरल हाई कोर्ट में अपनी बेटी को वापस लाने के लिए याचिका दायर की गई है। चूंकि यह मामला आतंकवाद, चरमपंथ, नागरिकता और भावना आदि कई तथ्यों से जुड़ा हुआ है लिहाजा इन युवतियों की वापसी पर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। समाज का एक तबका जहां इन युवतियों को वापस लाकर भारतीय कानून के तहत कार्रवाई करने का पक्षधर है, वहीं दूसरी ओर एक वर्ग तो इन्हें वापस लाने के ही विरोध में है।

भारत तक सीमित नहीं मामले: देखा जाए तो यह एक वैश्विक परिघटना के भारतीय पक्ष को दर्शाता है। कट्टरता का समर्थन और उसके अनुपालन के लिए आतंकवादी गतिविधियों और संगठनों में शामिल होने के उदाहरण विश्व के लगभग सभी देशों में मौजूद हैं। वर्ष 2015 में करीब 85 देशों के 30 हजार लोग आइएसआइएस में शामिल हुए। 'द सूफन सेंटर' की 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप से बड़ी संख्या में लोग लड़ाकों के रूप में आइएस में शामिल हुए। इनमें सबसे ज्यादा संख्या में मध्य एशिया से शामिल हुए। हालांकि इस्लामिक देशों में सरकारें और बहुसंख्यक जनसंख्या आइएस के कट्टर, क्रूर और आतंकवादी तरीकों का पक्षधर नहीं है और स्वयं को इन प्रतिबंधित संगठनों से दूर ही रखना चाहते हैं। आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए यूरोप और अमेरिका जैसे महाद्वीपों में भी वर्ष 2001 के बाद से आकर्षण बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। इन संगठनों में शामिल युवतियों को 'जिहादी ब्राइड्स' कहा जाता है। ऐसा देखा गया है कि अधिकांश युवतियों के आइएस में शामिल होने की मुख्य वजह प्रेम संबंध और विवाह से जुड़े हैं।

कट्टरता का वैश्विक परिदृश्य: आकड़ों के आधार पर देखें तो यूरोप में बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड से सबसे बड़ी संख्या में वहां के नागरिक न केवल आइएस में शामिल हुए, बल्कि इस आतंकवादी संगठन से सहानुभूति रखने वाले लोगों की संख्या भी तुलनात्मक रूप से कहीं ज्यादा है। इस आतंकवादी संगठन से जुड़ने वाले लोगों की औसत उम्र यहां करीब 24 वर्ष है। इनमें इस्लामिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ ही इस्लाम में मतांतरित होने वाले लोग भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, मूल रूप से इस्लामिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की तुलना में मतांतरित लोगों में आइएस जैसे संगठनों को लेकर ज्यादा आकर्षण देखा गया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर काउंटर टेररिज्म (आइसीसीटी) की 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड से इस्लामिक स्टेट में शामिल विदेशी लड़ाकों का प्रतिशत क्रमशः आठ, 23, 12 और 16 प्रतिशत है।

गौरतलब है कि यूरोप और अमेरिका में हुए अलग-अलग शोध यह बताते हैं कि पैदाइशी मुसलमानों की तुलना में मतांतरित मुस्लिमों में कट्टर प्रवृत्तियों की तरफ जाने की आशंका कहीं अधिक होती है और इसके कारण को मूलतः इस्लाम को सही तरह से न समझने, किसी विशेष आकर्षण के तहत इस्लाम अपनाने, कट्टर गतिविधियों से शीघ्र प्रभावित होने और अपने धर्म में अच्छे अनुभवों का न होना हो सकते हैं। ये सभी कारण या तो एक साथ या इनमें से कोई एक भी न केवल मतांतरण, परंतु कट्टरपंथ की ओर झुकाव और आतंकवादी गतिविधियों में परस्पर भागीदारी को भी सुनिश्चित करते हैं।

इन जिहादी ब्राइड्स के अपने वतन वापसी का सबसे चर्चित मामला ब्रिटेन की शमीमा बेगम का है। शमीमा बेगम 15 साल की उम्र में आइएस में शामिल होने के लिए यूके से सीरिया गई और इसके बाद उसने इस्लाम में मतांतरित एक डच नागरिक से शादी कर ली। उसके तीन बच्चे हुए, लेकिन सभी की नवजात अवस्था में ही मृत्यु हो गई। करीब 21 साल की उम्र में वर्ष 2019 में जब उसने सीरिया से यूके वापसी की इच्छा जताई तो वहां के तत्कालीन रक्षा सचिव ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए उसकी नागरिकता समाप्त कर दी और इस प्रकार उसे वापसी की इजाजत नहीं दी गई।

कट्टरपंथ को रोकने के लिए विभिन्न यूरोपीय देशों द्वारा चरमपंथ निरोधी नीतियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। इनमें कई बार चरमपंथ और आतंकवाद को विभिन्न यूरोपीय देशों के द्वारा समानार्थी शब्द के रूप में और कहीं पूरी तरह अलग करके देखा गया है। कट्टरपंथ को मूलतः ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जिसमें समाज में दूरगामी परिवर्तन की इच्छा रखने वाले लोग ऐसे परिवर्तनों को स्वीकार करने और दूसरों से स्वीकार कराने के लिए दबाव बनाते हैं जो कई बार अलोकतांत्रिक और उदार विचारों से इतर होते हैं। ये परिवर्तन समाज की मूल संरचना और इनमें निहित मूल्यों के अस्वीकरण से प्रभावित होते हैं जो कभी-कभी पूरी व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर देते हैं। अतः इस तरह की परिस्थितियों को पनपने से रोकने और बदलने के लिए विभिन्न देशों ने कट्टरपंथ निरोधी नीतियों को भी इसी प्रकार से विभिन्न देशों में अलग अलग प्रारूप दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व में कट्टरपंथ को लेकर परिभाषा और नीतिगत स्तर पर तमाम विविधताएं हैं जिनमें कहीं कट्टरपंथ को पूर्ण तौर पर आतंकवाद और चरमपंथ से जोड़कर देखा जाता है तो कई देशों में इन विभिन्न शब्दावलियों को उनके अलग अलग प्रकारों से समझा जाता है। इसी प्रकार से कट्टरपंथ निरोधी कार्यक्रम और चरमपंथ निरोधी प्रक्रिया भी एक दूसरे से भिन्न है। जहां कट्टरपंथ निरोधी कार्यक्रम पूरी तरह से कट्टरपंथ को रोकने के लिए प्रेरित है, वहीं दूसरी ओर चरमपंथ निरोधी प्रक्रिया के तहत विभिन्न देश इस्लामिक स्टेट से वापस आए नागरिकों को स्वीकार करने के बाद उन्हें अपने समाज में शामिल करने का प्रयास करते हैं।

ऐसा हो निर्णय ताकि भविष्य के लिए बने नजीर

आइएस जैसे संगठनों में शामिल होने के बाद यदि कोई अपने वतन वापस लौटने और वहां की सामाजिक धारा में शामिल होने की इच्छा जताता है तो इस संदर्भ में भारत और यूरोपीय देशों में फर्क है। हाल के वर्षों में यूरोपीय देशों में मतांतरण का मामला न केवल तेजी से बढ़ा है, बल्कि इस्लामिक स्टेट में शामिल होने वाले मतांतरित मुस्लिमों की संख्या भी भारत के मुकाबले ज्यादा है। भारत में वर्ष 2019 में आइएस के प्रति सहानुभूति रखने वाले 155 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूरोप में कुल आबादी के करीब छह प्रतिशत इस्लाम को मानने वाले हैं। पूरी दुनिया से यदि तुलना करें तो यह आंकड़ा करीब दो प्रतिशत बैठता है।

तत्कालीन घटनाक्रम इन सभी बहसों को भारत में लाकर केंद्रित करता है, जहां भारत की चार युवतियों ने मतांतरण के बाद आइएस से जुड़ने (जो कि जिहादी ब्राइड्स का ही एक उदाहरण है) के बाद अब भारत वापसी की इच्छा जताई है। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ये सभी अफगानिस्तान की जेलों में बंद हैं। चारों युवतियों को भारत लाकर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और भारतीय दंड संहिता का सेक्शन तीन किसी भी भारतीय द्वारा किए गए अपराध के लिए (भारत के भीतर या बाहर) भारत में ही कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान करता है।

भारत के मामले में यह बहस एक जटिल मुद्दा है जिसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। उपरोक्त युवतियों को वापस लाकर और भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा चलाकर उन्हें फिर से समाज में शामिल करने की बात की जा रही है। हालांकि यहां कुछ बातें विचारणीय हैं। पहला, भारत की सुरक्षा का मुद्दा है जहां इस तरह के चरमपंथियों को बिना किसी पर्याप्त प्रमाण के न्यायिक व्यवस्था की तरफ से छूट मिलने की पूरी उम्मीद है और यह कहना कि भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को चार युवतियों से कोई खतरा नहीं है, एक तरह से पूरे मामले को कम करके आंकने जैसा है। दूसरा, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि किसी भी व्यक्ति के कट्टरपंथ से संबंधों का पता लगाना संभव नहीं है। इसके साथ ही यूरोप और भारतीय परिस्थितियों की भिन्नता को समझना आवश्यक है। जनसंख्या और प्रति व्यक्ति सुरक्षाकर्मियों की संख्या, खुफिया तंत्र और तकनीक जैसे कारकों को समझना बेहद आवश्यक है। तीसरा, विवाह की इच्छा रखते हुए मतांतरण बेशक एक व्यक्तिगत तरजीह है, किंतु यह कहीं न कहीं लव जिहाद की तरफ इंगित करता है जो आगे जाकर कट्टरपंथ में परिवर्तित होता दिखाई पड़ता है।

इस पूरे प्रकरण को यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो दूसरे देशों के अनुभवों को भी देखना और समझना जरूरी है। यह समझना भी आवश्यक है कि धर्म विशेष के नाम पर जो भी लोग कट्टरपंथ को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग करते हैं और इसके जरिये किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में सहभागी बनते हैं या उन्हें बढ़ावा देते हैं, उनके लिए सुधरने के अवसर किस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए। इसके अलावा, यह पूरा मुद्दा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ा है जिसकी किसी भी कीमत पर उपेक्षा नहीं की जा सकती है। लिहाजा इस तरह के मामलों पर बेहद गंभीरता से निर्णय लेना होगा, ताकि भविष्य में यह अपनेआप में एक नजीर की तरह भी हो।

खरी-खरी

गंभीरता का पैमाना

डॉ. तीरथ सिंह खरबंदा

आपकी शुभकामनाओं से मैं आज के दौर में भी वैसा गंभीर नहीं हूं कि जिसको लेकर कोई चिंता का विषय बने या जिसके बारे में सुनकर दुश्मनों की तो छोड़िए देनदारों तक को मन ही मन प्रसन्नता अथवा लेनदारों को चिंता महसूस होने लगे।

लोगों का कहना है कि मुझे चुनाव समाचारों से ज्यादा महामारी को लेकर गंभीर होना चाहिए। घर के लोगों की मुझसे यह अपेक्षा है कि मुझे अब गंभीर हो जाना चाहिए। मैं उनकी अपेक्षा पर एकदम खरा उतरा हूं और हर विषय में अभी तक कम से कम गंभीर बना हुआ हूं। कहते हैं उम्र का तकाजा भी गंभीरता की दरकार करने लगता है, परंतु मैं ऐसा नहीं मानता।

वैसे भी गंभीरता कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु तो है नहीं कि दौड़े-दौड़े गए और खरीद लाए और उसे ओढ़कर आड़े वक्त में अपना काम निकाल लिया।

कई पद और रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि जिनके साथ गंभीरता ओढ़ने की अनिवार्य शर्त होती है, कुछ के साथ वह मुफ्त में भी मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे एक के साथ एक मुफ्त वाली स्कीम आज हर बाजार में है। पद पाते ही कई लोग अकस्मात अति गंभीर हो उठते हैं, जिन्हें अभी तक लोग कतई गंभीरता से नहीं लेते थे वे अब झोला छापों की तरह गंभीर से गंभीर मामलों का चुटकियों में हल खोजने का दावा करने लगते हैं।

शादी होते ही गंभीर हो जाने वाले मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसे मामलों में हमने लक्ष्य को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है।

दैनंदिनी गंभीर समस्याओं से गुजरकर हर आम व्यक्ति भी आज अच्छा खासा गंभीर है। इन दिनों महामारी से गंभीर होने वालों से कहीं ज्यादा संख्या महंगाई और बेरोजगारी से गंभीर होने वालों की है। स्थिति चाहे जितनी गंभीर, चिंताजनक या तनावपूर्ण हो, रहती हमेशा वह शासन के नियंत्रण में है। इसीलिए अक्सर हमें समाचारों में पढ़ने और सुनने को मिलता है कि स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है।

गंभीरता के लिए अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन इजाद नहीं हुई है जिसको लगवाते ही कोई व्यक्ति गंभीर हो जाए और न ही कोई ऐसा प्रमापी यंत्र बाजार में आया है जिससे किसी व्यक्ति की गंभीरता का स्तर नापा जा सके।

ट्वीट-ट्वीट

स्पष्ट है कि केंद्र में नया मंत्री बनने के लिए यह जरूरी नहीं था कि ट्विटर पर फॉलोअर की संख्या लाखों में हो। ऐसे कई नए मंत्री बने हैं, जिनके फॉलोअर केवल हजारों में हैं। इसलिए अगर आपके फॉलोअर भी कम हैं तो उदास न हों। यह प्रसिद्धि या योग्यता का पैमाना नहीं।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सात वर्षों के दौरान रेल मंत्रालय का चरणबद्ध तरीके से अ-राजनीतिकरण कर दिया है। अब किसी दिग्गज नेता के पास इसकी कमान नहीं रह गई। यह पार्टी के लिए चंदा जुटाने वाला जरिया भी नहीं रहा। न तो लंबी-चौड़ी बजट कवायद और न ही अव्यावहारिक घोषणाएं। अश्विनी वैष्णव के आने से रेल मंत्रालय का कायाकल्प पूरा हुआ।
सिद्धार्थ जराबी@szarabi

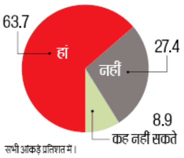


मंत्रिपरिषद विस्तार के अगले दिन ही मंत्रियों के नए और बदले हुए तेवर नजर आए। तीन मंत्रियों द्वारा दो-टूक ब्रीफिंग देखकर अच्छा लगा। बस यह महज एक दिन का आयोजन नहीं होना चाहिए। समय की यही मांग है कि दुष्प्रचार की काट के लिए आपको त्वरित और निरंतर आधार पर सही सूचनाएं देना बहुत आवश्यक है।
मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

यह देखकर खुशी मिल रही है कि तमाम स्टार्ट-अप जल्द ही भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होंगे और आइपीओ के जरिये पूंजी जुटाने जा रहे हैं। अमिताभ कांत@amitabhk87

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या जिन केंद्रीय मंत्रियों को बाहर किया गया, वे हटाए जाने लायक ही थे?



सभी आकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या समान नागरिक संहिता के निर्माण का समय आ गया है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

मंत्री कुछ पैदल हुए हैं उसके निहितार्थ,
नए मोर्चे पर जरा लक्ष्य साधिए पार्थ।
लक्ष्य साधिए पार्थ न चूके पुन: निशाना,
रखता नहीं महत्त्व सिर्फ मंत्री बन जाना।
रहो देखते भाग्य रोज ही खोले जंत्री,
इससे तो ना आप बने रह सकते मंत्री।
- ओमप्रकाश तिवारी



आलोक मिश्रा
स्थानीय संपादक, बिहार

बिहार डायरी

वाकई सधेंगे बिहार में साधे गए समीकरण

राजनीति में जो दिखता है, वो होता नहीं और जो होता है, वो दिखता नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में बिहार की हिस्सेदारी भी कुछ ऐसी ही है। सहयोगी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) व पुराने सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के पारस खेमे को शामिल कर एक तरह से सभी समीकरण साधे गए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वाकई ये सध गए हैं इस पर राजनीतिक गलियारे की फुसफुसाहट कुछ और ही कह रही है। फिलहाल अभी सब शांत दिख रहा है। अपने कोटे से एक मंत्री कम करके जदयू व पारस खेमे को समाहित कर भाजपा फिर एक बार बड़प्पन दिखाती दिख रही है, लेकिन खलबली हर तरफ मची है।

दो साल पहले मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद मंत्रिमंडल में जदयू को एक पद दिया जा रहा था, जिसने उसे दरकिनार कर दिया था। इस बार तीन से चार पद की दावेदारी थी। नीतीश सहित पूरी जदयू भले ही शांत थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह (आरसीपी) केंद्र में अपनी हिस्सेदारी की आवाज लगातार उठा रहे थे। आरसीपी पूर्व आइएएस हैं और नीतीश से उनका साथ 23 साल पुराना है। दोनों एक ही जिले नालंदा से आते हैं और जातिवाद में जकड़ी बिहार की राजनीति में दोनों एक ही जाति से हैं। लेकिन इधर दोनों के बीच सबकुछ ठीक-ठाक दिखाई नहीं दे रहा था। मंत्रिमंडल के लिए पहला नाम जदयू संसदीय दल के नेता ललन सिंह का माना जा रहा था। लेकिन विस्तार के समय दिल्ली से केवल आरसीपी को फोन आया और वे नीतीश से मिलकर दिल्ली निकल लिए। तब भी यही हवा बनी थी कि चार मंत्री जदयू कोटे से बनाए जा रहे हैं। लेकिन बाद में केवल आरसीपी सिंह ने ही कैबिनेट मंत्री की शपथ ली और बाकी के अरमान धरे रह गए। दो साल पहले के



जदयू से एकमात्र मंत्री : आरसीपी सिंह। फाइल



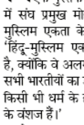
हाथ लगी बाजी : पशुपति कुमार पारस। फाइल

नकारे गए फार्मूले पर मान जाना भाजपा से कम सीटें पाकर मुख्यमंत्री बने नीतीश के कद पर सवाल खड़ा कर रहा है और ललन सिंह समेत ऐसे नेताओं को बेचैन भी जो केंद्र में जाने के अरमान पाले थे।

आरसीपी सिंह पार्टी के अध्यक्ष हैं और केंद्र से सौदेबाजी के लिए वही अधिकृत थे। नीतीश बार-बार यही दोहरा भी रहे थे। अब केवल आरसीपी को मंत्री पद मिलने पर हर तरफ भले ही चुप्पी हो, लेकिन भीतर की बेचैनी ऊपर से शांति दिखाते हुए रिस रही है। एक व्यक्ति-एक पद के आधार पर आरसीपी के बजाए किसी और को अध्यक्ष बनाने की चर्चा भी होने लगी है। ललन सिंह या हाल ही में पार्टी में आए और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा है, लेकिन बैकवर्ड की राजनीति करने वाली जदयू में फारवर्ड ललन का अध्यक्ष बनना समीकरण में फिट नहीं हो रहा इसलिए उपेंद्र पर निगाहें ज्यादा टिकी हैं। उनके जिलों के दौरे तय हो गए हैं। जिसमें टीकाकरण का हाल लेने से लेकर दलित टोलों तक में बैठकें वे करेंगे। आरसीपी ने भी जल्दी ही इस्तीफा देने को कह भी दिया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने यह कहकर विरोध की चिंगारी भड़का दी कि तीन साल तक आरसीपी ही बने रहेंगे। पार्टी की मजबूती में उनका बहुत योगदान है। उमेश की बात का ही असर है कि शुक्रवार को सुबह ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंच गए। राजनीतिक गलियारे में नाराजगी की बात बही, लेकिन दोनों ने इसे नकार दिया। अब आगे पता चलेगा कि शांति बनी रहेगी या कुछ और ही गुल खिलेगा?

दूसरी तरफ चाचा-भतीजा (पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान) के बीच बंटी लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) में बाजी पारस के हाथ लगी और वे भाई रामविलास पासवान की जगह मंत्रिमंडल में स्थान पा गए। विधानसभा चुनाव में मोदी के हनुमान बने चिराग को उम्मीद थी कि उनकी पार्टी पर मजबूत पकड़ होने के कारण पारस को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने ऐसा होने पर कोर्ट जाने की धमकी भी दी थी। अब भाजपा से उनका मोहभंग हो गया है। अब वे जनता के बीच सहानुभूति बटोरने के लिए जिले-जिले यात्रा कर रहे हैं और साथ ही पारस गुट को मान्यता देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट भी चले गए हैं। अब देखना है कि कद्दावर मंत्री रविशंकर प्रसाद को हटाकर बिहार में जदयू को समाहित करने वाली भाजपा ने रामविलास की जगह चिराग के बजाए पारस को तवज्जो देकर जो दांव चला है, वह कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में सत्तापक्ष को विपक्ष से मात्र 12 हजार वोट ज्यादा मिले थे। जबकि चिराग के नेतृत्व में 25 लाख से ज्यादा वोट लोजपा पाई थी, जिसने भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारे थे। इस घटनाक्रम के बाद तेजस्वी लगातार चिराग पर टकटकी लगाए हैं।

मंथन



पीयूष द्विवेदी
संस्कृति के जानकार

राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान

मोहन भागवत ने हिंदू–मुस्लिम एकता को लेकर जो कुछ कहा है, उसका उद्देश्य चुनावी राजनीति के संकीर्ण दायरे से कहीं बड़ा और व्यापक है जिसे समग्रता में समझा जाना चाहिए

पिछले दिनों राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू-मुस्लिम एकता के संदर्भ में कहा कि, 'हिंदू-मुस्लिम एकता की बात भ्रामक है, क्योंकि वे अलग नहीं, बल्कि एक हैं। सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। हम एक ही पूर्वज के वंशज हैं।'

मोहन भागवत के इस वक्तव्य के बाद देश के राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा जहां संघ प्रमुख के कथन का समर्थन किया गया है, वहीं विपक्ष के अनेक नेताओं के सुर इसके विरोध में रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हों या बसपा प्रमुख मायावती अथवा एआइएमआइएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, इन सब विपक्षी नेताओं ने इस वक्तव्य का विरोध किया।

विचार करें तो इस विरोध के पीछे विशुद्ध राजनीतिक कारण हैं। चूंकि आगामी कुछ माह के भीतर देश में उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में विपक्ष को लगता है कि संघ प्रमुख ने यह वक्तव्य मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ लाने की रणनीति के तहत दिया है, जिससे आगामी चुनावों में भाजपा को लाभ मिल सके। यही कारण है कि जाति-मजहब के आधार पर अपनी राजनीति चमकाने वाले दलों और नेताओं को संघ प्रमुख का यह वक्तव्य बहुत चुभ रहा है और वे इसके विरोध में लामबंद हुए हैं।

बहरहाल, राजनीति का तो चरित्र ही ऐसा है कि इसमें हर बात को चुनावी लाभ-हानि की कसौटी पर रखकर देखा जाता है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि संघ भाजपा के साथ भले हो, लेकिन अपने आप में वह कोई राजनीतिक संगठन नहीं है और न ही संघ प्रमुख कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं। अतः उनके वक्तव्य को राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं है। आज जब देश में जाति-धर्म के नाम पर विद्वेष की घटनाएं आए दिन देखने-सुनने को मिल रही हैं, ऐसे समय में देश के लोगों को उनकी वास्तविक पहचान से अवगत कराकर उनमें एकजुटता की भावना पैदा करने वाले इस तरह के वक्तव्य समय की आवश्यकता बन गए हैं। इस पर विवाद होना दुर्भाग्यपूर्ण ही है।

मोहन भागवत का वक्तव्य न केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, बल्कि संविधान की भावना के अनुरूप भी है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि देश में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा अपने शासन के दौर में बड़े पैमाने पर हिंदुओं को जबरन मतांतरण के जरिये मुसलमान बनाया गया था। आज देश के जो मुसलमान हैं, वे उन मतांतरित हिंदुओं की ही संतानें हैं। अतः मूल रूप में वे हिंदुओं से अलग नहीं हैं। यह एक ऐतिहासिक सच है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा, बौद्ध, जैन, सिख आदि मतों का मूल भी हिंदू मत में ही है। ऐसे में मोहन भागवत ने इस देश के सभी लोगों का डीएनए एक बताया, तो इसमें गलत क्या है?

गौर करें तो मोहन भागवत ने अपने वक्तव्य में हिंदुओं के प्रभुत्व की बात नहीं की है, बल्कि यह कहा है कि 'हम एक लोकतंत्र में हैं और यहां हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता है। यहां केवल भारतीयों का वर्चस्व हो सकता है।' यह बात देश के संविधान की भावना के अनुरूप है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में देश के नागरिकों को 'हम भारत के लोग' कहकर संबोधित किया गया है, जहां इस देश के नागरिकों की पहचान एक भारतीय के रूप में निश्चित हो जाती है। वैसे यह पहचान केवल आजादी के बाद अस्तित्व में आए संविधान से ही नहीं है, अपितु प्राचीनकाल से है। यह प्रसंग सर्वविदित है कि दुष्यंत पुत्र राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत का वंशज होने के आशय से ही महाभारत में कृष्ण द्वारा अर्जुन को अनेक अवसरों पर 'भारत' कहकर संबोधित किया गया है। यह 'भारत' ही अब हमारी राष्ट्रीय पहचान का सूचक भारतीय हो चुका है।



सभी भारतीयों का डीएनए एक है : मोहन भागवत। फाइल

भारतीयों को उनकी वास्तविक पहचान से भटकाने की कोशिश देश में लंबे समय से होती आई है। अंग्रेजों द्वारा इतिहास में आर्य आक्रमण सिद्धांत के जरिये आर्यों को बाहरी साबित करने की जो कुचेष्टा की गई उसका निर्वाह आजाद भारत के वामपंथी इतिहासकारों ने भी किया। यह सिद्ध करने का प्रयास होता रहा है कि आर्य बाहर से आए और यहां के मूल निवासियों को खदेड़कर यहीं बस गए। लेकिन जब राखीगढ़ी के अवशेष सामने आए तो उन्होंने इन वामपंथी प्रपंचों को बेनकाब कर दिया। राखीगढ़ी से प्राप्त कंकाल के अवशेषों की जांच के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि पिछले कम से कम बारह हजार साल से एशिया का जीन एक ही रहा है, अतः आर्य यहीं के निवासी थे। कई अन्य तथ्यों के भी सामने आने से नई अवधारणाएं सामने आईं।

कहने का आशय यह है कि समय के साथ अलग-अलग संस्कृतियों के संपर्क व प्रभाव से भले ही देश की आबादी के एक हिस्से की जीवनशैली और पूजा-पद्धति में अंतर आ गया हो, परंतु इस देश के सभी निवासियों का मूल एक ही है। वे महाभारत काल में 'भारत' से संबोधित होते थे, आज उनकी पहचान भारतीय है और इसी पहचान के साथ देश को आगे बढ़ना है। मोहन भागवत ने अपने वक्तव्य में इसी पहचान द्वारा राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान किया है। जो लोग इससे सहमत नहीं हैं, वे कहीं न कहीं भारतीयता की भावना से ही असहमत हैं।

This PDF was originally uploaded To The English Newspaper L-- Banna SA (https://t.me/English_Newspaper_L_Banna)one else Backup chennal @NEWS_Backup_L_Banna

50 पर्यटक ही एक बार में जा सकेंगे मसूरी के कैम्पटी फाल। कोविड प्रोटोकाल के तहत टिहरी जिला प्रशासन ने लिया फैसला।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 10 जुलाई, 2021

बंगाल

मंत्रियों की नियुक्ति के मायने

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को बड़े स्तर पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। इसमें कई दिग्गज नेताओं की मंत्री पद से छुट्टी हो गई। मीडिया में इस बदलाव और विस्तार को आने वाले समय में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है। परंतु बंगाल के परिप्रेक्ष्य में इसकी कहानी कुछ और है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के सात वर्षों के कार्यकाल में पहली बार बंगाल से एक साथ चार मंत्री बनाए गए हैं। पहले कार्यकाल में तो केवल दो ही मंत्री थे। दूसरे कार्यकाल में भी अब तक दो ही मंत्री थे। भले ही वे चार कनिष्ठ मंत्री हैं, लेकिन इसके निहितार्थ बड़ी रणनीति हो सकती है।

देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का हर निर्णय के पीछे दूरगामी बड़ी रणनीति होती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने बंगाल के कूचबिहार के भाजपा सांसद निशिथ प्रमाणिक चुनाव बाद हुई हिंसा से लेकर कानून-व्यवस्था को लेकर काफी मुखर रहे हैं। राजवंशी समुदाय से आने वाले निशिथ प्रमाणिक तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आए हैं और उनका प्रभाव भी अच्छा खासा है, जिसकी वजह से पिछले लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में भाजपा के प्रभाव विस्तार में उनकी भूमिका अहम रही है। अमित शाह के डिप्टी के रूप में वह निश्चित रूप से कानून और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ताकि न केवल बंगाल की खराब कानून व्यवस्था की स्थिति को उजागर किया जा सके, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। दरअसल भाजपा के कई कार्यकर्ता तृणमूल के हमलों व धमकियों से भयभीत व आतंकित होकर पार्टी छोड़ रहे हैं।

बंगाल के परिप्रेक्ष्य में कहानी कुछ और है। प्रधानमंत्री मोदी के अब तक के कार्यकाल में पहली बार बंगाल से चार मंत्री बनाए गए हैं। पहले कार्यकाल में सिर्फ दो मंत्री थे

वहीं बंगाल के अलीपुरद्वार के सांसद व चाय बागान श्रमिकों के बीच काफी प्रभाव रखे वाले जान बारला को भी मंत्री बनाया गया है, ताकि विधानसभा चुनाव परिणाम और हिंसा से हताश पार्टी कार्यकर्ताओं समेत समर्थकों में जोश भरा जा सके।

इसी तरह से मतुआ समुदाय को साधने के लिए शांतनु ठाकुर और आदिवासी प्रभाव वाले जंगलमहल के मतदाताओं को साधने के लिए डॉक्टर सुभाष सरकार को मंत्री पद दिया गया है।

हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल से ही मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो को अपना पद खोना पड़ा है और उधर महिला चेहरा देबश्री चौधरी की भी कुर्सी चली गई। परंतु राज्य के चार क्षेत्रों से चार मंत्री बनकर भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग रणनीति बनाई है जिसके नतीजे भविष्य में सामने आ सकते हैं।

उत्तर प्रदेश

सामने आई नई चुनौती

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वैरिएंट के दो मरीजों की पुष्टि ने स्वाभाविक ही चिंता की लकीरें गहरा दी हैं। दोनों ही मरीज गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में पाए गए थे। इनमें देवरिया जिले के मरीज की मौत हो चुकी है, जबकि बीआरडी मेडिकल कालेज की रेजीडेंट डाक्टर होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो चुकी हैं। इस पूरे मामले में राहत की बात यह है कि इंस्टीट्यूट आफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलाजी नई दिल्ली को दोनों मरीजों के स्वजन और संपर्क में आए अन्य सौ लोगों की जांच में नए वैरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी, डेल्टा प्लस की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। नेपाल के सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि सीमा पार से संक्रमण की आशंका अधिक है।

उल्लेखनीय है कि देश के कई राज्यों में डेल्टा प्लस वैरिएंट का संक्रमण काफी पहले ही पुष्ट हो चुका है। यह वैरिएंट अधिक खतरनाक है। इतना कि खांसी, जुकाम और गले में खराश जैसे लक्षणों से ही मरीज को मौत के मुहाने तक जल्द पहुंचा देता है। इसकी भयावहता को देखते हुए केजीएमयू, डा. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, सीडीआरआइ, एनबीआरआइ, चाइल्ड पीजीआइ और जिम्स में जांच की व्यवस्था की गई है। हालांकि, इनमें से किसी भी लैब ने नए वैरिएंट के मिलने की पुष्टि नहीं की है, मगर जैसी सतर्कता की अपेक्षा है, वह बरती नहीं जा रही।


कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन। फाइल

यह समझ से परे है कि कोरोना गाइड लाइंस जारी करने में जो तत्परता दिखाई जाती है, वही चुस्ती उनका अनुपालन कराने में क्यों नहीं नजर आती

वर्तमान महामारी के संदर्भ में समझ से परे यह भी है कि कोरोना गाइड लाइंस जारी करने में जो तत्परता दिखाई जाती है, वही चुस्ती उनका अनुपालन कराने में क्यों नहीं नजर आती। अधिकांश जिलों से आ रही तस्वीरें गवाही देती हैं कि वहां कोविड प्रोटोकाल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिम्मेदार अफसर मौन हैं। यह जानते हुए भी कि यह अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है। सबने देखा-भोगा भी है कि बेड, आक्सीजन और दवाओं के लिए किस तरह हाहाकार मचा था। इसीलिए, सरकार को टीकाकरण पर तो फोकस बनाए ही रखना चाहिए, बरती जा रही सार्वजनिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार अफसरों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए।

हरियाणा

बचाना ही होगा तालाबों को

तालाब हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों की इस सोच के परिचायक थे कि जल की एक एक बूंद सहेजी जानी चाहिए थी। हरियाणा सरकार जल-संरक्षण की दिशा में तालाबों के महत्व को देखते हुए अस्तित्व खो चुके तालाबों का सेटेलाइट सर्वे कराने जा रही है। यह सरकार संवेदनशील प्रयास है। तालाबों को पुनर्जीवन प्रदान करना हमारे अपने जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए आवासीय क्षेत्रों में लगभग 21 हजार तालाब जो लुप्त हो चुके हैं, उन्हें इस सेटेलाइट सर्वे के दौरान तलाशा जाएगा और उनका राजस्व अभिलेखों के साथ मिलान किया जाएगा और फिर उनको पुनर्जीवन देने का कार्य प्रारंभ होगा। यदि ऐसा हो सका तो प्रदेश का भूजल स्तर भी बढ़ेगा और गांवों का सौंदर्य व भाग्य भी संवरेगा।

जिन शहरों में भी तालाबों पर कब्जे हो गए हैं, यदि खाली करा लिए गए तो वे तालाब भी जलाशय के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और यह उस शहर के लोगों के हित में होगा। हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की योजना यह भी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंबाला से लेकर दिल्ली सीमा तक दोनों तरफ 14 तालाबों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए। ये तालाब एक तरह से लघु पिकनिक स्थल होंगे। विचारणीय है कि तालाबों को पुनर्जीवन मिलना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि हरियाणा में भूजल स्तर काफी नीचे पहुंच गया है।


जल संरक्षण की दिशा में बढ़ते कदम। फाइल

हरियाणा में 21 हजार तालाब लुप्त हो चुके हैं, सरकार उनको पुनर्जीवन देने का प्रयास कर रही है

इसके कई कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण तालाबों का समाप्त हो जाना है। जो बचे हुए हैं, उनपर भी लोग कब्जा करते जा रहे हैं। अभी पांच-सात दशक पहले तक हमारे हर गांवों और शहरों में कई-कई तालाब होते थे। वर्षा-जल का उनमें संचय होता था। उससे भूजल का स्तर बना रहता था, साथ ही उन तालाबों में पशु-पक्षी पानी पीते थे। अन्य कई प्रकार से भी उस जल का उपयोग होता था। तालाबों के समाप्त होने का एक कारण यह भी है कि पहले गांवों में आवास कच्चे होते थे। तालाबों से मिट्टी निकालकर बनाए जाते थे। इससे तालाबों की गहराई कम नहीं होने पाती थी। अब ऐसा नहीं होता। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रतिवर्ष तालाबों की खोदाई हो और उनमें जमा हो जानी सिल्ट बाहर निकाली जाए।

उत्तराखंड

व्यावहारिक बने अटल आयुष्मान योजना

प्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड में पेश आ रही दिक्कतों का संज्ञान लेना एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। बशर्ते सरकार पूरी शिद्दत के साथ इसमें सामने आई तमाम खामियों को दूर करने का प्रयास करे। कारण यह कि गोल्डन कार्ड की खामियों का मुद्दा राज्य कर्मचारी और पेंशनर बीते कई महीनों से उठा रहे हैं। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन इसमें अभी तक कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। देखा जाए तो प्रदेश सरकार द्वारा आमजन के लिए लागू की गई अटल आयुष्मान योजना और राज्य कर्मचारियों व पेंशनर के लिए गोल्डन कार्ड योजना बेहद अहम हैं। उल्लेखनीय है कि कैशलेस उपचार की सुविधा देने वाली इस स्वास्थ्य योजना से लाखों परिवार जुड़े हुए हैं। हालांकि इस योजना के लागू होने के बाद इसमें कई खामियां सामने आई हैं। विशेष रूप से पेंशनर व राज्य कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड में। दरअसल, इस योजना में ओपीडी, यानी अस्पताल में भर्ती होने से पहले चिकित्सक की सलाह से लेकर विभिन्न जांच इन्हें खुद अपने खर्च पर करानी पड़ रही हैं। इसके बाद इन्हें विभाग से प्रतिपूर्ति सरकारी दरों पर हो रही है। इतना ही नहीं, इसमें अलग-अलग इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों की पहचान की गई है। यानी, अगर मरीज एक अस्पताल में भर्ती है और उसे दूसरी ऐसी बीमारी है, जिसके इलाज के लिए वह अस्पताल अधिकृत नहीं है, तो उसे दूसरी बीमारी के इलाज के लिए अधिकृत अस्पताल में ही जाना पड़ेगा। अन्यथा जिस अस्पताल में वह भर्ती है, वहां दूसरी बीमारी के इलाज के लिए उसे अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे।

आयुष्मान और गोल्डन कार्ड की विसंगतियों का सरकार ने संज्ञान लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये तमाम विसंगतियां जल्द दूर होंगी

कोरोना की दूसरी लहर में इस तरह की विसंगतियों से गोल्डन कार्ड धारकों को खासी परेशानी हुई। इसके साथ ही सरकार ने इलाज की जो दरें निर्धारित की हैं, उसे देखते हुए कई बार सूची में शामिल अस्पताल भी मरीजों के इलाज से कन्नी काट रहे हैं। हालांकि, कई मामलों में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई की है, बावजूद इसके शिकायतें कम नहीं हो रही हैं। निश्चित तौर पर यह गोल्डन कार्ड की खामियों के कारण ही हो रहा है। संबंधित प्राधिकरण को इस कार्ड से जुड़ी तमाम व्यावहारिक समस्याओं का आकलन करते हुए इसके सभी पहलुओं की समीक्षा करनी चाहिए ताकि लाभार्थियों को किसी तरह की समस्या न हो।

सरकार को चाहिए कि वह इन समस्याओं का संज्ञान लेते हुए इनके निराकरण के लिए कदम उठाए। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए, ताकि मरीजों को खामियों से हो रही समस्या से राहत मिल सके।

हल्की और मजबूत हुई बुलेटप्रूफ जैकेट, एके-56 की गोली भी न भेद पाएगी

विक्सन सिक्रोड़िया, कानपुर

सैनिक अब हल्की बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकेंगे। सिलिकान मिलाकर बनाई गई बोरान कार्बाइड की बुलेटप्रूफ जैकेट ज्यादा सुरक्षा देने वाली और महज नौ किलो की होगी। यह ज्यादा मारक क्षमता सहन करने में सक्षम होगी। अभी तक बोरान कार्बाइड (कार्बनिक यौगिक) की ही बनी ऐसी जैकेट का वजन साढ़े 10 किलो होता था। साल भर शोध के बाद तैयार यह जैकेट यूनाइटेड स्टेट्स (यूएस) की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट आफ जस्टिस (एनआइजे) के मानकों पर खरी है। दो-तीन मीटर से मारी गई एक-56 की गोली भी इसे भेद नहीं पाएगी और न ही गोली के निशान पड़ेंगे। भारतीय सेना के लिए इसका परीक्षण चल रहा है। कसौटी पर खरी उतरने के बाद सेना जल्द इस अत्याधुनिक बुलेटप्रूफ जैकेट का इस्तेमाल कर सकेगी। खास बात यह कि इस जैकेट की धमक विदेश तक पहुंच गई है। कई देशों ने सेना और पुलिस के लिए जैकेट का आर्डर दिया है।

एनसीएफडी कंपनी, पनकी के प्रबंध निदेशक मयंक श्रीवास्तव कहते हैं कि सिलिकान बोरान कार्बाइड का उपयोग करके बनाई गई इस जैकेट का हल्की होने का कारण यह है कि यह स्टील की तुलना में हल्की व उससे कई गुना मजबूत होती है। सिलिकान क्रिस्टल होता है और काफी कठोर भी। इसे बोरान कार्बाइड के साथ मिलाकर 2730 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलाकर आर्मर प्लेट बनाई जाती है। सिलिकान व बोरान कार्बाइड मिलाने से वजन घटा है। अभी तक बुलेटप्रूफ का मैटीरियल हैवी होता था। जैकेट हल्की भी हुई है और क्षमता भी बढ़ी है।

थोड़ा वजन घटना भी बड़ी बात : मयंक श्रीवास्तव बताते हैं कि बुलेटप्रूफ जैकेट में थोड़ा वजन कम होना बहुत बड़ी बात होती है। इसका कारण यह है कि सैनिकों को उन ऊबड़-खाबड़ स्थानों पर हथियारों के साथ चलना होता है, जहां सामान्य रूप से चलना भी आसान नहीं होता है। ऐसे में भारी जैकेट पहनकर चलना उनके लिए बड़ी चुनौती होती है। जैकेट का वजन यदि कम होगा तो सैनिकों को चलने व दौड़ने में आसानी होगी। इसी बात को ध्यान में रखकर यह जैकेट बनाई गई है।


सिलिकान मिलाकर बनाई गई बोरान कार्बाइड की बुलेटप्रूफ जैकेट। सौ. उद्यमी मयंक

- सिलिकान बोरान कार्बाइड से बनी, स्टील की तुलना में हल्की और ज्यादा मजबूत
- मारक क्षमता सहने की शक्ति बढ़ाई, सैनिकों के लिए बेहद सुविधाजनक साबित होगी

आत्मनिर्भर होकर चीन को पीछे छोड़ा

उद्यमी मयंक श्रीवास्तव बताते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उत्पाद यहीं बनाए जाने से अब कई देशों से आयात कम हुआ है। सबसे हल्की बुलेटप्रूफ जैकेट बनाकर चीन को हम पीछे छोड़ रहे हैं। विदेश में अब भी 10 किलो से ज्यादा वजन की ही जैकेट इस्तेमाल होती हैं और उनकी लागत भी भारतीय जैकेट के मुकाबले ज्यादा है।

ब्राजील, बांग्लादेश, चिली से मिले आर्डर

उद्यमी बताते हैं कि यह जैकेट कड़े शोध का परिणाम है। रक्षा क्षेत्र में निगमीकरण के बाद से निजी रक्षा उत्पाद बनाने वाले उद्यमियों के लिए राहें खुल गई हैं। रक्षा विभाग के सहयोग व उसके दिशा निर्देश के आधार पर इस जैकेट को परीक्षण के लिए ब्राजील, चिली, बांग्लादेश, कीनिया, तंजानिया व नाइजीरिया भेजा गया। वहां मानक पर खरी उतरने के बाद पुलिस फोर्स व सेना ने भी इसे लेने की इच्छा जताकर आर्डर भी दिया है।

शिक्षा के लिए संघर्ष

पढ़ाई से रोकने पर युवती ने मां और भाइयों पर दर्ज कराया केस

जागरण संवाददाता, हरिद्वार : अब वह समय चला गया जब लड़कियां माता-पिता के अनुचित फैसलों को भी चुपचाप स्वीकार कर अपने सपनों को मार लेती थीं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में एक परास्नातक युवती ने आगे की पढ़ाई नहीं करने देने और घर का काम कराने पर अपनी मां और भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है और युवती इस समय अपनी बुआ के घर में रह रही है।

हरिद्वार के रोहालकी गांव निवासी रूपा देवी (30) ने पुलिस से शिकायत की थी कि उनकी मां स्मृति, भाई घनश्याम और रूपेश उन्हें पढ़ने नहीं देते हैं। वह एमए (परास्नातक) कर चुकी हैं और आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून जाना चाहती हैं, लेकिन स्वजन नहीं जाने दे रहे हैं। उनसे घर का काम कराया जाता है। जब वह पढ़ने के लिए कहती हैं तो उनके साथ गाली-गलौज और पिटाई की जाती है। साथ ही उन्हें मारने की भी धमकी दी जाती है। इसके बाद वह 27 मई से रुड़की में अपनी बुआ के घर रहने लगीं। इस संबंध में उन्होंने पुलिस में लिखित शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। एसओ संजीव थपलियाल ने बताया कि इस संबंध में स्वजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

शांति का कथित संदेश दे नक्सलियों ने मप्र को हथियारों की आपूर्ति का गढ़ बनाया

मोहम्मद रफीक, भोपाल

मध्य प्रदेश में नक्सली गतिविधियां बढ़ने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन नक्सलियों ने यहां के लिए अलग तरीके अपनाए हैं। नक्सली मध्य प्रदेश को हथियारों की आपूर्ति के ठिकाने के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। यही वजह है कि नक्सली यहां किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से बचते रहे हैं। प्रदेश में तीन प्रमुख स्थानों पर हथियारों की आपूर्ति महाराष्ट्र से होती रही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इन स्थानों पर घने जंगल की मौजूदगी नक्सलियों को हथियार देने वाले आरोपितों के लिए आसान बनाती रही है।

प्रदेश पुलिस के प्रस्ताव पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिंडौरी को नक्सल प्रभावित घोषित किया है। इससे प्रदेश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या अब तीन हो गई है। सूत्रों के अनुसार, मध्य प्रदेश में नक्सलियों ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया, ताकि सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान इस समस्या की ओर न जाए। इस तरह वे कथित शांति का अहसास करवाते रहे। पुलिस पड़ताल में पता चला है कि प्रदेश के कई जंगलों का नक्सलियों तक पहुंचाए जाने वाले हथियारों के आपूर्ति केंद्र के तौर पर उपयोग किया जा रहा था। यहां हथियार नक्सलियों को उपलब्ध कराए जाते और इसके बाद नक्सली अपने नेटवर्क के माध्यम से इन्हें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड भेज देते थे। हाल ही में नक्सलियों को हथियार उपलब्ध कराने वाले आरोपितों की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ में पता चला है कि हथियार मुख्यरूप से राजस्थान से खरीदे जाते थे। यहां से उन्हें महाराष्ट्र ले जाया जाता था और फिर महाराष्ट्र की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के जिलों से इन्हें नक्सलियों तक पहुंचाया जाता था।

- राजस्थान से हथियार लाकर महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों से प्रदेश में की जाती एंट्री
- सीधे नजर में न आएं, इसलिए प्रदेश में नहीं करते बड़ी वारदात

हथियारों के साथ ऐसा होता था रूट

हथियारों की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र से लगने वाली बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी जिले की सीमाओं का उपयोग किए जाने की जानकारी मिली है। खरगोन जिले की झिरन्या तहसील का पाल क्षेत्र और बड़वानी जिले के सेंधवा की सीमा आरोपितों के लिए ज्यादा आसान होती थी। यह क्षेत्र घने जंगलों वाला है। साथ ही आदिवासी बहुल होने के कारण समाजसेवा के नाम पर नक्सलियों का कुछ नेटवर्क भी यहा है। इन्हीं क्षेत्रों में सिकलीगरों द्वारा अवैध हथियार बनाने का इतिहास रहा है। राजस्थान के बदमाशों के अलावा सिकलीगर भी हथियार मुहैया कराते थे।


मप्र में नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं। फाइल/इंटरनेट मीडिया



नक्सलियों पर मध्य प्रदेश पुलिस की पैनी नजर है। अभी हमने हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा है। उनके नेटवर्क का भी राजफाश हुआ है। आगे की जांच में और भी जानकारियां सामने आएंगी। सीमावर्ती राज्यों से भी सूचनाएं साझा कर रहे हैं। किसी भी हालत में मध्य प्रदेश में नक्सलियों को सिर उठाने नहीं दिया जाएगा।

– डा. नरोत्तम मिश्रा, गृहमंत्री, मध्य प्रदेश

जागरण विशेष

नंदियों के आंगन में बसा दिया सरोकारों का संसार

सुखद एहसास : शिव नंदी गोशाला के संचालकों की संवेदना से कोरोना काल में 15 हजार लोगों तक पहुंची काढ़े की अमृत-धारा

मणिकांत मयंक • फतेहाबाद

बेसहारा गोवंश। इधर-उधर भटकते थे। टोहाना शहर के कुछ संवेदनशील लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया। उनका पालन-पोषण कैसे हो, उनको आश्रय कैसे मिले? इस पर विचार-विमर्श के बाद तय हुआ कि शहर में जो 12 एकड़ का एक विवादित भूखंड है, उस पर गोवंश के लिए आश्रय स्थल बनाया जाए। जमीन का टुकड़ा था। उस भूखंड के आधे हिस्से पर गोवंश के लिए आश्रय स्थल बन गया। नाम दिया गया- शिव नंदी गोशाला। उसके बाद गोवंश के इस आंगन में उस क्षेत्र के बेसहारा गोवंश लाए जाने लगे। इनमें कुछ नंदी थे तो कुछ गाय, जो वृद्ध और अशक्त हो चुकी थीं। कोई भी दुधारू नहीं। दुधारू होतीं तो लोग बेसहारा क्यों छोड़ते। लेकिन, अब वे बेसहारा नहीं रहे।

फिर गोवंश के पानी के लिए एक एकड़ भूमि पर तालाब बनाया गया। उसमें वर्षा जल का संचय होने लगा। आवश्यकता पर उसमें पानी भी भरा जाता। शहर के लोग उनके लिए चारा लेकर भी आने लगे। फिर विचार हुआ कि क्यों न गोमूत्र और गोबर से जनोपयोगी उत्पाद बनाए जाएं। इससे कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और गोशाला का खर्च भी आराम से चलने लगेगा। सो, हवन-समिधा (लकड़ी की जगह गोबर की स्टिक, गूगल, लोबान आदि मिलाकर) बनाने का काम शुरू हुआ। गोमूत्र के औषधीय उपयोग के लिए उसकी बिक्री शुरू की गई। आज यहां 1600 गोवंश हैं और साठ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लोग यहां हवन-समिधा व घरेलू उपयोग की वस्तुएं कैसे बनाई जाएं, यह सीखने भी आते हैं।

हर घर-आंगन में हो हरियाली: जो लोग गोवंश चारा लेकर आते थे, उनके घर में भी एक दो गोवंश होते थे। गोबर देने का उनका आग्रह स्वीकार किया गया और उस गोबर का उपयोग खाद के रूप में करने का निर्णय हुआ। फिर एक नर्सरी की शुरुआत हुई, उसमें ऐसे पौधे उगाए गए जो छतों पर या अन्य स्थानों पर लगाए जा सकें। ऐसे पौधे भी तैयार होने लगे और वितरित होने लगे।

कोरोना से लड़ने के लिए काढ़ा: सब ठीक चल रहा था। लेकिन, अचानक आपदा के रूप में कोरोना आ गया। शुरू में गोशाला के लोग थोड़ा असहज हुए, लेकिन फिर तय हुआ कि क्यों न रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला काढ़ा बनाया जाए। इसमें आजवाइन, खसखस, मुलेठी, दालचीनी, काली मिर्च, छोटी व बड़ी इलायची, बुलबन-फसा, तुलसी, गिलोय, सोंठ, सौंफ पड़ती है। कोरोना की दूसरी लहर में दस हजार से अधिक लोगों को काढ़े के निश्शुल्क पैकेट बांटे जा चुके हैं। जिला आयुर्वेद अधिकारी डा. धर्मपाल पूनिया कहते हैं कि इस काढ़े की गुणवत्ता उत्कृष्ट है।





» नंदीशाला परिसर में सूख रही हवन समिधा • जागरण

« विविध रंगों में तैयार गोबर से बने दीये • जागरण

^ कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शिव नंदी संजीवनी किट तैयार करते कर्मचारी • जागरण

ऐसी गोशालाएं प्रेरणादायक होती हैं। आयोग की तरफ से इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।
– श्रवण कुमार गर्ग, अध्यक्ष हरियाणा गोसेवा आयोग।

हर काम के पीछे सामाजिक सरोकार

गोशाला संचालक व संयोजक धर्मपाल सैनी बताते हैं कि यह सब कुछ 12 गांवों के सरपंचों व पंचों के सहयोग से संभव हो रहा है। हम जो भी करते हैं, उसके पहले विचार करते हैं कि इसका समाज से क्या सरोकार है। हमने गरीबी उन्मूलन के तहत गोमूत्र-गोबर आदि के उत्पाद बनाना शुरू किया, जिससे लोगों को रोजगार मिले। पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधों की नर्सरी बनाई। जल संरक्षण के लिए तालाब की खोदाई कराई और समाज स्वस्थ रहे इसके लिए काढ़े का उत्पादन आरंभ किया।

इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

छत्तीसगढ़ में भी फिर चीनी उत्पाद से सजने लगे इलेक्ट्रिकल बाजार

राधाकिशन शर्मा, बिलासपुर

छत्तीसगढ़ में भी एक साल बाद फिर इलेक्ट्रिकल बाजार में चीनी उत्पादों का दबदबा बढ़ने लगा है। दुकानें एलईडी बल्ब, ट्यूब लाइट, झालर व पैनल समेत अन्य चीनी उत्पादों से सज गई हैं। स्टाकिस्टों के अनुसार प्रदेश के इलेक्ट्रिकल बाजार में प्रत्येक माह 50 से 55 करोड़ रुपये का व्यवसाय हो रहा है। इसके अलावा इस व्यवसाय से जुड़ी देश की नामी कंपनियां भी चीन के कच्चे माल का उपयोग अपने उत्पादों में कर रही हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश से भी इस तरह की खबर आई थी कि वहां भी चीन के उत्पादों की मांग फिर से बढ़ी है।

दरअसल, गलवन घाटी में चीन और भारतीय सेना के बीच हिंसक झड़प के बाद छत्तीसगढ़ में भी चीनी उत्पादों के बहिष्कार का सिलसिला शुरू हुआ था। स्वदेशी जागरण मंच सहित अन्य संगठनों ने इस दिशा में प्रभावी कार्य किया था। इसका असर एक साल में ही खत्म हो गया है। चीनी उत्पाद फिर बाजार में चमक बिखेरने लगे हैं। अचरज की बात ये है कि चीनी उत्पादों की कीमतों में तेजी भी आ गई है। बहिष्कार के समय जो कीमत थी, उसमें बढ़ोतरी हो गई है। स्टाकिस्ट मनीष भागवानी का कहना है कि एलईडी, बल्ब, झालर, ट्यूब लाइट सहित कच्चे माल की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। इसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। चीनी एलईडी ट्यूब लाइट 20 से 25 प्रतिशत, बल्ब 15, झालर 20 और लड़ी में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई है।

- चीनी उत्पाद के बहिष्कार का असर एक साल में ही हो गया खत्म

चीनी उत्पाद के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने या उसके बहिष्कार से पहले बाजार के लिए एक सशक्त विकल्प तैयार करना होगा। उद्योगों के लिए ठोस और स्थाई नीति बनानी होगी। तब कम दाम पर गुणवत्ता के साथ उत्पाद देश में निर्मित होंगे और बाजार को एक अच्छा विकल्प दे सकेंगे। घरेलू व्यापार एवं उद्योग को सक्षम बनाने की जरूरत है। ऐसा करके ही आत्मनिर्भर बना जा सकता है।

– हरीश केडिया, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ

This PDF was originally uploaded To The English Newspaper L-- Banna SA (https://t.me/English_Newspaper_L_Banna)one else Backup chennal @NEWS_Backup_L_Banna

अफगानिस्तान के 85 फीसद हिस्से पर तालिबान का कब्जा

संघर्ष ▸ अफगान सरकार ने आतंकी संगठन के दावे को बताया दुष्प्रचार

तालिबान ने कहा, अफगानिस्तान को दूसरे देशों पर हमले के लिए प्लेटफार्म बनने नहीं देगा

काबुल, रायटरः अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की हो रही वापसी के बीच आतंकी संगठन तालिबान तेजी से इस देश पर काबिज होता जा रहा है। उसने युद्ध प्रभावित इस देश के 85 फीसद से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यह दावा रूस की राजधानी मास्को पहुंचे तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने किया है। हालांकि अफगान सरकार ने इस बात का खंडन किया और कहा कि यह सिर्फ दुष्प्रचार है।

तालिबान प्रतिनिधिमंडल के सदस्य शहाबुद्दीन दिलावर ने मास्को में पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'आप और पूरी दुनिया को यह पता चल चुका है कि अफगानिस्तान का 85 फीसद हिस्सा हमारे नियंत्रण में आ गया है।' उन्होंने यह भरोसा भी दिया कि तालिबान अफगानिस्तान को दूसरे देशों पर हमले के लिए प्लेटफार्म बनने नहीं देगा। इधर, अफगान अधिकारियों ने तालिबान के इस दावे को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका समेत विदेशी बलों की वापसी के बीच यह सिर्फ एक दुष्प्रचार है। हालांकि कई अधिकारियों ने यह माना कि तालिबान आतंकियों का हेरात समेत कई प्रांतों के अहम जिलों पर कब्जा हो गया है। उल्लेखनीय है कि तालिबान और सुरक्षाबलों के बीच विभिन्न जिलों में संघर्ष चल रहा है।



रूस की राजधानी मास्को पहुंचे तालिबान प्रतिनिधिमंडल के सदस्य (बाएं से) सुहिल शाहीन, शहाबुद्दीन दिलावर और मोहम्मद नईम। एपी

चीन ने अपने 210 नागरिकों को निकाला

समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, चीन ने अफगानिस्तान से अपने 210 नागरिकों को निकाल लिया है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने शुक्रवार को बताया कि गत दो जुलाई को विशेष विमान से इन नागरिकों को स्वदेश लाया गया।

दहशतगर्दों ने सात पायलटों की हत्या

अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की वापसी के साथ ही तालिबान के हमले बढ़ गए हैं। उसने वायु सेना के पायलटों को भी निशाना बनाया है। अधिकारियों के अनुसार, हाल के महीनों में सात पायलटों की हत्या कर दी गई। पहले ऐसी घटना नहीं होती थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन बोले, 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा अफगान मिशन

न्यूयॉर्क टाइम्स से

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने गुरुवार को अफगानिस्तान में अपने देश के सैन्य मिशन को लेकर बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों से जारी अफगान मिशन 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। उन्होंने अपने इस फैसले का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि अमेरिका एक संघर्ष में और जानमाल के नुकसान को सहन नहीं कर सकता। अमेरिका अपने लक्ष्यों को हासिल कर चुका है।

बाइडन ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अमेरिका औपचारिक तौर पर अगस्त के आखिर में अपने सैन्य मिशन को समाप्त कर देगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने फैसले की आलोचना करने वालों से पूछा, 'हममें से कौन वहां रुकना चाहता है। ऐसे कितने लोग हैं? कितने हजार अमेरिकी यह जोखिम लेने के इच्छुक हैं? कितने लंबे समय तक वहां रहना चाहेंगे?' अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि वह मिशन पूरा होने की घोषणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह साफ कर रहे हैं कि मौजूदा अफगान सरकार के साथ ही महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की चिंता समेत इस देश का भविष्य अब अमेरिकी सेना के हाथ में नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका ने अफगान पुलिस और सेना को अपने लोगों के भविष्य की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूती देने के लिए बहुत कुछ किया है। बाइडन ने मिशन फेल होने की बात को भी नकार दिया। उन्होंने गत अप्रैल में यह एलान किया था कि 11 सितंबर से पहले अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की पूर्ण वापसी हो जाएगी। इस बीच अमेरिकी सेना ने बताया कि अफगानिस्तान से 90 फीसद से ज्यादा सैनिकों की वापसी हो चुकी है।

अहम एलान

- बोले, अफगानिस्तान का भविष्य अमेरिकी सेना के हाथ में नहीं
- अफगान सेना की मजबूती के लिए अमेरिका ने बहुत कुछ किया



जो बाइडन फाइल/इंटरनेट मीडिया

इतना महंगा पड़ा यह संघर्ष

- अमेरिका में 11 सितंबर, 2001 को आतंकी हमला हुआ था
- यह हमला अफगानिस्तान आधारित अलकायदा ने किया था
- तब से अमेरिकी बल अफगानिस्तान में आतंकियों से संघर्ष कर रहे थे
- बीते 20 वर्षों के दौरान करीब 75 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए
- 2,448 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई और 20 हजार 722 घायल हुए
- 66 हजार से अधिक अफगान सैनिकों के जान गंवाने का अनुमान है
- अफगानिस्तान से 27 लाख से ज्यादा लोगों ने पलायन किया है
- यह सबसे महंगा और सबसे लंबे समय तक चला संघर्ष माना जाता है

अमेरिका ने 10 चीनी समेत 34 कंपनियों को काली सूची में डाला

वाशिंगटन, रायटरः अमेरिका ने शुक्रवार को आर्थिक आधार पर 34 और कंपनियों को काली सूची में डाल दिया है। इसमें से दस कंपनियां चीन की हैं। इस संबंध में अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने नोटिस जारी किया है। वहीं एक अन्य सूत्र का कहना है कि अमेरिकी वाणिज्य विभाग की योजना है कि प्रतिबंध के दायरे में और चीनी कंपनियों को भी लाया जाए। सूची में 14 चीनी कंपनियों को शामिल किया जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि चीन के स्वायत्त प्रांत शिनजियांग में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों और उच्चस्तरीय तकनीकी निगरानी के कारण यह कड़ी कार्रवाई की गई है। चीन के अलावा भी विश्व के कई देशों पर कार्रवाई हुई है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने पिछले महीने ही घोषणा की थी कि मुस्लिम उइगर मुसलमानों और हानों पर जुल्म करने के खिलाफ चीनी कंपनियों पर यह कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, चीनी उप राष्ट्रपति वांग किशान ने सरकारी इंटरव्यू में कहा कि चीन और अमेरिका के बीच मतभेद बातचीत और परामर्श से सुलझाए जाने चाहिए।

पहली अफ्रीकी अमेरिकी जाइला गार्डे ने स्पेलिंग बी पुरस्कार जीता



स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 प्रतियोगिता की विजेता 14 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी जाइला अवांत गार्डे। रायटर

वाशिंगटन, प्रेट्र : वर्ष 2021 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता के 93वें संस्करण का पहला पुरस्कार पहली बार अफ्रीकी मूल की अमेरिकी लड़की जाइला अवांत गार्डे ने जीता है। 14 वर्षीय जाइला बास्केटबाल खिलाड़ी हैं। दशकों से इस प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले भारतीय अमेरिकी इस बार प्रतियोगिता में दूसरा और तीसरा स्थान ले पाए हैं। सैन फ्रांसिस्को की 12 वर्षीय चैत्रा थुमाला को दूसरा और न्यूयार्क की 13 वर्षीय भावना मदीनी को तीसरा स्थान मिला है।

अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन की उपस्थिति में यह प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्द्धा गुरुवार को हुई। इस प्रतियोगिता में प्रथम आने वाली जाइला अवांत गार्डे ने एशिया और आस्ट्रेलिया के कटिबंधीय पेड़ों का नाम 'मुराया-एमयूआरआरएवाइए' की स्पेलिंग बताई थी। इसके लिए उन्हें 50 हजार डालर का पुरस्कार मिला है।

फ्लोरिडा के ओरलैंडो में ईएसपीएन वाइड वर्ल्ड आफ स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में आयोजित प्रतियोगिता में जाइला समेत 11 लोग अंतिम दौर में पहुंचे थे। इनमें से कई भारतीय अमेरिकी थे। जाइला के कारण 93 साल के इतिहास में पहली बार कोई अफ्रीकी मूल का अमेरिकी इस पुरस्कार को जीत सका है। सीएनएन के मुताबिक इससे पहले सिर्फ एक बार जमाइका के आठवीं में पढ़ने वाले अफ्रीकी जोडी एनी मैक्सवेल ने वर्ष 1998 में यह पुरस्कार जीता था।

बास्केटबाल खिलाड़ी जाइला ने कई बास्केटबाल ड्रिबिल करने की अनूठी क्षमताओं पर तीन गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड अपने नाम कर रखे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वह एक दिन अमेरिकी महिला बास्केटबाल टीम के लिए जरूर खेलेंगी।

ब्रैन्सन और सिरीषा का कल शुरू होगा अंतरिक्ष का सफर

▸ **जेफ बेजोस से नौ दिन पहले होंगे रवाना, अंतरिक्ष के लिए होगी पहली गैर सरकारी यात्रा**

वाशिंगटन, रायटर : दशकों तक बोटिंग और हॉट एयर बैलून के जरिये लंबी यात्राएं करने वाले अरबपति ब्रिटिश नागरिक रिचर्ड ब्रैन्सन (70) अब आकाश की ऊंचाइयों को नापने के लिए रवाना होने वाले हैं। अंतरिक्ष के उनके सफर में पांच सहयात्री भी होंगे जिनमें आंध्र प्रदेश में जन्मीं भारतीय मूल की सिरीषा बांडला भी शामिल हैं। ब्रैन्सन समेत छह अंतरिक्षयात्रियों को लेकर उनका सफेद रंग का रॉकेट प्लेन 11 जुलाई को न्यू मेक्सिको रेगिस्तान से रवाना होगा। इस सफर पर रवाना होकर ब्रैन्सन ऑनलाइन कंपनी अमेजन के मालिक जेफ बेजोस को नौ दिन पीछे छोड़ेंगे। बेजोस 20 जुलाई को अपने भाई के साथ टेक्सास से अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे।

ब्रैन्सन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिस होल्डिंग इंक रॉकेट प्लेन अंतरिक्ष के लिए रवाना कर रही है। वीएसएस यूनिटी नामक इस प्लेन को वीएमएस ईव 50 हजार फीट की ऊंचाई पर पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ले जाकर छोड़ेगा। वीएमएस ईव का नाम ब्रैन्सन की मां के नाम पर रखा गया है। न्यू मेक्सिको के रेगिस्तान से शुरू होने वाली यह उड़ान 89 किलोमीटर की होगी। इसमें वायुमंडल छोड़ने के कुछ देर बाद ही यात्री भारहीनता की स्थिति महसूस करने लगेंगे। वैसे तो वर्जिन यूनिटी के मिशन में शामिल यह अंतरिक्ष यान 22 परीक्षण उड़ानें भर चुका है, चार बार यह पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर भी घूम आया है। लेकिन दो चालकों और चार यात्रियों के साथ उसकी यह पहली अंतरिक्ष यात्रा होगी।

यह यात्रा गैर सरकारी प्रयासों से नागरिकों की अंतरिक्ष यात्रा की दिशा में मील का पत्थर होगी। यह दुनिया के अमीरों के लिए पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा कराने का प्रस्ताव भी होगी। वैसे वर्जिन गैलेक्टिस का पूर्व में एक प्रयास 2014 में विफल हो चुका है। तब उसका रॉकेट प्लेन परीक्षण उड़ान के दौरान क्रैश हो गया था और उसमें एक पायलट की मौत हो गई थी।

भारत और नेपाल के बीच रेल नेटवर्क इस्तेमाल का समझौता

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को नए समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत दोनों देशों के सभी प्राइवेट कार्गो ट्रेन ऑपरेटर अब एक-दूसरे के रेल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी तक यह कार्य केवल सरकारी कंपनी कोनकोर ही करती थी।

समझौते के तहत दोनों देश किसी तीसरे देश में माल के निर्यात या आयात के लिए भी रेल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। नेपाल के निर्यातक प्राइवेट ट्रेन के जरिये अपना माल भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचा सकेंगे। भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क समझौता 2004 में हुआ था। लेकिन उसके बाद कई मौकों पर इसमें संशोधन होता रहा है। इस समझौते में हर पांच वर्ष में समीक्षा का प्रविधान है जिससे कि उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए जा सकें। ताजा समझौते से भारत और नेपाल के रेल नेटवर्क के विकास में मदद मिलेगी और उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी होगी। इससे दोनों देशों के बीच रेल संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।

पाकिस्तान से व्यापार के लिए सड़क मार्ग खोलने में चीन की आनाकानी

▸ **दोनों सरकारों के बीच गुलाम कश्मीर स्थित खुनजरेब सीमा तक व्यापार शुरू करने पर हो चुका है समझौता**

इस्लामाबाद, एएनआइ : कोविड-19 के संक्रमण के बीच पाकिस्तान के साथ अपने कारोबार के लिए चीन केवल सड़क मार्ग खोलने में आनाकानी कर रहा है। हालांकि दोनों सरकारों के बीच गुलाम कश्मीर स्थित खुनजरेब सीमा तक व्यापार शुरू करने पर समझौता हो चुका है।

चीन ने इसी साल एक मई से खुनजरेब सीमा पर व्यापार शुरू करने का फैसला लिया था। लेकिन कोविड-19 के चलते चीन इस समझौते को अब तक लागू नहीं कर पाया है। बल्कि यहां पर इससे पहले लॉकडाउन लगा हुआ था।

पाकिस्तान टुडे से मिली जानकारी के अनुसार इस्लामाबाद में 30 जून को वाणिज्य मंत्रालय में चीनी अधिकारियों से मुलाकात के बाद गिलगित-बाल्टिस्तान के निर्यातकों-आयातकों के संगठन के प्रमुख जावेद हुसैन ने बताया कि आगामी दस जुलाई से चीन सामान सीमा पार ले जाने की इजाजत दे देगा। लेकिन इस दिशा में आगे के घटनाक्रम को लेकर अभी भी संशय है। उन्होंने बताया कि बैठक में तय हुआ था कि तीन जुलाई को ही बार्डर खोल दिया जाएगा। लेकिन अब हम लोगों को दस जुलाई की दूसरी तारीख दी गई है।

समुद्र तल से पांच हजार मीटर ऊपर पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर में स्थित खुनजरेब दर्रे में चीन और पाकिस्तान के व्यापारिक मार्ग का मुख्य केंद्र होगा। यही दर्रा दक्षिण एशिया और यूरोप के बीच अहम कड़ी भी होगा।

चीन मुख्यतः कपड़े, कृषि उत्पादों और रोजमर्रा की वस्तुओं का आयात करता है और पौधों और औषधियों का निर्यात करता है। इससे पहले पाकिस्तान ने चीन से सीमा पार से व्यापार करने के लिए रास्ता खोलने को कहा था। ताकि कारोबार और दोनों देशों के लोगों के बीच मेलजोल बढ़े। पाकिस्तान स्थित चीनी दूतावास को भेजे गए पत्र में लिखा था कि एक दिसंबर 2019 को ठंड के मौसम के कारण सीमा बंद कर दी गई थी जो एक अप्रैल 2020 को खोली जाएगी। लेकिन कोरोना फैलने के कारण फिर इस सीमा को बंद ही रखा गया था।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर चीनी सेना की नजर

बीजिंग, एएनआइ : हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हवाई में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे से 1800 मील के दायरे में चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) ने कंबोडिया, तंजानिया, किरबती समेत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नए सैन्य अड्डों को स्थापित करना शुरू कर दिया है। विदेश नीति पर क्रेग सिंगलटन ने कहा कि चीन के इच्छित देशों में तंजानिया, कंबोडिया और यूएई हैं, और अब किरबिती भी इसी दायरे में आ गया है। यह सभी इलाके हवाई पर निशाना साधने के दायरे में आते हैं। इस तरह से चीन ताइवान से आगे बढ़कर भी क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद करना चाहता है।

बांग्लादेश में जूस फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 52 लोग जिंदा जले

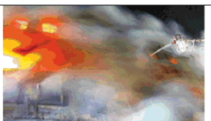
ढाका, प्रेट्रः बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहरी इलाके में स्थित छह मंजिला मैंगो जूस फैक्ट्री में लगी भीषण आग में कम से कम 52 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 50 लोग घायल हो गए हैं। आइएएनएस के मुताबिक, इस हादसे के 25 घंटों बाद इस इमारत में काम करने वाले सौ लोग गायब बताए जा रहे हैं।

नारायणगंज जिले के रूपगंज में गुरुवार को शाम साढ़े पांच बजे के करीब शेजान ब्रांड की मैंगो जूस फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 52 लोग जिंदा जलकर मर गए। घायलों में भी अत्यधिक जलने के कारण कुछ ही हालत बेहद गंभीर है। ऐसा समझा जाता है कि आग ग्राउंड फ्लोर से ही फैली है। ऊपर की मंजिलों में आग ने वहां जमा प्लास्टिक और रसायनों के कारण भीषण रूप ले लिया। इस भयावह आग से बचने के लिए फैक्ट्री में काम करने वाले तीन मजदूरों ने छत के ऊपर से नीचे छलांग लगा कर जान गंवा दी। आइएएनएस के मुताबिक, ढाका मेडिकल कालेज अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि शवों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। अब तक निकाले गए 49 शवों का डीएनए टेस्ट होगा। एम्बुलेंस में शवों को लाते हुए मजदूरों के घरवालों को रोते-बिलखते देखा जा सकता है। उन लोगों का कहना है कि लोग इमारत के अंदर फंसे हुए हैं।

रायटर के मुताबिक, हाशिम फूड एंड बेवरेजेस की इस फैक्ट्री में आम के रस के शीतल पेय बनते हैं जिसका ब्रांड नेम शेजान है। इस अग्निकांड पर काबू पाने के लिए अग्निशमन दल की 18 गाड़ियां लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में आग से बचाव का कोई उपकरण नहीं था।

जिले के फायर सर्विस के उप निदेशक अब्दुल्ला अल अरेफिन ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पाने में समय अधिक लग गया। शुक्रवार की सुबह पांचवीं और छठी मंजिल पर एक बार फिर से आग भड़क गई जिसे बाद में बुझा लिया गया। फैक्ट्री से काला धुआं काफी देर तक आसमान में उड़ता रहा। इमारत की खिड़कियां, अल्यूमिनियम के ढांचे आदि सब जलकर नष्ट हो गए। जिला प्रशासन ने इस घटना की जांच के लिए एक पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है।

- आग से झुलसकर 50 से अधिक मजदूर घायल, करीब सौ लोग लापता
- तीन लोगों की मौत छह मंजिला इमारत की छत से कूदने से हुई



बांग्लादेश के नारायणगंज जिले में शुक्रवार को एक फैक्ट्री में भीषण आग के बाद उसे बुझाने में जुटे अग्निशमनकर्मी। रायटर

चीन भी तिब्बतियों की फौज खड़ी करने में जुटा

नई दिल्ली, एएनआइः भारत की तर्ज पर चीन भी तिब्बती सैनिकों को ऊंचे पर्वतीय इलाकों में युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। इसके लिए तिब्बत मूल के सैनिकों को खास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछली सदी में चीन के साथ युद्ध के बाद भारतीय सेना ने तिब्बती मूल के युवाओं को प्रशिक्षित कर इंडियन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बनाई थी। दशकों तक इस फोर्स के अस्तित्व को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जब इस फोर्स के जवानों को ऊंचे पर्वतीय इलाकों में तैनात किया तब यह फोर्स चर्चा में आई। ऑपरेशन के दौरान इस फोर्स का एक सैनिक शहीद भी हुआ जिसका सम्मान सहित अंतिम संस्कार किया गया।

भारतीय एजेंसियों को पता लगा है कि चीनी सेना तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के युवाओं को इस फोर्स के लिए भर्ती करने के लिए अभियान चला रही है। इस फोर्स में शामिल होने वालों के लिए चीन की मंदारिन भाषा का जानना जरूरी है। साथ ही चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के प्रति समर्पण का भाव और कुछ भी कर गुजरने का भाव होना भी जरूरी है।

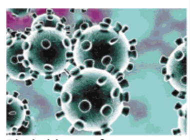
ब्रिटेन में लगातार दूसरे दिन मिले 32 हजार से ज्यादा नए मामले

▸ **रूस में जनवरी के बाद एक दिन में पाए गए 25 हजार नए केस**

लंदन, आइएएनएस : कोरोना महामारी की दो लहरों का सामना कर चुके ब्रिटेन में इस वायरस का कहर फिर तेज गति से बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में 32 हजार 551 नए मामले पाए गए। यह लगातार दूसरा दिन है, जब इस देश में 32 हजार से अधिक नए संक्रमित पाए गए। इधर, रूस में भी संक्रमण बढ़ रहा है। गत जनवरी के बाद पहली बार 25 हजार से अधिक नए केस पाए गए। इन दोनों देशों में कोरोना के डेल्टा वैरिएंट के चलते नए मामलों में उछाल बताया जा रहा है।

ब्रिटिश सरकार के डाटा के अनुसार, बीते 24 घंटे में 32 हजार 551 नए पॉजिटिव केस की पुष्टि होने से कुल मामलों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। इस अवधि में 35 पीड़ितों के दम तोड़ने से मरने वालों की संख्या एक लाख 28 हजार 336 हो गई है। इस यूरोपीय देश में अब तक तीन करोड़ 41 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है।

इधर, समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार, रूस में बीते 24 घंटे में 25 हजार 766 नए मामले पाए गए और 726 मरीजों की मौत हो गई। गत दो जनवरी के बाद पहली बार एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में नए केस पाए गए।



ब्रिटेन में कोरोना महामारी का कहर एक बार फिर तेज गति से बढ़ने लगा है।

इंडोनेशिया में डेल्टा का बढ़ा कहर

एएनआइ के मुताबिक, इंडोनेशिया में डेल्टा वायरस का कहर बढ़ गया है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,040 मरीजों की जान चली गई। 27 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अभी महज पांच फीसद लोगों का ही टीकाकरण पूरा हो पाया है।

मीना शेषमणि को बनाया गया 'यूएस सेंटर फॉर मेडिकेयर' का निदेशक

वाशिंगटन, प्रेट्र : भारतीय-अमेरिकी स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ डॉ. मीना शेषमणि को 'यूएस सेंटर फॉर मेडिकेयर' का निदेशक नियुक्त किया गया है। इस बीच, विभिन्न क्षेत्रों के तीन भारतीय अमेरिकी विशेषज्ञों को एएपीआइ विक्ट्री एलायंस के थिंक टैंक एडवाइजरी बोर्ड में शामिल किया गया है। इनके नाम मनीष बापना, पवन ढींगरा और संजय मिश्रा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नेतृत्व में स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ डॉ. मीना शेषमणि ने सत्ता हस्तांतरण के दौरान स्वास्थ्य एवं मानव सेवा एजेंसी समीक्षा दल के साथ भी काम किया था। शेषमणि मेडिकेयर कवरेज पर निर्भर 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों, दिव्यांगों और गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोगों की सेवा करने में संस्थान के प्रयासों का नेतृत्व करेंगी। 'सेंटर फॉर मेडिकेयर' के उप प्रशासक एवं निदेशक के रूप में डॉ. शेषमणि का कार्यकाल छह जुलाई से शुरू हुआ।

सीएमएस (मेडिकेयर एवं मेडिकेड सेवाओं के केंद्रों) प्रशासक चिक्विटा ब्रूक्स-लासुर ने कहा, 'एक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकारी, स्वास्थ्य अर्थशास्त्री, चिकित्सक और स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ के रूप में मीना शेषमणि सीएमएस के लिए काम करेंगी।' उन्होंने कहा, 'मेडिकेयर पर भरोसा करने वाले लोगों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, जैसा कि हम करते आए हैं और इसे आगे बढ़ाना सीएमएस की प्राथमिकता है। मैं खुश हूं कि डॉ. शेषमणि उप प्रशासक और सेंटर फॉर मेडिकेयर के निदेशक के रूप में इस संबंध में एक नया दृष्टिकोण पेश करेगी कि स्वास्थ्य नीति का रोगियों के वास्तविक जीवन पर क्या असर पड़ता है।' शेषमणि ने ब्राउन यूनिवर्सिटी से बिजनेस इकोनॉमिक्स में बीए ऑनर्स किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन से एमडी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्वास्थ्य अर्थशास्त्र में पीएचडी की है।

इस बीच, तीन भारतीय अमेरिकी विशेषज्ञों मनीष बापना, पवन ढींगरा और संजय मिश्रा को एएपीआइ विक्ट्री एलायंस के थिंक टैंक एडवाइजरी बोर्ड में रखा गया है। बापना वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अंतरिम अध्यक्ष और सीईओ हैं। जबकि ढींगरा अमेरिकन स्टडीज और आर्महेस्ट कालेज में एंथ्रोपलोजी के प्रोफेसर हैं। मिश्रा भी ड्रियू यूनिवर्सिटी में पोलिटिकल साइंस व अंतरराष्ट्रीय संबंधों के एसोसिएट प्रोफेसर हैं।

उपलब्धि

▸ **तीन भारतीय अमेरिकी विशेषज्ञ एएपीआइ विक्ट्री एलायंस के थिंक टैंक एडवाइजरी बोर्ड में शामिल**

हैती के राष्ट्रपति की हत्या में दो अमेरिकी समेत 17 हिरासत में

▸ पकड़े गए संदिग्धों में कोलंबिया के छह पूर्व सैनिक भी

▸ मौसे की मंगलवार रात उनके आवास में गोली मारकर हत्या की गई थी

▸ हमले में गंभीर रूप से घायल पत्नी का अमेरिका में हो रहा इलाज



हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मौसे की हत्या में राजधानी पोर्ट-ओ-प्रिंस में पकड़े गए संदिग्ध। एपी

पोर्ट-ओ-प्रिंस, एपीः हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मौसे की हत्या में अब तक 17 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए लोगों में दो के पास अमेरिका व हैती की दोहरी नागरिकता है। कोलंबिया की सरकार ने कहा, उसके छह पूर्व सैनिक भी पकड़े गए हैं। मौसे की मंगलवार रात उनके निजी आवास में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमले में उनकी पत्नी मार्टिनी मौसे गंभीर रूप से घायल हुईं।

हैती के पुलिस महानिदेशक लियोन चार्ल्स ने बताया कि पकड़े गए लोगों में 15 कोलंबिया के रहने वाले हैं। एएनआइ के अनुसार, हत्याकांड में 28 लोग लिप्त थे। इनमें 26 कोलंबियाई हैं। आठ लोग फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। ज्ञात हो, 53 वर्षीय मौसे वर्ष 2017 में राष्ट्रपति बने थे और पिछले दो साल से राजनीतिक अस्थिरता के बीच सरकार चला रहे थे। हिंसा के चलते यहां गरीबी की समस्या है।

दुनिया में हर मिनट भूख से जा रही 11 लोगों की जान

दुनियाभर में भुखमरी को लेकर दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रयासरत अंतरराष्ट्रीय संस्था ऑक्सफैम ने 'द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया में हर मिनट 11 लोगों की जान भूख के कारण चली जाती है। यह कोविड-19 से भी घातक है, जिससे हर मिनट सात लोग जान गंवा रहे हैं।

पांच सर्वाधिक संकटग्रस्त देश : अफगानिस्तान, इथियोपिया, दक्षिण सूडान, सीरिया, यमन



15.5 करोड़ लोग दुनियाभर में खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे

2 करोड़ बढ़ गई है संख्या पिछले साल के मुकाबले

5.20 लाख लोग कोरोना के आर्थिक प्रभाव एवं जलवायु संकट के कारण भुखमरी के कगार पर पहुंचे

सैन्य टकराव भी बड़ी वजह

रिपोर्ट के मुताबिक, करीब दो तिहाई लोगों को इसलिए भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके देश में सैन्य टकराव चल रहा है। इसके अलावा, ग्लोबल वार्मिंग और महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर खाद्य कीमतें 40% बढ़ गई हैं। इससे भी संकट बढ़ा है।

जरा ध्यान दें

महामारी के दौरान विभिन्न देशों की सैन्य गतिविधियों पर खर्च 51 अरब डॉलर बढ़ा है। भुखमरी से निजात के लिए संयुक्त राष्ट्र ने जितनी राशि की जरूरत जताई है, यह उसकी छह गुना है।

This PDF was originally uploaded To The English Newspaper L-- Banna SA (https://t.me/English_Newspaper_L_Banna)one else Backup chennal @NEWS_Backup_L_Banna

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण शनिवार 10 जुलाई, 2021
स्पोर्ट्स
12
www.jagran.com



टीम टी-20 विश्व कप को देखते हुए नए संयोजन की कोशिश करेगी। इसकी शुरुआत वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से होगी।
– जस्टिन लैंगर, मुख्य कोच, आस्ट्रेलिया

पोलार्ड ने युवा बल्लेबाजों से धैर्य रखने की अपील की

सेंट लूसिया, आइएएनएस : वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड ने युवा बल्लेबाजों, विशेषकर शिमरोन हेटमायर व निकोलस पूरन से धैर्य रखने की अपील की है। पोलार्ड ने कहा, 'टीम के रूप में हम इन दोनों युवा खिलाड़ियों के साथ काम करना चाहते हैं। हमें पता है कि भविष्य में ये दोनों क्या कर सकते हैं। हम इन युवा खिलाड़ियों का समर्थन कर इनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं।'



सबसे बड़े मुकाबले के लिए हो जाइए तैयार

- अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच खिताबी मुकाबला
- मेसी और नेमार के बीच देखने को मिलेगी भिड़ंत

रियो डि जेनेरियो, एपी : क्रिकेट में भारत बनाम पाकिस्तान, टेनिस में फेडरर बनाम नडाल, टेस्ट में आस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, ला लीगा में बार्सिलोना बनाम रीयल मैड्रिड के मैच देखने में जितना मजा आता है उससे ज्यादा रोमांच रविवार की सुबह को कोपा अमेरिका कप में देखने को मिलेगा क्योंकि एक तरफ फुटबाल का किंग ब्राजील होगा तो दूसरी तरफ महाधुरंधर अर्जेंटीना। पेले और रोनाल्डो जैसे महान खिलाड़ियों वाले देश का प्रतिनिधित्व नेमार करेंगे तो वहीं लियोन मेसी की कोशिश डिएगो मेराडोना की सत्ता को आगे बढ़ाने की होगी।

ब्राजील के रियो डि जेनेरियो के ऐतिहासिक माराकाना स्टेडियम में रोमांच का चरम दोगुना होगा क्योंकि अर्जेंटीना और ब्राजील जैसी दो प्रतिद्वंद्वी टीमें तो आमने-सामने होंगी ही, साथ में दुनिया के दो सबसे बड़े स्टार भी आमने-सामने होंगे। ये दोनों ही अपनी-अपनी टीमों को विजयी ट्राफी दिलाने के लिए जी-जान लगा देंगे क्योंकि इससे उनका कद भी बढ़ेगा। मेसी के लिए ज्यादा खास है क्योंकि वह तीन बार इस टूर्नामेंट का फाइनल हारने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। वह अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को कोई बड़ा खिताब नहीं दिला सके हैं।

स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के लिए एक साथ चैंपियंस लीग जीत चुके नेमार और मेसी अच्छे दोस्त भी हैं। दोनों को एक-दूसरे की कमजोरियों और ताकत का पता है। जहां मेसी अनुभवी हैं तो नेमार युवा हैं। दोनों की फुर्ती निश्चित ही आपको दीवाना बना देगी।

गोलकीपरों का खेल : ब्राजील के कोच टिटे टूर्नामेंट में कुछ मैचों में अलग-अलग गोलकीपर को खिला चुके हैं। एलिसन को वह ज्यादा मैच में नहीं खिला रहे हैं और उनकी जगह एडरसन को मौका दे रहे हैं। एडरसन दोनों नाकआउट मैचों में खेले थे। ब्राजील की टीम छह मैचों में दो गोल खा चुकी है और रिपोर्ट के मुताबिक टिटे फाइनल में एलिसन को खिला सकते हैं। लेकिन अर्जेंटीना के साथ ऐसा नहीं है। वह मार्टिनेज को मौका दे रहा है और उन्होंने भी टीम को निराश नहीं किया है। यहां तक सेमीफाइनल में पेनाल्टी शूटआउट में उनके द्वारा बचाई गई तीन पेनाल्टी पर ही टीम फाइनल में गई थी। मार्टिनेज के रूप में अर्जेंटीना के पास शीर्ष स्तर का गोलकीपर है और उनके रहते ब्राजील के खिलाड़ियों को गोल करना इतना आसान नहीं होगा।

डिफेंस : ब्राजील के डिफेंस का प्रदर्शन अभी तक दमदार रहा है। विश्व क्वालीफायर्स और कोपा अमेरिका को मिलाकर वह 12 मैचों में चार गोल ही खा पाए हैं। डेनिलो रेनान लोडी को उनकी भूमिका दे दी गई है। राइट बैक डेनिलो और लेफ्ट बैक लोडी को छकाना आसान नहीं है। अनुभवी थियागो सिल्वा, मारकिन्होस और एडेर मिलिताओ बारी-बारी से खेल रहे हैं ताकि जोखिम से बच सकें। वहीं, अर्जेंटीना के लिए मिडफील्ड में गेंद को पास करना महत्वपूर्ण रहेगा। डिफेंस में जर्मन पेजला को निकोलस आटेमेंडी का साथ मिलेगा और दोनों ही फ्री किक के मौके बनाते हैं जिससे गोल करने का तरीका मिल जाए। अर्जेंटीना को अगर डिफेंस को मजबूत करना है तो यह देखना होगा कि अर्जेंटीना मिडफील्ड कैसे रखता है।

मिडफील्ड : टिटे मैच में 4-4-2 की रणनीति के साथ मैदान में उतरना पसंद करते हैं। उनके स्ट्राइकर और मिडफील्डर दोनों ही मिलकर गोल दाग देते हैं और क्वार्टर फाइनल व सेमीफाइनल में मिडफील्डर लुकास पकेटा के गोल की मदद से टीम फाइनल में पहुंची थी। मिडफील्ड में गेंद को पास करना अर्जेंटीना का मजबूत पक्ष है और पकेटा को केसेमिरो व फ्रेड की चुनौती का सामना करना होगा। अर्जेंटीना के कोच 4-3-3 के साथ खेलना पसंद करेंगे।

अटैक : टिटे पहले ही साफ कर चुके हैं उनके अटैक की अगुआई नेमार ही करेंगे। टीम को खासकर नेमार को ग्रेबियल जीसस की कमी खलेगी जो रेड कार्ड के कारण इस मैच में नहीं उतरेंगे। नेमार के अलावा विनिसियस जूनियर, रोबर्टो फिरमिनो अटैक को और मजबूत करेंगे। वहीं, अर्जेंटीना के पास मेसी तो हैं ही, लेकिन लोतारो मार्टिनेज की मेसी के साथ जुगलबंदी से टीम को फायदा हो रहा है। मार्टिनेज गोल भी कर चुके हैं और उनकी जगह सर्जियो अग्यूरो को बेंच पर बैठना पड़ सकता है। एंजेल डि मारिया ने स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर अच्छा किया है। अर्जेंटीना ने मेसी को बचाने का तरीका खोज लिया है। मिडफील्डर रौद्रिगो डि पाल और जियोवानी लो सेल्सो उनके इर्द-गिर्द घेरा बनाते हैं। इसके साथ ही वे मार्टिनेज और निको गोंजालेस को अच्छे पास देने में भी कामयाब रहते हैं।

ब्राजील

फीफा रैंकिंग	गोल किए	गोल खाए
03	12	02

कोपा में इस बार प्रदर्शन: 6 कुल मैच, 5 जीत, 1 ड्रा

केसेमिरो
मिडफील्डर

केसेमिरो ने इस टूर्नामेंट में पांच मैच खेले हैं और सिर्फ एक्वाडोर के खिलाफ ही वह 28 मिनट तक मैदान पर रहे थे। अन्य मैचों में वह 90 मिनट तक खेले। कोलंबिया के खिलाफ मैच में नेमार की मदद से उन्होंने एक गोल दागा था। वेनेजुएला के खिलाफ टीम के लिए कप्तानी भी की थी।

5 मैच, 1 गोल

लुकास पेकटा
मिडफील्डर

लुकास पेकटा ने अभी तक टीम को निराश नहीं किया है। कोच टिटे ने उन्हें पांच मैचों में मैदान पर उतारा, लेकिन वह सिर्फ पेरू के खिलाफ सेमीफाइनल में ही 90 मिनट तक मैदान पर खेले थे। टीम अगर फाइनल खेल रही है तो इसका कारण पेकटा ही हैं। उन्होंने पहले क्वार्टर फाइनल में चिली के खिलाफ 1-0 और सेमीफाइल में पेरू के खिलाफ जीत में गोल दागा था।

5 मैच, 2 गोल

नेमार
फारवर्ड

ब्राजील के पास सितारों से सजी टीम है व उसके पास कई अच्छे स्ट्राइकर भी हैं। लेकिन कोच टिटे की टीम और प्रशंसक नेमार का अच्छा प्रदर्शन भी देखना चाहते हैं। मेसी की तुलना में नेमार टूर्नामेंट में दो गोल ही कर पाए हैं लेकिन वह ऐसे खिलाड़ी जो किसी भी पल मैच का रुख बदल सकते हैं। वह गोल नहीं कर पाते तो गोल करने में मदद कर देते हैं। ब्राजील को अगर यह खिताब जीतना है तो उसके लिए नेमार का चलना जरूरी है।

5 मैच, 2 गोल



रविवार सुबह 5:30
सोनी नेटवर्क

अर्जेंटीना

फीफा रैंकिंग	गोल किए	गोल खाए
08	11	03

कोपा में इस बार प्रदर्शन: 6 कुल मैच, 5 जीत, 1 ड्रा

लियोन मेसी
फारवर्ड

लियोन मेसी की मंशा देश के लिए पहला बड़ा खिताब जीतने की होगी और वह इस बार इसे जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अर्जेंटीना ने आखिरी बार 1993 में बड़ा खिताब जीता था। मेसी 2007, 2015 और 2016 कोपा फाइनल हारने वाली टीम का हिस्सा रहे और 2014 विश्व कप फाइनल में जर्मनी के हाथों पराजय झेली। मेसी इस टूर्नामेंट में शानदार फार्म में चल रहे हैं और उन्हें रोकना ब्राजील के लिए बड़ी चुनौती होगी।

6 मैच, 4 गोल

एमिलियानो मार्टिनेज
गोलकीपर

अर्जेंटीना ने इस टूर्नामेंट में तीन गोल खाए लेकिन मार्टिनेज के प्रदर्शन को कम नहीं आंका जा सकता। सेमीफाइनल में पेनाल्टी शूटआउट में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। कोलंबिया के खिलाफ मैच में उन्होंने तीन पेनाल्टी बचाई थी जिसके बाद टीम फाइनल में पहुंची थी।

5 मैच, 3 गोल

लोतारो मार्टिनेज
फारवर्ड

इटली के क्लब इंटर मिलान के लिए खेलने वाले मार्टिनेज के लिए टूर्नामेंट का यह सत्र अभी तक अच्छा रहा है। वह मैच में गोल करके मेसी के ऊपर से दबाव कम कर देते हैं। कोलंबिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में मार्टिनेज ने मेसी की मदद से ही पहला गोल किया था और उसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में भी गोल दागा था। मेसी के साथ मार्टिनेज को रोकना भी ब्राजील के लिए आसान नहीं होगा।

5 मैच, 3 गोल

आमने-सामने

107 कुल मैच — अर्जेंटीना 39 जीत, ब्राजील 43 जीत, 25 ड्रा

14 बार अर्जेंटीना की टीम कोपा अमेरिका का खिताब जीत चुकी है जबकि ब्राजील ने नौ बार यह खिताब अपनी झोली में डाला है

33 मैच दोनों टीमों के बीच कोपा अमेरिका में हुए हैं जिसमें 15 मैच अर्जेंटीना ने जीते हैं जबकि ब्राजील 10 मुकाबले ही जीत पाया है। आठ मुकाबले ड्रा रहे हैं

52 गोल अर्जेंटीना की टीम ने ब्राजील के खिलाफ कोपा अमेरिका में किए हैं जबकि 40 गोल ब्राजील कर पाया है

2019 में पिछली बार कोपा अमेरिका के सेमीफाइनल में ब्राजील ने अर्जेंटीना को हराया था। नेमार चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर थे

भिड़ंत का पुराना इतिहास

अर्जेंटीना और ब्राजील का सामना यूं तो सौ से ज्यादा बार हुआ है लेकिन फाइनल चार ही खेले। अर्जेंटीना ने 1937 में दक्षिण अमेरिकी चैंपियनशिप फाइनल में ब्राजील को 2-0 से हराया। इसके बाद 2004 कोपा फाइनल में ब्राजील ने पेनाल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना को मात दी। एक साल बाद जर्मनी में कन्फडरेशन कप फाइनल में ब्राजील ने अर्जेंटीना को 4-1 से हराया। कोपा 2007 में ब्राजील ने अर्जेंटीना को 3-0 से हराया।

राष्ट्रपतियों में भी दीवानगी

इस मैच को लेकर दीवानगी का आलम यह है कि ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोलसोनारो ने एक आनलाइन बैठक में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अलबर्टो फर्नांडिज से कहा, 'मुझे पता है कि नतीजा क्या होगा। 5-0। इस पर फर्नांडिज हंसकर रह गए।'

फाइनल मुकाबले में बेरेटिनी से भिड़ेंगे नोवाक जोकोविक

लंदन, एपी : सर्बिया के नोवाक जोकोविक भले ही विंबलडन में सीधे सेटों में जीतकर फाइनल तक पहुंच गए हो लेकिन, सेमीफाइनल में सीधे सेटों मिली यह जीत उनके के लिए आसान नहीं रही। शुक्रवार को विश्व के नंबर एक खिलाड़ी जोकोविक 12वें नंबर के खिलाड़ी कनाडा के डेनिस शापावालोव से भिड़े और हमेशा की तरह सर्बियाई खिलाड़ी इस मैच के जीतने के प्रबल दावेदार थे। लेकिन शापावालोव ने हर गेम के लिए जोकोविक को संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया और उन्हें आसानी से फाइनल का टिकट मिलने नहीं दिया। जोकोविक ने यह मैच दो घंटे 47 मिनट में 7-6 (7-3), 7-5, 7-5 से जीतकर फाइनल में पहुंच गए। वह 30वीं बार ग्रैंडस्लैम के फाइनल में पहुंचे है। वहीं, शापावालोव मैच हारने के बाद भावुक होकर कोर्ट से बाहर चले गए। हालांकि उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनके डबल्स के जोड़ीदार भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना उनके कोच के साथ बैठकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। रविवार को फाइनल मुकाबले में जोकोविक का सामना इटली के मेटेयो बेरेटिनी से होगा जिन्होंने हुबर्ह हरकैज को 6-3, 6-0, 6-7 (3-7), 6-4 से हरा दिया। हरकैज ने क्वार्टर फाइनल में रोजर फेडरर को हराकर सुर्खियों में आए थे। बेरेटिनी विंबलडन के फाइनल में पहुंचने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी हैं।

जोकोविक ने अपनी सर्व पर पहला गेम आसानी से 40-0 से जीत लिया। लेकिन दूसरे गेम में जोकोविक जब 30-15 से आगे थे तो उनके पास यह गेम जीतने का मौका था, लेकिन शापावालोव ने वापसी करते हुए 40-30 के स्कोर के बाद गेम जीतकर स्कोर 1-1 कर दिया। तीसरे गेम में शापावालोव ने शानदार फोरहैंड लगाया जिसे जोकोविक संभाल नहीं पाए। फिर 15-40 पर शापावालोव को तीन ब्रेक प्वाइंट मिले पहला वह गंवा बैठे। उनका बैकहेंड से लगा शाट नेट पर टकरा गया। दूसरे को सर्बियाई खिलाड़ी ने ड्यूस कर दिया। फिर जोकोविक डबल फाल्ट कर बैठे जिससे शापावालोव को एडवांटेज मिल गई और फिर 22 वर्षीय शापावालोव ने कोर्ट के पीछे से ग्राउंड शाट खेला जिसका जोकोविक के पास जवाब नहीं था। शापावालोव 2-1 से आगे हो गए। फिर शापावालोव ने अपनी बढ़त 5-4 तक पहुंचा दी थी। जोकोविक 10वें गेम में 30-0 से आगे चल रहे थे लेकिन कनाडा के शापावालोव ने स्कोर 30-30 कर दिया। फिर जोकोविक को पहला ब्रेक प्वाइंट मिला लेकिन शापावालोव ने स्कोर ड्यूस कर दिया फिर जोकोविक ने अगले ब्रेक प्वाइंट पर गेम जीतकर स्कोर 5-5 कर दिया। फिर जोकोविक ने स्कोर 6-5 किया तो शापावालोव ने 40-0 पर गेम जीतकर सेट को टाई ब्रेकर में धकेल दिया। टाई ब्रेकर में जब जोकोविक 3-1 से आगे थे तो कनाडा के खिलाड़ी का बैकहैंड शाट नेट से टकरा गया। लेकिन वह जोकोविक को टाई ब्रेकर में जीतने से रहीं रोक पाए।

दूसरे सेट में एक समय शापावालोव 2-1 से आगे चल रहे थे और 40-0 पर उन्हें पहला ब्रेक प्वाइंट मिला लेकिन वह अपनी गलती के कारण ही यह गेम गंवा बैठे। जोकोविक ने वापसी की और स्कोर 40-30 कर दिया और तीसरे ब्रेक प्वाइंट पर शापावालोव ने दो गलतियां की। उनका पहला होरहैंड शाट नेट से टकरा गया और स्कोर ड्यूस हो गया फिर उनका दूसरा शाट भी नेट पर लग गया जिससे सर्बियाई खिलाड़ी को एडवांटेज मिल गई और फिर उन्होंने स्कोर 2-2 कर दिया। फिर कनाडा के खिलाड़ी अगला गेम जीतकर बढ़त अपने पास रखी तो सर्बियाई खिलाड़ी ने स्कोर 3-3 कर दिया। जोकोविक इस गेम में सर्व कर रहे थे और 15-40 पर शापावालोव को पहला ब्रेक प्वाइंट मिला फिर शापावालोव ने दूसरे ब्रेक प्वाइंट पर स्कोर ड्यूस किया और फिर जोकोविक ने एडवांटेज ली तो शापावालोव ने ड्यूस कर दिया तो फिर सर्बियाई खिलाड़ी ने एडवांटेज लेकर गेम जीत लिया। फिर शापावालोव ने अच्छी सर्विस करते हुए 40-0 पर गेम जीत लिया और स्कोर 4-3 कर दिया। फिर जोकोविक ने 6-5 स्कोर करने में देर नहीं लगाई। शापावालोव सर्बियाई खिलाड़ी के खिलाफ पहला सेट प्वाइंट बचाने में सफल रहे लेकन दूसरा सेट प्वाइंट वह नहीं बचा पाए।



नोवाक ने कड़े सेमीफाइनल में डेनिस शापावालोव को हराया

जीत के बाद खुश नोवाक जोकोविक • रायटर

चार दिन देर से शुरू होगी भारत-श्रीलंका सीरीज

श्रीलंका टीम में पाजिटिव मामले आने के बाद बदला कार्यक्रम, पहले 13 जुलाई से शुरू होनी थी अब 17 को होगा पहला वनडे

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत और श्रीलंका के बीच छह मैचों (तीन वनडे व तीन टी-20) की सीमित ओवर की सीरीज के कार्यक्रम में शुक्रवार को बदलाव किया गया। यह बदलाव घरेलू टीम के शिविर में कोविड-19 के पाजिटिव मामले सामने आने के बाद किया गया। दोनों टीमों के बीच अब पहला वनडे मैच 13 जुलाई के बजाय 17 जुलाई को खेला जाएगा।

इंग्लैंड से लौटने के बाद श्रीलंका के बल्लेबाजी कोच ग्रांट फ्लावर और डाटा विश्लेषक जीटी निरोशन कोरोना पाजिटिव पाए गए थे, जिसकी वजह से श्रीलंका क्रिकेट को कड़े क्वारंटाइन की अवधि को तीन दिन के लिए बढ़ाना पड़ा। बीसीसीआइ अधिकारी ने कहा, 'हां, अब यह सीरीज 13 जुलाई के बजाय 17 जुलाई से शुरू होगी। खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसएलसी के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है। पहले वनडे सीरीज 13 जुलाई से शुरू होनी थी और इसके अंतिम दोनों मैच 16 व 18 जुलाई को खेले जाने थे। टी-20 सीरीज का आगाज 21 जुलाई को होना था।

सीरीज का नया कार्यक्रम

तारीख	मैच
17 जुलाई	पहला वनडे
19 जुलाई	दूसरा वनडे
21 जुलाई	तीसरा वनडे
24 जुलाई	पहला टी-20
25 जुलाई	दूसरा टी-20
27 जुलाई	तीसरा टी-20

टोक्यो जाने वाले दल से बात करेंगे मोदी

ओलंपिक डायरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को टोक्यो ओलंपिक में भारत की तैयारियों का जायजा लिया और यह भी घोषणा की कि वह ओलंपिक जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से 13 जुलाई को बात करेंगे। इसके तीन दिन बाद भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल रवाना होगा। कोरोना महामारी के कारण यह बातचीत वर्चुअल होगी।

मोदी ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए लिखा, 'टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल की तैयारियों का जायजा लिया। उनके टीकाकरण, लाजिस्टिक संबंधी ब्यौरे, उन्हें दी जा रही सहायता पर बात की। 130 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं 13 जुलाई को ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से बात करूंगा। उन्हें शुभकामनाएं दूंगा। हम सभी उनकी हौसलाअफजाई करें।' भारत का पहला दल 17 जुलाई को एयर इंडिया से रवाना होगा। भारत के 120 से अधिक खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है। अभी तक खिलाड़ियों की संख्या की आधिकारिक घोषणा भारतीय ओलंपिक संघ ने नहीं की है।

प्रज्वलन समारोह के साथ ओलंपिक

केटी इरफान और भावना जाट का हुआ फिटनेस परीक्षण

नई दिल्ली, प्रेट्र : पैदल चाल एथलीट केटी इरफान और भावना जाट का शुक्रवार को फिटनेस परीक्षण हुआ, जबकि ओलंपिक टीम में शामिल एक अन्य एथलीट एम श्रीशंकर को टोक्यो ओलंपिक में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 21 जुलाई को अपनी फिटनेस साबित करनी होगी। भावना और इरफान दोनों ही 20 किमी पैदल चाल में भाग लेंगे।

नार्वे के कोच की मदद से अभ्यास कर रहे अंगद

नई दिल्ली : भारतीय स्कीट निशानेबाज अंगद वीर सिंह बाजवा की ओलंपिक तैयारियां कुछ अलग तरह से चल रही हैं क्योंकि वह इटली में रहकर नार्वे में अपने विदेशी कोच टोरे ब्रोवाल्ड की मदद से तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसके अलावा वह लोनाटो में कुवैत और कतर की राष्ट्रीय टीम के सदस्यों के साथ भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। टोक्यो के लिए क्वालीफाई करने वाले अन्य निशानेबाज क्रोएशिया के जगरेब में कुछ कोचों के साथ ट्रेनिंग में जुटे हैं।

मशाल रिले का टोक्यो चरण शुरू: ओलंपिक आयोजकों ने शुक्रवार को ओलंपिक मशाल के टोक्यो आगमन के साथ ही प्रज्ज्वलन समारोह का आयोजन किया। इससे एक दिन पहले ही सरकार ने टोक्यो में कोरोना आपातकाल की घोषणा की थी, चूंकि डेल्टा वैरिएंट के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी वजह से मशाल रिले राजधानी की सड़कों पर आयोजित नहीं की जा सकी। टोक्यो के तटवर्ती इलाकों पर ही इसका आयोजन किया गया।

सिंधू बोले, अच्छा ड्रा मिला, लेकिन कुछ भी आसान नहीं होगा : पदक की दावेदार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि उन्हें अनुकूल ड्रा मिला है, लेकिन ओलंपिक में कोई भी मैच आसान नहीं होगा। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता सिंधू को हांगकांग की चियुंग एंगान यि (34वीं रैंक) और इजरायल की सेनिया पोलिकारपोवा (58वीं रैंक) के साथ महिला सिंगल्स के ग्रुप-जे में रखा गया है।

अपूर्वी का जुनून देख पिता ने घर में ही बनवा दी शूटिंग रेंज

शुभम पांडेय • नई दिल्ली

2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्डन निशाना लगाकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा की जीत से प्रेरित होकर अपूर्वी चंदेला ने भी निशानेबाज बनने की ठान ली। हालांकि, इससे पहले वह खेल पत्रकार बनना चाहती थीं, मगर बिंद्रा को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता देखकर, 15 साल की उम्र में इसी सपने को अपूर्वी ने भी जीना शुरू कर दिया। इसका आलम यह रहा कि एक बार फिर से वह टोक्यो ओलंपिक में अपने सपने को साकार करने के लिए सटीक निशाना लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

पदक पर निशाने की उम्मीद : 28 साल की अपूर्वी का यह लगातार दूसरा ओलंपिक है और इस बार वह पदक पर निशाना लगाकर स्वदेश लौटना चाहती हैं। साल 2016 रियो ओलंपिक में वह अपनी अपेक्षाओं के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी थीं। दैनिक जागरण से खास बातचीत में ओलंपिक की तैयारी को लेकर 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लेने वाली अपूर्वी ने कहा, 'क्रोएशिया में टीम के साथ तैयारी काफी शानदार चल रही है। अभ्यास के साथ-साथ मैचों में खेलने का भी अनुभव मिल रहा है, जो कि आगामी ओलंपिक से पहले हमारे लिए काफी जरूरी है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस बार पदक जीतकर आऊं।'



अपूर्वी चंदेला • फाइल फोटो, ट्विटर

अपूर्वी के स्वर्ण पदक

साल	टूर्नामेंट	स्थान
2014	राष्ट्रमंडल खेल	ग्लासगो
2019	विश्व कप	म्यूनिख
2019	विश्व कप	नई दिल्ली
2019	विश्व कप	रियो डि जनेरियो

10 पदक अभी तक भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम कर चुकी हैं

खेलों से रिश्ता पुराना

अपूर्वी के परिवार का खेलों से काफी पुराना रिश्ता है। उनकी मां बिंदु बास्केटबाल खिलाड़ी थीं और उनके चचेरे भाई-बहन भी निशानेबाजी से जुड़े थे। बिंद्रा के ओलंपिक स्वर्ण जीतने की घटना ने अपूर्वी को बंदूक उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और साल 2009 में इंडिया स्कूल निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। इसके बाद 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी श्रेणी में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने में उन्हें सिर्फ तीन साल लगे और वह आगे बढ़ती गईं। अपूर्वी ने कहा, 'यह एक शानदार सफर रहा है। एक दिन में निशानेबाज बनने का फैसला नहीं किया था। बिंद्रा सर को जीतते देखने के बाद मैंने धीरे-धीरे इस खेल में रुचि लेना शुरू किया और फिर अच्छा करने की भूख बढ़ती गई। मैंने 9-10 साल पहले ही इस खेल को अपना जीवन बनाने की ठान ली थी।'

पिता ने घर में ही बनवा दी रेंज

राजस्थान के जयपुर से आने वाली अपूर्वी को अपनी ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में नजदीकी निशानेबाजी रेंज तक पहुंचने में 45 मिनट का समय लगा करता था। जब उनके घर वालों को पता चला कि निशानेबाजी रेंज तक जाने-आने में काफी समय लगता है तो उनके पिता ने घर में ही निशानेबाजी रेंज बनवा दी, जिससे अपूर्वी की काफी फायदा हुआ। इस तरह टोक्यो ओलंपिक तक के सफर में परिवार के योगदान के बारे में अपूर्वी ने कहा, 'ओलंपिक तक के सफर में हर एक इंसान का योगदान रहा है, माता-पिता, कोच, दोस्त, परिवार और टीम के साथी। सभी ने मेरा काफी सहयोग किया है।'

This PDF was originally uploaded To The English Newspaper L-- Banna SA (https://t.me/English_Newspaper_L_Banna)one else Backup chennal @NEWS_Backup_L_Banna

दैनिक जागरण
सप्तरंग

जोश नई राहों का



शनिवार, 10 जुलाई, 2021

'सपने वे नहीं होते, जिन्हें हम सोते हुए देखते हैं, सपने वे होते हैं, जो हमें सोने नहीं देते।' देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइलमैन के नाम से मशहूर डा. एपीजे अब्दुल कलाम की यह बात युवाओं में उत्साह और जोश भरने का काम करती रही है। उन्हें अपने उद्देश्य के प्रति एकाग्र करती है। कोविड के कारण उत्पन्न हुए विपरीत हालात में खुद को सकारात्मक रखते हुए अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन अभी भी कुछ नहीं है...

खुद को साबित करने की चुनौती

भले ही हम सभी के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय है। फिर भी हमारी आखों में चमक बिखेरने वाले सपनों को पूरा करने की ताकत हमारे अंदर अभी भी है और उन्हें हमारे अलावा कोई और पूरा नहीं कर सकता। सबसे पहले हमें इसी बात को समझने की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। यह हमसे नहीं होगा, यह सोचने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा? हमें सबसे पहले अपनी मनोदशा को बदलना होगा, तभी हमारी परिस्थितियां बदलेंगी। कहीं से निकलने से लेकर, कहीं पर पहुंचने तक के सफर को तय करने के लिए हमें खुद को आत्मविश्वास से भरना होगा, क्योंकि सब कुछ हमारे आत्मविश्वास पर ही निर्भर करता है। परिस्थितियां चाहे कैसे भी क्यों न हों, हमें कठिन राह में भी आसान डगर बनानी होगी। इसलिए हमें हालात के आगे घुटने टेकने के बजाय हौसले के साथ कदम आगे बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए।



फोकस सबसे जरूरी चीज है। इसकी जरूरत केवल कंपनी चलाने में ही नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी उतनी ही है। -टिम कुक

यहां सर्च करें वीडियो एडिटिंग की फ्रीलांस जॉब्स

टेक लर्निंग



आज के दौर में अगर वीडियो एडिटिंग से जुड़े जॉब्स घर बैठे करना चाहें, तो उसकी भी सुविधा मौजूद है। कई ऐसे आनलाइन प्लेटफार्म हैं, जहां स्किल्ड वीडियो एडिटर्स के लिए तमाम तरह के कार्य मौजूद हैं। आइए जानें कहां खोज सकते हैं वीडियो एडिटिंग से जुड़ी नौकरियां...

बेहांस डाट नेट: वीडियो एडिटिंग की फ्रीलांस जॉब के लिए बेहांस (behance.net/joblist) प्लेटफार्म पर विजिट कर सकते हैं। यहां पर वीडियो एडिटिंग से संबंधित कार्य हासिल करने के लिए पहले अपनी प्रोफाइल के साथ वीडियो एडिटिंग के कुछ कार्यों को भी अपलोड करना होगा। साथ ही, प्रोफाइल को इस तरह से तैयार करें कि क्लाइंट आकर्षित हों। फिर यहां पर नियमित तौर पर निकलने वाली जाब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रीलांस जॉब के साथ फुलटाइम और इंटर्नशिप वीडियो एडिटिंग जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर आप चाहें, तो कंट्री या फिर सिटी के हिसाब से भी जाब सर्च कर सकते हैं। खासकर क्रिएटिव जाब्स के लिए यह बेहतर प्लेटफार्म है।

स्टेज 32: वीडियो एडिटिंग से संबंधित फ्रीलांस जॉब सर्च करने के लिए स्टेज 32 (stage32.com) साइट को भी ट्राई कर सकते हैं। यहां पर लोकेशन के हिसाब से जॉब सर्च करने की सुविधा दी गई है। आप फिल्म, टीवी और थियेटर इंडस्ट्री से जुड़े वीडियो एडिटिंग के कार्य को यहां पर खोज सकते हैं। यहां पर फ्री में प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं या फिर फेसबुक के जरिए भी साइन-इन करने की सुविधा दी गई है। साथ ही, इसमें मीटअप का सेक्शन दिया गया है, जिससे आपको आगामी इवेंट के बारे में जानकारी के साथ-साथ अपना नेटवर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी।

फीचर डेस्क

प्रोडक्शन हब

इस प्लेटफॉर्म पर आप फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन हाउस से जुड़े वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रोडक्शन हब (productionhub.com) पर एनिमेशन, गेम डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन आदि से जुड़े जॉब को भी सर्च करने की सुविधा है। फ्रीलांस वर्क के साथ फुल टाइम, कांट्रैक्ट, इंटर्नशिप के हिसाब से भी जॉब को सर्च किया जा सकता है।

टर्निंग प्वाइंट



डॉ. विवेक बिंद्रा
मोटिवेशनल स्पीकर एवं सीईओ, बड़ा बिजनेस



फोटो: इमेजेज बाजार

पहचानें अपने सपने



दुनिया भर में जिस तरह से पिछले करीब डेढ़ साल से कोविड महामारी ने अपने पैर पसारे हैं, ऐसे में इस स्थिति ने लोगों, खासकर युवाओं से उनके सपने, उनके लक्ष्य, उद्देश्य, उनका रोजगार और उनके जीवन के कई बड़े मायनों को छीनने या फिर दूर करने का काम भी किया है। ऐसी स्थिति में खुद को ऊर्जावान बनाए रखना किसी भी युवा के लिए थोड़ा कठिन हो गया है। यही कारण है कि आज का युवा अपने सपनों से दूर जा रहा है। भटकाव-दुविधा का सामना कर रहा है। ऐसे दौर में खुद को सकारात्मक रखकर अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना थोड़ा मुश्किल तो जरूर है, लेकिन नामुमकिन अभी भी कुछ नहीं है।

हर किसी का होता है सपना: ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी भी व्यक्ति का कोई सपना न हो। अपने सपनों को पूरा करना ज्यादा कठिन भी नहीं होता है। बस जरूरत होती है तो बस उसे पहचानने की। इसके लिए हमें अपने सपनों या ड्रीम की एक लिस्ट बनानी होगी। सभी सपनों को एक पेन की मदद से हमें अपनी डायरी में उकेरना होगा, विस्तार से समझना होगा कि हमें आखिर चाहिए क्या? और जो चाहिए, आखिर वह हासिल कैसे होगा? इन सब बातों पर गहनता के साथ विचार-विमर्श करना होगा। कुछ पन्नों पर हर एक सपने को लिखना चाहिए और उसके बारे में कल्पना करनी होगी। फिर यहीं से मिलती है आगे बढ़ने की स्पष्टता।

दरअसल, हमें अपने ड्रीम या लक्ष्य तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा मदद स्पष्टता ही करती है। इसलिए हमें आखिर करना क्या है, इस बात का निर्णय पहले लेना होगा और स्पष्ट होना होगा। जब इंसान अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट हो जाता है, तो उसके पास किसी भी बाधा को पार करने का साहस और समाधान दोनों होता है। इसलिए कंफ्यूजन को खुद से दूर रखना होगा और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना होगा, तभी सपनों को हकीकत में बदला जा सकेगा।

बाधाओं से पाएं पार: सपनों के बीच आने वाली आधी मुश्किलें और अड़चनें लक्ष्य में स्पष्टता के आ जाने से ही दूर हो जाएंगी, बाकी की परेशानियों को दूर करने के लिए हमें जरा और मशक्कत करनी होगी। हमें अपने सपने को हासिल करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाकर उस पर कुछ इस तरह काम करना होगा:

- मुश्किलों-संभावनाओं की बनाएं लिस्ट: फ्रेमवर्क बनाने के लिए हमें एक बार फिर से पेन और पेपर की मदद लेनी होगी और तीन ऐसी मुश्किलों के बारे में लिखना होगा, जो लक्ष्य को प्राप्त करने के दौरान हमारे सामने आ सकती हैं। यहां हम मुश्किलों को तो लिखेंगे ही, साथ ही तीन बड़ी संभावनाओं को भी पेपर पर लिखेंगे। हम सभी जानते हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाना आसान काम नहीं होता है। परेशानियां और मुश्किलें मानों चट्टान की तरह सीना ताने हमारे सामने खड़ी होती हैं। लेकिन क्या हो, अगर हम मुश्किलों की पहले ही एक लिस्ट बना लें और उन्हें संभावनाओं में बदलने का जुनून अपने भीतर भर लें। इस तरह से हम अपनी सफलता की तरफ एक और कदम बढ़ा लेते हैं।
- साथ देने वालों को लाएं साथ: कोई भी सफल व्यक्ति जब भी अपनी सफलता की यात्रा के बारे में बात करता है, तो उसमें वह ऐसे लोगों के नाम भी लेता है, जो उसके जीवन में बेहद सराहनीय रहे हैं, जिनसे उसे सकारात्मक सपोर्ट मिला है, हिम्मत मिली है। दरअसल, सपोर्ट की जरूरत हर व्यक्ति को होती है। यह हमारे शरीर के जरूरी ऑर्गन की तरह होता है। हमें भी अपनी लिस्ट में तीन ऐसे व्यक्तियों के नाम शामिल करने चाहिए, जो हमेशा हमारे लिए हितकारी हों, जिनकी आंखों में हमारे सपनों को पूरा करने की खुशी झलकती हो। ऐसे लोगों को हमें भी अपनी लिस्ट में शामिल रखना चाहिए।
- लगातार करें अभ्यास : दोस्तो, योजना हर काम की तरक्की की गारंटी तो नहीं देती है, लेकिन योजना हमारे भीतर बारंबारता का निर्माण जरूर करती है और यही बारंबारता एक अच्छी प्रैक्टिस यानी अभ्यास का रूप धारण कर लेती है। लगातार किया जाने वाला यही अभ्यास हमें अपने क्षेत्र में पारंगत बनाता है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमें सात दिन का एक मैसिव प्लान बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। ये सात दिन ऐसे होने चाहिए, जहां पर हम सपने की ओर बढ़ते हुए अपने कदमों को माप पाएं। इन सात दिनों में हम देख सकते हैं कि हमने अपने सपने को कितना प्राप्त किया है और हमारे प्लान में किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है या फिर कितनी और मेहनत की जरूरत है? यह विश्लेषण हमें अपनी कमियों को समझने और समय पर उन्हें दूर करने में भी मदद करेगा।
- सफर को तय करने का जुनून: कामयाबी पाना हर इंसान की ख्वाहिश है, लेकिन कामयाबी पाने के सफर को तय करने का जुनून किसी-किसी में ही होता है। वैसे, कामयाब व्यक्ति ऐसा कुछ अलग काम नहीं करता है। बस वह खुद पर भरोसा करता है। उसमें आत्मविश्वास, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, सटीकता, अनुशासन और लगनशीलता होती है। इन्हीं गुणों को वह अपना आदर्श बनाकर रखता है। हमें भी सफलता के लिए इन्हीं गुणों को अपने व्यक्तित्व में शामिल करना होगा।

सक्सेस मंत्रा



गगन वरमानी
संस्थापक/सीईओ, माईसन

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सार्थक पहल



आनलाइन टेक-इंजीनियरिंग साल्युशन एवं फाइनेंसिंग प्लेटफार्म 'माईसन' के संस्थापक एवं सीईओ गगन वरमानी ने सोलर यूटिलिटी प्रोडक्ट्स (रूफटाप पैनल्स) को देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। वह लोगों की सोच में बदलाव लाना चाहते हैं, इसलिए सौर ऊर्जा उत्पादों के प्रति जागरूकता लाना इनके बिजनेस माडल का एक अहम हिस्सा है। आने वाले वर्षों में इनका लक्ष्य एक करोड़ घरों तक सोलर रूफटाप पहुंचाना है। हाल ही में कंपनी ने आनसाइट एवं आफसाइट सोलर एनर्जी साल्युशन देने वाला एक नया वर्टिकल 'माईसन प्लस' लांच किया है, जो रेस्को एवं बूट माडल के तहत सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स विकसित करेगा। इनका लक्ष्य आने वाले तीन वर्षों में 200 मेगावाट की पाइपलाइन विकसित करना है। वरमानी के अनुसार, माईसन प्लस एक स्वतंत्र सब्सिडियरी के तौर पर काम करेगी, जिसके लिए 600 करोड़ रुपये निवेश करने का इरादा है।

गगन वरमानी ने एनआइटी कुरुक्षेत्र से बीटेक (मैकेनिकल) किया है। कैंपस प्लेसमेंट के दौरान ही आटोमोटिव इंडस्ट्री में नौकरी मिल गई। वहां 12 साल विभिन्न पदों पर रहते हुए चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। 2006 में मोजरबियर ज्वाइन किया। सोलर बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन संस्थापकों ने कंपनी के लिए सोलर डाउनस्ट्रीम बिजनेस स्थापित करने की अहम जिम्मेदारी सौंपी। गगन बताते हैं, मैंने जोखिम लिया। थोड़ा डर भी था। लेकिन कुछ नया करने का उत्साह अधिक था। आखिर एक पारिवारिक कारोबार में मुझे स्वतंत्र रूप से कारोबार करने का अवसर जो मिल रहा था। यहीं से एंटरप्रेन्योरशिप में पहला कदम रखा।

सीखते हुए बढ़े आगे: गगन की मानें, तो शुरू के कुछ महीने सीखने में ही लग गए। मार्केट को जाना-समझा। स्ट्रेटेजी पर कार्य किया। जब आत्मविश्वास बढ़ा, तो 2010 में अपनी कंपनी सनबार्न एनर्जी की नींव रखी। इसमें भारत समेत अमेरिका के निवेशकों ने पूंजी लगाई। वह बताते हैं, हमने मार्केट रिसर्च भी जारी रखा। इसी दौरान सोलर प्रोडक्ट्स की जरूरत का पता चला। हमने देखा कि कंपनियां बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही हैं, जबकि आम कस्टमर्स को उनकी जरूरत का सोलर प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा। इसके बाद ही सितंबर 2015 में हमने एक नया स्टार्टअप 'माईसन' लांच कर दिया, जो लोगों की हर ऊर्जा जरूरत को पूरा करता है।

बातचीत: अंशु सिंह

विजन पर था भरोसा

गगन मानते हैं कि सीख हमेशा विपरीत परिस्थितियों में ही मिलती है। 2006-07 के आसपास सोलर इंडस्ट्री उतनी विकसित नहीं थी। लोगों ने कई प्रकार की शंकाएं जताई। ग्राहकों को आश्वस्त करना एक चुनौती रहा। आर्थिक मुश्किलें आई। बैंक ऋण देने में दिलचस्पी नहीं लेते थे। लेकिन मैंने धैर्य बनाये रखा। मुझे अपने विजन पर विश्वास था। हमने ग्राहकों की पहचान कर निवेशकों से बात की। उन्होंने 25 लाख डालर का निवेश किया। ग्राहकों को सोलर पावर पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया गया। बाजार में मांग बढ़ी और हमें अच्छे नतीजे मिलने लगे।

लाइफ स्किल



डा. अनिल सेठी
मोटिवेटर एवं लाइफ कोच

शार्टकट से नहीं मिलती जीवन में कामयाबी



फोटो: इमेजेज बाजार

जीवन में बहुत से सफल लोगों के साथ मुझे काम करने या फिर उनसे मिलने का मौका मिला। सफल लोगों की किताबें पढ़ीं। इन सभी से जो सीखने को मिला, वह था जीवन में सफलता के लिए दीर्घकालीन योजना का होना। हो सकता है कि सफलता की परिभाषा हर किसी की अलग हो। एक गरीब आदमी के लिए दो वक्त का भोजन ही सफलता है। मेरी नजर में टाटा, बिड़ला, रिलायंस, मदर टेरेसा, कैलाश विद्यार्थी जैसे सभी सफल लोग हैं। मेरी सफलता की परिभाषा है कि आप जीवन में कितने अधिक लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।

जीवन का लक्ष्य: पहले की तरह आज भी अगर जीवन में आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए आपको पूरी निष्ठा के साथ अथक प्रयास करना होगा और वह भी लगातार और लंबे समय तक। अब अगर उदाहरण के तौर पर आप भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानें, तो पता चलेगा कि वह कितने गरीब घर से आये और कहां तक पहुंचे। बचपन में अखबार/ मैगजीन बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की। इसरो में डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने देश के लिए अतुलनीय योगदान किया। उसके बाद देश के राष्ट्रपति बनकर देश का नाम रोशन किया। अगर आप उनके जीवन के सार या उद्देश्य को जानने का प्रयास करें, तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई भी उनसे मिलता था, तो कलाम साहब का एकमात्र उद्देश्य उसके लिए कुछ अच्छा करना होता था और वह मिलने वाला व्यक्ति चाहे उनका सहायक हो या चाय पिलाने वाला ऑफिस बॉय या किसी देश का प्रधानमंत्री। उनका लक्ष्य एक ही होता था और वह इसमें पूरी तरह कामयाब हुए।

इसी तरह का एक और उदाहरण जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी का ले सकते हैं, जो आज बहुत बड़ी अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है। कंपनी की सफलताओं के पीछे एक इंसान का बड़ा हाथ था और वह नाम है जैक वेल्श। अब अगर आप जैक वेल्श के जीवन के बारे में पढ़ें, तो पता चलेगा कि उनका जन्म एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। अपनी पढ़ाई के दिनों में स्कूल से आने के बाद वह पास के गोल्फ कोर्स में काम करते थे। स्कूल की छुट्टियों के समय वह सड़क के किनारे जूते-चप्पल आदि बेचा करते थे। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने जीई कंपनी में ट्रेनी के तौर पर अपना करियर शुरू किया और 14 साल के बाद कंपनी के सीईओ के पद पर पहुंचे। सीईओ बनने के बाद उन्होंने एक परिवर्तन किया कि मेरे पास कोई भी शार्टटर्म प्लान लेकर मत आओ, सिर्फ और सिर्फ लांग टर्म प्लांस ही लाओ। उनके इस निर्णय ने कंपनी की काया पलट कर दी। अगर आप अपने आसपास देखेंगे, तो और भी बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे।

विश्वास के साथ मेहनत: जीवन में सफलता के लिए हम सबको भी लांग टर्म ही सोचना चाहिए और छोटी-छोटी असफलताओं की परवाह किये बिना आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। आज कोरोना के कारण हम सब किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में हम निराश न हों और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहें, तो हमको सफलता जरूर मिलेगी। हम चाहे पढ़ाई कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों या अपना कोई काम कर रहे हों, अगर हम पूरे विश्वास के साथ मेहनत करते रहेंगे, तो एक न एक दिन कामयाबी सुनिश्चित है।

आज का भविष्यफल

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: 10 जुलाई, 2021 शनिवार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या का राशिफल।
आज का राहुकाल: प्रातः 09:00 बजे से 10:30 बजे तक।
आज का दिशाशूल: पूर्व।
आज का पर्व एवं त्योहार: स्नानदान की अमावस्या।

कल 11 जुलाई का पंचांग



कल का दिशाशूल: पश्चिम।
कल का पर्व एवं त्योहार: पुष्य नक्षत्र, रथ यात्रा।
विक्रम संवत 2078 शके 1943 उत्तरायन, उत्तरगोल, ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 07 घंटे 48 मिनट तक, तत्पश्चात् द्वितीया पुष्य नक्षत्र 26 घंटे 22 मिनट तक, तत्पश्चात् अश्लेषा नक्षत्र हर्षण योग 16 घंटे 31 मिनट तक, तत्पश्चात् वज्र योग कर्क में चंद्रमा।

मेष: पारिवारिक सदस्य से तनाव मिल सकता है। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

वृष: किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। उच्च अधिकारी या घर के मुखिया का प्रोत्साहन मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में आशातीत प्रगति होगी।

मिथुन: बहुप्रतिक्षित कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। आपसी संबंधों में मधुरता आएगी।

कर्क: उदर या नेत्र विकार की संभावना है। रक्तचाप के प्रति सचेत रहें। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी।

सिंह: जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। संबंधों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य पूर्ण होगा।

कन्या: चल या अचल संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगी। किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होंगे। नए संबंध बनेंगे।

तुला: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। महिला अधिकारी का सहयोग रहेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे।

वृश्चिक: जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। आपसी संबंध मधुर होंगे।

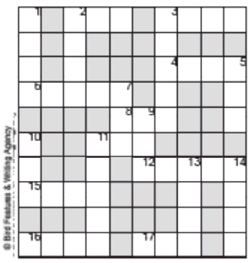
धनु: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पिता या घर के मुखिया का सहयोग रहेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी।

मकर: पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। जीवनसाथी का सहयोग रहेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी।

कुंभ: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।

मीन: जीवनसाथी का सहयोग और सान्निध्य मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। पुरुषार्थ सार्थक होगा।

वर्ग पहेली-1632



© Best Features & Writing Agency

बाएं से दाएं
2 राजा दशरथ के चार पुत्रों में से एक (3)।
3 विविध प्रकार की आकृति वाला (4)।
4 [illegible] (4)।
6 [illegible] (5)।
8 स्थान (3)।
11 [illegible] (3)।
12 [illegible] (5)।
15 [illegible] (4)।
16 [illegible] (4)।
17 [illegible] (3)।

ऊपर से नीचे
1 [illegible] (4)।
2 [illegible] (4)।
3 [illegible] (5)।
5 [illegible] (3)।
7 [illegible] (3)।
9 [illegible] (3)।
10 [illegible] (3)।
11 [illegible] (5)।
13 [illegible] (4)।
14 [illegible] (4)।

कल का हल

अ	रा	ब	नों		त्रि	ल	त्रि	ला	नों
रु			टि	कि	या				ग
नि		वों	त		ह	टा	नों		रा
क		ल			ता		सं	मी	न
र	र	क	ना					न	
	सि					नों	मी	क	नें
मों	या	नों		लें			ह		त
ला		रें	ग	टू		भों	बी		ना
मा				नों	न	र			सि
तों	ल	का	र	ना		तों	ह	ल	का

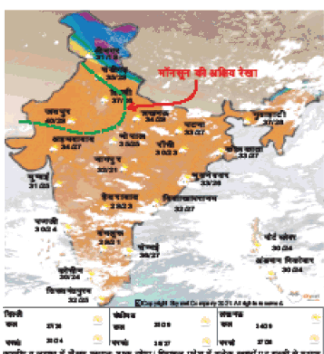
जागरण सुडोकू-1632

		5		2		4		8
2	1				3			5
		7	4		5		1	
8			3			5		7
	4	3			6		9	
9				7				4
4				3		1	8	
		9		1			4	
1			7		2			3

कल का हल

1	9	5	4	8	2	6	7	3
8	4	6	9	3	7	1	2	5
7	3	2	6	1	5	8	4	9
3	8	4	7	9	6	5	1	2
2	6	7	8	5	1	3	9	4
9	5	1	3	2	4	7	8	6
6	2	8	5	7	9	4	3	1
5	7	9	1	4	3	2	6	8
4	1	3	2	6	8	9	5	7

मौसम



कश्मीर व लद्दाख में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा व जम्मू में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। राजस्थान, पूर्वी हरियाणा और सटे पंजाब व दिल्ली में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा दक्षिण राजस्थान में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होगी।

कल पढ़ें



पीसी-फोन पर स्क्रीनशाट

अक्सर कार्य से संबंधित चीजों को सहेजकर रखने के लिए स्क्रीनशाट की जरूरत पड़ जाती है। कुछ ट्रिक्स ऐसे भी हैं, जो इस कार्य को और आसान बना देंगे। जानें कैसे पीसी, स्मार्टफोन पर आसान तरीके से ले सकते हैं स्क्रीनशाट...

This PDF was originally uploaded To The English Newspaper L-- Banna SA (https://t.me/English_Newspaper_L_Banna)one else Backup chennal @NEWS_Backup_L_Banna

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
आजकल
शनिवार 10 जुलाई, 2021
www.jagran.com

पाकिस्तान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी



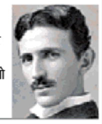
भारत के हाथों 1971 में पाकिस्तान को मिली हार के बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और बांग्लादेश के तौर पर एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र मानने में पाकिस्तान ने दो साल लगा दिए। 10 जुलाई, 1973 को नेशनल असेंबली ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया।



आंग सान सू को नजरबंदी से रिहा किया गया

छह साल नजरबंद रहने के बाद 1995 में आज ही के दिन म्यांमार की मानवाधिकार कार्यकर्ता आंग सान सू को रिहा किया गया था। बाद के दिनों में भी कई पाबंदियों का सामना करना पड़ा था। 2016 से वह स्टेट काउंसलर थीं। इसी साल फरवरी में सेना ने तख्तापलट कर उन्हें फिर बंदी बना लिया।

सस्ती बिजली और वायरलेस तकनीक के जनक हैं टेस्ला



वर्ष 1856 में आज ही के दिन क्रोएशिया में निकोला टेस्ला का जन्म हुआ था। उन्हें सस्ती बिजली, रिमोट और वाई-फाई जैसी तकनीकों का जनक माना जाता है। यूरोप में टेलीग्राफ ड्राफ्टर और इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करने के बाद 1884 में वह अमेरिका चले गए और थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम किया। तस्वीरें, संगीत, वीडियो ट्रांसमिट करने के लिए 'पॉकेट टेक्नोलॉजी' नाम से आइडिया दिया। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क ने अपनी इलेक्ट्रिक कार 'टेस्ला' इनको ही समर्पित की है।

इधर-उधर की

वीडियो गेम कलेक्शन के शौक ने बनवाया रिकॉर्ड

टेक्सास, एजेंसी : इंसान के शौक जब जुनून बन जाते हैं तभी कीर्तिमान स्थापित होते हैं। टेक्सास में भी ऐसा ही एक रिकॉर्ड बना। यहां रहने वाली 51 वर्षीय लिंडा गिलोरी नाम की महिला के शौक ने उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया। दरअसल लिंडा को आठ साल की उम्र से ही वीडियो गेम कलेक्शन का शौक था और इसी आदत के चलते उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में 1599 एलसीडी गेमिंग सिस्टम और 2430 प्लेएबल गेमिंग सिस्टम जमा कर लिए। इसके चलते उनके नाम दो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। लिंडा कहती हैं कि, उन्हें उम्मीद है एक दिन उनके कलेक्शन को म्यूजिम में प्रदर्शित किया जाएगा।



लिंडा को उम्मीद है कि उनके कलेक्शन को म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाएगा। इंटरनेट मीडिया

तेजी से खाने से बढ़ सकता है मोटापा

शोध ▶ धीमे खाने वाले बच्चों के आवेगी होने की कम होती है संभावना

अध्ययन के आधार पर स्वभाव में भी लाया जा सकता है बदलाव

वाशिंगटन, एएनआइ : अक्सर यह देखने में आता है कि माता-पिता को अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाने में बड़ी जल्दबाजी होती है। वे चाहते हैं कि बच्चा कितनी जल्दी खा ले ताकि वे कोई दूसरा काम करें। यदि आप भी यही मनोवृत्ति रखते हैं तो थोड़ा संभल जाइए। एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि तेजी से खाने वाले बच्चों में मोटापा का जोखिम ज्यादा होता है। जबकि धीमे-धीमे खाने वाले बच्चों के बहिर्मुखी (एक्स्ट्रोवर्ट) और आवेगी (इंप्लसिव) होने की संभावना कम होती है। जाहिर है कि मोटापा से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हृदय रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है।

यह शोध 'पीडियाट्रिक ओबेसिटी' नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। फिलाडेल्फिया के चिल्ड्रेंस हास्पिटल और यूनिवर्सिटी के इस शोध में बच्चों के खाने के तौर-तरीके और स्वभाव के बीच संबंधों की पड़ताल की गई। यूबी ग्रैजुएट स्कूल आफ एजुकेशन काउंसलिंग के प्रोफेसर तथा शोध के सह-लेखक मायल्स फेथ ने बताया कि यह निष्कर्ष इस मायने में अहम हैं कि तेजी से खाना और अधिक प्रतिक्रियाशील होने का संबंध बच्चों में मोटापा बढ़ने के जोखिम से है।

इस शोध से बच्चों के व्यवहार या स्वभाव के आधार पर उनके मोटापे के इलाज का भी तरीका खोजा जा सकता है। हालांकि इस संबंध में पूर्व के अध्ययनों का और विश्लेषण किए जाने की जरूरत है।

खाने की रफ्तार और स्वभाव के बीच संबंध : शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में 28 प्रतिभागियों को शामिल किया। उनके परिवार की मदद से चार से आठ साल के बच्चों के खाने की रफ्तार को धीमा कर उनके मोटापे के जोखिम का आकलन किया। अध्ययन में खाने के व्यवहार के तीन पहलुओं पर गौर किया गया। इनमें खाने को जानकर भावपूर्ण प्रतिक्रिया, खाने को देखने, सूंघने और स्वाद लेने पर प्रतिक्रिया और उसके बाद खाने की स्पीड को शामिल किया गया। इसके आधार पर बच्चों के बहिर्मुखी तथा आवेगपूर्ण व्यवहार, खुद को गुस्सा, भय और खिन्नता जैसे नकारात्मक भावों से सहज कर पाने की अक्षमता को परखा गया। इसमें ऐसा भी पाया गया कि कुछ बच्चों ने ज्यादा आत्मसंयम भी दिखाया।



खाने के तरीके पर ध्यान देना जरूरी। फाइल

आगे इस पर हो शोध

शोधकर्ताओं का कहना है कि माता-पिता बच्चों के नकारात्मक भाव को कम करने के लिए खाने का इस्तेमाल करते हैं। जैकब स्कूल आफ मेडिसिन एंड बायोमेडिकल साइंसेज के डिपार्टमेंट आफ पीडियाट्रिक्स में वरिष्ठ शोधकर्ता बट्टन का कहना है कि इस बात का भी अध्ययन होना चाहिए कि माता-पिता किस प्रकार से बच्चों को खाना खिलाते हैं और बच्चों की कैसी प्रतिक्रिया होती है। यह भी पता लगाने की जरूरत है कि क्या धीमे या बहुत ज्यादा समय में खाना खाने से आवेग भी मद्धिम पड़ता है? इस अध्ययन ने बच्चों के खाने के पैटर्न और उनके स्वभाव के बीच संबंधों को स्थापित किया है, लेकिन इसके बावजूद यह सवाल कायम है कि खाने के पैटर्न से स्वभाव निर्धारित होता है या स्वभाव से खाने का तौर-तरीका प्रभावित होता है।

फिल्म रिव्यू

★★

स्टेट आफ सीज : टेंपल अटैक

प्रमुख कलाकार : अक्षय खन्ना, समीर सोनी, गौतम रोड़े, विवेक दहिया, प्रवीन डब्बास
निर्देशक : केन घोष
अवधि : एक घंटा 50 मिनट
प्रसारण प्लेटफॉर्म : जी5

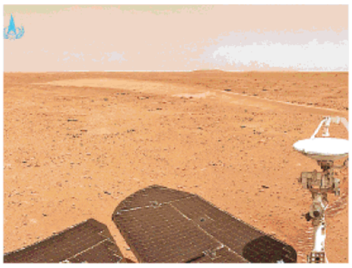
अहिंसा का संदेश, जोश की कमी



डिजिटल प्लेटफार्म पर डेब्यू करने वालों में अक्षय खन्ना का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने जी5 की फिल्म 'स्टेट आफ सीज : टेंपल अटैक' से पदार्पण किया है। यह फिल्म साल 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले पर बनी वेब सीरीज 'स्टेट ऑफ सीजः 26/11' की दूसरी कड़ी है। यह साल 2002 में गुजरात के गांधीनगर में स्थित अक्षरधाम मंदिर में हुए आतंकी हमले से प्रेरित है। इसे वेब सीरीज नहीं, बल्कि फिल्म का रूप दिया गया है। कहानी शुरू होती है जम्मू-कश्मीर में चल रहे एक मिशन के साथ, जहां मेजर हनुत सिंह (अक्षय खन्ना) अपनी टीम के साथ एक बंधक महिला को आतंकियों से बचाते हैं। उनके सीनियर कैप्टन नागर (प्रवीन डब्बास) उन्हें बाकी की टीम के आने तक इंतजार करने का निर्देश देते हैं, लेकिन मेजर सिंह आदेश न मानते हुए आतंकियों के बीच पहुंचकर बंधक महिला को छुड़ा लेते हैं। इस मिशन में उनके जूनियर कैप्टन विवेक (अक्षय ओबेराय) शहीद हो जाते हैं। मेजर सिंह का आत्मविश्वास इस हादसे के बाद कम हो जाता है। उन्हें दोबारा एक मिशन पर जाने का मौका मिलता है। गुजरात के मुख्यमंत्री मनीष चोकसी (समीर सोनी) राज्य शाइनिंग पर एक बिजनेस इवेंट करने वाले होते हैं। वहां आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) टीम को उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है, लेकिन आतंकी हमला गांधीनगर के कृष्णधाम मंदिर में हो जाता है। एनएसजी टीम से मेजर सिंह को उनकी टीम के साथ मंदिर भेजा जाता है। आतंकी मंदिर में बंधकों को छोड़ने के बदले भारत की जेल में कैद बिलाल नायकु (मीर सरवार) की रिहाई मांगते हैं। यहां से शुरू होता है आतंकियों से एनएसजी का मुकाबला। फिल्म में अक्षरधाम मंदिर का नाम बदलकर कृष्णधाम कर दिया गया, जबकि हमले की तारीख और साल को एक ही रखा गया है। चूंकि फिल्म वास्तविक घटना से प्रेरित है, ऐसे में अंजाम क्या होगा, उसका अंदाजा पहले से हो जाता है। लेकिन जो बात इस फिल्म में अखरती है, वह है एनएसजी की टीम की फिल्म में लगभग एक घंटे बाद एंट्री। शुरुआत में मिशन को देखकर लगता है, आगे बहुत ही रोमांचक मोड़ आएंगे, लेकिन एनएसजी के अगले आपरेशन के लिए लगभग एक घंटे का इंतजार करना पड़ता है। उसके बीच के कई प्रसंग उबाऊ लगते हैं। अक्षय खन्ना के अभिनय में कमियां नहीं निकाली जा सकतीं, लेकिन किरदारों को विकसित करने में लेखक चूके हैं। मेजर सिंह अपने सीनियर की बात क्यों नहीं मानते, विवेक दहिया का किरदार इतनी जल्दी किसी को जज कैसे कर लेता है, मेजर समर के परिवार को दिखाने का क्या तुक बनता है, जब मेजर सिंह के ही परिवार पर फोकस नहीं किया गया? ऐसे कई सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। फिल्म का डायलाग, 'घृणा का उत्तर प्रेम ही है। हिंसा का उत्तर अहिंसा। पूरे विश्व को यह समझना होगा कि हिंसा हजार प्रश्नों को जन्म दे सकती है, पर किसी भी एक प्रश्न का उत्तर नहीं बन सकती है...' सोचने पर मजबूर करता है।

प्रियंका सिंह

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम



मंगल की नई तस्वीर...

चीन की अंतरिक्ष एजेंसी सीएनएसए ने जुरोंग रोवर द्वारा ली गई मंगल ग्रह की ताजा तस्वीर जारी की है। इसमें मंगल की सतह दिख रही है। यह रोवर तमाम अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है जो वहां जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहा है। एएफपी

अब तक बच्चों के लिए कम खतरनाक रहा है कोरोना

अनुसंधान

लंदन : कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में भारी तबाही मचाई है और इससे 40 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। लेकिन एक नवीनतम अध्ययन में सुकून देने वाले नतीजे सामने आए हैं। कोरोना वायरस बच्चों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा। बच्चों में यह ज्यादा गंभीर रूप नहीं ले रहा और न ही इससे संक्रमित होने के बाद ज्यादातर बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ रही है। संक्रमण के चलते बच्चों में मौत का प्रतिशत भी बहुत कम है। यूनिवर्सिटी कालेज लंदन के विज्ञानियों के नेतृत्व में हुए अध्ययन में यह भी देखने को मिला की कई पुरानी बीमारियों और न्यूरो-विकलांगता से ग्रस्त बच्चों को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरा है। यह अध्ययन करने वाली टीम में यूनिवर्सिटी आफ यार्क, यूनिवर्सिटी आफ ब्रिस्टल और यूनिवर्सिटी आफ लिवरपूल के विज्ञानी भी शामिल थे।



आशंका के बीच अच्छी खबर। फाइल फोटो

अध्ययन करने वाली टीम ने इंग्लैंड के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के आकलन में पाया कि कोरोना वायरस के चलते जितने युवाओं की मौत हुई, उनमें से 15 कई पुरानी बीमारियों से ग्रस्त थे, इनमें से 13 को गंभीर न्यूरो विकलांगता की समस्या थी। जबकि, छह को पिछले पांच साल के दौरान कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई थी। इसके अलावा 36 बच्चों की जब मौत हुई तब वो कोरोना से संक्रमित थे, लेकिन उनकी मौत का कारण कुछ और ही था। मृतकों में ज्यादातर 10 साल से ज्यादा उम्र के और श्वेत या एशिया मूल के थे। अध्ययन दल के अगुआ प्रो. रसेल विनर का कहना है कि बच्चों का टीकाकरण के बारे में फैसला करने से पहले विस्तृत शोध की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अध्ययन में एक बात यह सामने आई कि बच्चों में कुछ वर्ग समूह ऐसे हैं जिनका टीकाकरण जरूरी है। हालांकि, कोरोना से इस समूह के सदस्यों को भी मौत और गंभीर संक्रमण का खतरा कम है। (आइएएनएस)

स्क्रीन शॉट

मैं इंटरनेट मीडिया के कमेंट्स पढ़ती ही नहीं : विद्या बालन



विद्या ने दिए निगेटिव कमेंट्स से दूर रहने के टिप्स। इंटरनेट

इंटरनेट मीडिया यूं तो बड़े काम की चीज है, लेकिन कई बार यह नकारात्मक तब हो जाती है, जब ट्रोलर्स सितारों को बेवजह परेशान करने लग जाते हैं। सर्वविदित है कि सितारों की एक पोस्ट पर ढेरों कमेंट्स आते हैं। निगेटिव कमेंट्स यकीनन दुख पहुंचाते हैं, लेकिन विद्या बालन ने इस तरह के कमेंट्स का सामना करने का एक आसान तरीका निकाल लिया है। दैनिक जागरण से बातचीत में विद्या ने कहा कि इंटरनेट मीडिया की निगेटिविटी से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी आपकी तस्वीरों पर कमेंट कर रहा है, उसे पढ़े ही नहीं। मैं तो यही करती हूं। कमेंट्स नहीं पढ़ती हूं, इससे यह जानने का मौका ही नहीं मिलता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं अपने बारे में जानती हूं। ऐसे में दूसरों के कमेंट्स पढ़कर क्या फायदा। आगे विद्या ने कहा कि मैं अपने करियर को लेकर बहुत स्पष्ट हूं। लोग कहते हैं कि महिला केंद्रित किरदार ही करती हूं। हालांकि मैंने ऐसा करने की कभी कोशिश नहीं की है, लेकिन अगर जाने-अनजाने मैं महिला प्रधान फिल्में कर रही हूं, तो मैं इसे एक बोनस की तरह देखती हूं। मैं ऐसी कहानियां चुन रही हूं, जो देखने के लिए आकर्षित करती हैं। जब तक फिल्म की हीरो मैं हूं, तब तक महिला केंद्रित फिल्में करने में बुराई क्या है।

अनुपमा में काम करने से रोनित राय का इन्कार, अभी कोई टीवी शो नहीं कर रहे

बीते दिनों आई खबरों में कहा गया था कि स्टार प्लस के शो अनुपमा में रोनित राय की एंट्री होने वाली है। वह अनुपमा के बचपन के दोस्त की भूमिका में नजर आएंगे, जो उन्हें बेहतर तरीके से समझता है। रोनित ने ट्विटर पर इस खबर को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वह फिलहाल कोई टीवी शो नहीं कर रहे हैं। अगर वह कुछ करेंगे तो खुद ही सूचित करेंगे। वहीं शो से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस शो के लिए अरशद वारसी से भी संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने भी इन्कार कर दिया। बताया जाता है कि उन्होंने फीस अधिक मांगी है। वहीं राम कपूर और शरद केलकर को भी इस किरदार का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने भी इन्कार कर दिया। फिलहाल वह डिजिटल प्लेटफार्म के प्रोजेक्ट्स में सक्रिय हैं। वह वेब सीरीज ही करना चाहते हैं। बताया जाता है कि शो में यह एंट्री 30 अगस्त को होगी। यह विदेशी बिजनेसमैन का किरदार होगा। उसके लिए निर्माता किसी नामी चेहरे को कास्ट करना चाहते हैं। उल्लेखनीय है अनुपमा शो में अनुपमा (रुपाली गांगुली) अपने पति वनराज (सुधांशु पांडेय) से अलग हो चुकी है। वनराज की काव्या (मदालसा शर्मा) से शादी हो चुकी है। अनुपमा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में शो में आगे कई रोचक ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे।



अभी फिल्मों, वेब शो में काम कर रहे हैं रोनित। इंस्टाग्राम

साक्षी तंवर की बेटी का किरदार निभाने में काफी कुछ सीखने को मिला : वामिका

क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार लगातार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं। ग्रहण शो से तारीफें बटोरने वाली पंजाबी फिल्मों की अभिनेत्री वामिका गब्बी भी हिंदी इंडस्ट्री में अपने पैर जमा रही हैं। उनकी आगामी वेब सीरीज नेटफ्लिक्स के लिए होगी, जिसका नाम माई है। इस शो में वामिका साक्षी तंवर की बेटी का किरदार निभा रही हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में वामिका ने कहा कि मेरे सिर्फ चार-पांच दिनों की शूटिंग बची है। मैं शो में साक्षी तंवर की बेटी का किरदार निभा रही हूं। मुझे उनसे काफी सीखने का मौका मिला। अच्छे कलाकार सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं, उनके साथ बात करके अंदर कुछ महसूस होता है। उनको देखकर सीखा कि दिल में प्यार रखना कितना जरूरी है। माई में एक सीन है, जिसे करने के बाद एक जादुई अनुभव हुआ था। मैं बिल्कुल उनकी बेटी बन गई थी, उस सीन में। मुझे लगा जैसे मेरी मां मेरे सामने खड़ी हैं। उन्होंने मुझे अपना महसूस कराया। मैंने इस शो से पहले उन्हें एक जगह देखा था। उन्होंने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी। बाल खुले थे। मेरी नजरें उन पर से नहीं हट रही थीं। उसके कुछ महीने बाद उन्हीं के साथ काम किया। मैंने उन्हें माई के सेट पर यह बात बताई कि मुझे उन पर क्रश हो गया था। इस किरदार को मैंने ऑडिशन के जरिये पाया था।



वेब सीरीज ग्रहण में नजर आई हैं वामिका। इंस्टाग्राम

नूतन से कभी झगड़ा नहीं हुआ था : तनुजा

डांस रियलिटी शो सुपर डांसर - चैप्टर 4 में इस बार गुजरे जमाने की अभिनेत्री तनुजा बतौर अतिथि नजर आएंगी। लिहाजा प्रतिभागियों ने तनुजा के सुपर हिट गानों पर परफॉर्म किया है। प्रतिभागी अनीश टाटीकोटा और उनके गुरु आकाश शेट्टी ने तनुजा के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक, फिल्म 'मेरे जीवन साथी' के 'चला जाता हूं' पर जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर मंच पर मौजूद सभी को चौंका दिया। तनुजा अनीश की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस से काफी हैरान थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अनीश इतनी कम उम्र में एक अनुभवी व्यक्ति की तरह परफॉर्मेंस देते हैं। शो से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अनीश और आकाश की परफॉर्मेंस के बाद, अनीश की मां ने तनुजा से उनकी बहन और अभिनेत्री नूतन के साथ अपने संबंधों के बारे में बताने का अनुरोध किया। इस पर तनुजा ने कहा, 'नूतन जी मुझसे साढ़े सात साल बड़ी थीं, इसलिए हमारा कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ क्योंकि वह मेरे लिए मां जैसी थीं और परिवार में छोटी बच्ची होने के कारण मैं सबकी लाडली थी।' भाई-बहन के रिश्ते के बारे में बात करते हुए, तनुजा ने एक किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे नूतन जी ने फिल्म हमारी बेटी में उन्हें सबक सिखाने के लिए 12 केले खिलाए, यह जानने के बाद भी कि उन्हें केले खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इस फिल्म में वह बाल कलाकार की भूमिका में थीं। तनुजा ने कहा, 'हम लड़ते हैं, हम बहस करते हैं, लेकिन हम एक-दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं, सभी भाई-बहन इस कहानी से रीलेट कर सकते हैं। मेरी बेटियां काजोल और तनीषा का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। वो दोनों दिन भर बहस करती रहती हैं और मुझे बीच में आने से मना कर देती हैं। उनका मानना है कि वे अपनी समस्या खुद सुलझा सकती हैं।' इस एपिसोड का प्रसारण शनिवार को सोनी चैनल पर रात आठ बजे होगा।



सोनी चैनल पर सुपर डांसर - चैप्टर 4 में दिखेंगी तनुजा। सौ. सोनी चैनल

मैंने अपनी दोनों गर्भावस्थाओं के दौरान शारीरिक और भावनात्मक रूप से जो अनुभव किया, उसका व्यक्तिगत लेखा-जोखा यह किताब है। कई मायनों में यह किताब मेरे तीसरे बच्चे की तरह है। इसे देश के स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञों के आधिकारिक निकाय ने अनुमोदित किया है।

करीना कपूर ने लांच की अपनी किताब प्रेग्नेंसी बाइबल

पिछले साल अपने बड़े बेटे तैमूर के चौथे जन्मदिन पर करीना कपूर खान ने अपनी किताब प्रेग्नेंसी बाइबल का फर्स्ट लुक इंस्टाग्राम पर साझा किया था, जिसमें उन्होंने अपने मां बनने के अनुभवों को साझा करने की बात कही थी। शुक्रवार को उन्होंने अपनी किताब लांच की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया। इसमें किचन में वह पूछती हैं कि क्या पक रहा है? फिर वह माइक्रोवेव से अपनी किताब निकालती हैं और कहती हैं कि यह पक रहा था। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में अपनी किताब लिखने की प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि मेरी गर्भावस्था और प्रेग्नेंसी बाइबिल लिखना यात्रा रही है। मेरे साथ अच्छे और बुरे दोनों दिन थे। कुछ दिन मैं काम पर जाने के लिए उत्सुक थी और वहीं कुछ दिन मैं बिस्तर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। मैंने अपनी दोनों गर्भावस्थाओं के दौरान शारीरिक और भावनात्मक रूप से जो अनुभव किया, उसका व्यक्तिगत लेखा-जोखा यह किताब है। कई मायनों में यह किताब मेरे तीसरे बच्चे की तरह है। मुझे यह साझा करते हुए गर्व हो रहा है कि मेरी प्रेग्नेंसी बाइबिल को भारत के स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञों के आधिकारिक निकाय (एफओजीएसआइ) द्वारा सत्यापित और अनुमोदित किया गया है। किताब के प्रीआर्डर का लिंक भी साझा किया। करीना ने इस साल अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया था। वहीं फिल्मों की बात करें तो वह आमिर खान के साथ लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगी।



किताब को करीना कपूर खान ने अपना तीसरा बच्चा बताया ● इंस्टाग्राम

तेलुगु फिल्म हिट की रीमेक में दिखेंगी सान्या मल्होत्रा



रीमेक में काम करने को बेकरार सान्या ● इंस्टाग्राम

साउथ फिल्मों की हिंदी रीमेक में अब तेलुगु हिट फिल्म हिट का नाम भी जुड़ गया है। हिट फिल्म पिछले साल रिलीज हुई थी। हिंदी रीमेक में राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा को कास्ट किया गया है। टी सीरीज और दिल राजू प्रोडक्शन तले बनने वाली इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर काम चल रहा है। इस फिल्म में काम करने को लेकर उत्साहित सान्या मल्होत्रा ने कहा कि मैंने हिट फिल्म देखी है और मुझे फिल्म का कांसेप्ट पसंद आया है। जब मुझे फिल्म का प्रस्ताव मिला तो मैंने तुरंत स्वीकृति दे दी। मैं राजकुमार के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हूं। हिट की कहानी एक पुलिस अधिकारी की है, जो एक लापता महिला की खोज में लगा है। इस फिल्म का निर्देशन डॉ. शैलेश कोलानु करेंगे जिन्होंने मूल फिल्म का निर्देशन किया था। मूल फिल्म में विश्व सेन और रूहानी शर्मा प्रमुख भूमिका में थे। हिंदी रीमेक में राजकुमार राव पुलिस कर्मी की भूमिका में नजर आएंगे। राजकुमार और सान्या मल्होत्रा ने इससे पहले अनुराग बसु निर्देशित फिल्म लूडो में एकसाथ काम किया था। हालांकि उसमें दोनों एकदूसरे के अपोजिट नहीं थे।

स्टार पावर तक सीमित नहीं रह गया है अभिनय : मणिरत्नम

डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़े फिल्ममेकर्स को भी आकर्षित कर रहा है। बात करें अगर गुरु, साथिया, रावण जैसी फिल्मों के निर्देशक मणिरत्नम की तो उनके मुताबिक पिछले साल से जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, वह इस क्षेत्र में अनुशासन को बढ़ाएगा। एक इंटरव्यू के दौरान मणिरत्नम ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहानियां कहने, एंथोलॉजी फिल्म (चार से पांच लघु कहानियां) बनाने की आजादी है। लंबी कहानियों को सीजन में बांटकर कई सीजन्स लाए जा रहे हैं। उन फिल्मों को जगह मिल रही है, जिन्हें थिएटर और ओपन मार्केट में रिलीज होने में दिक्कतें आ रही थी। फिल्में अपने दर्शक खुद ढूंढ ले रही हैं। जिस तरह की फिल्में बन रही है, उसमें बदलाव आएगा। फिल्म इंडस्ट्री में एक अनुशासन आना बाकी है, जो जल्द ही इस प्लेटफॉर्म की वजह से आएगा। अब ऐसा नहीं रहा कि बड़े स्केल की फिल्में सिर्फ थिएटर में ही आएंगी। डिजिटल भी बड़े स्केल पर कंटेंट ला रहा है। हालांकि मैं अगर दर्शक की तरह सोचूं तो मैं खुद फिल्म थिएटर में देखना चाहूंगा, लेकिन जिस तरह के कंटेंट अब देखे जा रहे हैं, वक्त के साथ दर्शकों की उम्मीदें बढ़ती जा रही है। दर्शकों की सोच भी बदल रही है, जब तक लोग इस न्यू नॉर्मल को अपना नहीं लेते, तब तक वह बदलाव चाहेंगे। जहां तक बात है स्टार पावर की वह अब कुछ कलाकारों तक सीमित नहीं रह गया है। अच्छे एक्टर्स के लिए अच्छा वक्त है।



मणिरत्नम का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म लाएगा अनुशासन ● इंस्टाग्राम

इस दौर में स्टंट करना चुनौतीपूर्ण था : रोहित

एडवेंचर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 की मेजबानी इस बार भी फिल्ममेकर रोहित शेट्टी कर रहे हैं। शो की शूटिंग दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन में की गई है। गुरुवार को इस शो की प्रेस कांफ्रेंस के दौरान शो के प्रतिभागी दिव्यांका त्रिपाठी, राहुल वैद्य, निक्की तंबोली, श्वेता तिवारी, आस्था गिल, महक चहल आदि मौजूद रहे। कोरोना काल में शो की शूटिंग को लेकर रोहित ने कहा कि इस दौर में स्टंट करना प्रतिभागियों के लिए काफी चैलेंजिंग था। पहले तो सब डर गए थे। मुझे लगता है कि यह शो ही ऐसी चीजें करने के बारे में हैं जो आपको डराती हैं। ये सभी अभिनेता हैं, स्टंटमैन नहीं। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी थी। साथ ही, इस बार हमें कोरोना वायरस के कारण अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी और इसके बीच स्टंट करना चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने कहा, दिव्यांका त्रिपाठी ने मुझे चौंका दिया। मैं आमतौर पर जानता हूं कि कौन सा प्रतियोगी टास्क के दौरान चिंतित या भयभीत है, लेकिन वह निडर हैं। विशाल काफी साहसी हैं। अर्जुन बिजलानी ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। इस शो का प्रसारण 17 जुलाई से कलर्स चैनल पर होगा। रोहित की फिल्म सूर्यवंशी भी पिछले एक साल से रिलीज का इंतजार कर रही है। वह पहले ही कह चुके हैं कि इस फिल्म को थिएटर में ही रिलीज करेंगे।



खतरों के खिलाड़ी की मेजबानी कर रहे हैं रोहित शेट्टी ● पीआर टीम

This PDF was originally uploaded To The English Newspaper L-- Banna SA (https://t.me/English_Newspaper_L_Banna)one else Backup chennal @NEWS_Backup_L_Banna